



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]
No. 334]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2001/अग्रहायण 27, 1923
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2001/AGRAHAYANA 27, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2001

विषय : पोलैण्ड और यूरोपीय संघ क्षेत्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाई स्टाइरिन बुटाडिन कोपोलीमर/आई स्टाइरिन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच

सं. 22/1/2000-डीजीएडी.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए :—

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त नियमों के तहत मै. अपार इंडस्ट्रीज लि. और मै. एपकोटैक्स लैटिक्स लि. (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता कहा जाएगा) जिनके पंजीकृत कार्यालय क्रमशः अपार हाऊस, कारपोरेट पार्क, सियोन-ट्राम्बे रोड, चैम्बूर, मुम्बई-400021 तथा 49—53, महावीर सेंटर, प्लॉट नं. 77, सैक्टर-17, वशी, नवी मुम्बई-400073 हैं, घरेलू उद्योग की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पोलैण्ड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र (इसके बाद इन्हें संबद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से

निर्यातित हाई-स्टाईरिन बुटाडिन कोपोलिमर/हाई स्टार्डिन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तुएं कहा जाएगा) के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

- (ii) याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए आवेदन की प्रारंभिक जांच से कतिपय त्रुटियों का पता चला जिन्हें बाद में याचिकाकर्ता ने दूर कर दिया । इसलिए इसे समुचित दस्तावेजयुक्त याचिका माना गया है ।
- (iii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लिया कि पोलैंड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू की जाए । प्राधिकारी ने उक्त नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरूआत की कार्यवाही से पहले नई दिल्ली में पोलैंड के दूतावास तथा यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधिमंडल (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देशों के दूतावास कहा जाएगा) को भी पाटन के आरोपों के संबंध में सूचित किया ।
- (iv) प्राधिकारी ने दिनांक 20.12.2000 का एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा पोलैंड तथा यूरोपीय संघ क्षेत्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं, जिन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची के सीमाशुल्क कोड 4002.1902 के तहत वर्गीकृत किया गया है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू की गयी ।
- (v) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच निष्कर्षों को 13.3.2001 को अधिसूचित किया और ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक जांच निष्कर्षों की एक प्रति भेजी, जिनसे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

- (vi) प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावास को भी इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने-अपने विचार उपर्युक्त (v) में दी गयी समय-सीमा के भीतर भेजने की सलाह दी जाए ।
- (vii) प्राधिकारी न सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग/उपयोक्ता संघों को भेजी और उन्हें नियम 6(2), 6(3) और 6(4) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।
- (viii) प्राधिकारी न हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार 9.5.2001 को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज कराने का अनुरोध भी किया गया था । पार्टियों का प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और उसका खंडन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी थी ।
- (ix) प्राधिकारी न नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पार्टियों को विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों के अगापनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल उनके अनुरोध पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवायी थी । कुछ हितबद्ध पार्टियों के अनुरोध पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता से अतिरिक्त सूचना जिस सीमा तक आवश्यक थी, संभव थी तथा नियमों के अंतर्गत अनुमत थी, उन्हें उपलब्ध करायी गयी ।
- (x) कन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) से जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ।

- (xi) निम्नलिखित हितबद्ध पार्टियो द्वारा प्रारंभिक जांच निष्कर्षों/प्रकटन विवरण उत्तर/सूचना दी गयी:-

घरेलू उद्योग

- (i) मै० अपार इंडस्ट्रीज लि०
(ii) मै० एपकोटैक्स लैटिटसिस लि०

निर्यातक

- (i) मै० फर्मा कैमिक्जिना डोरी एस ए, पोलैंड
(ii) मै० बॉयर इंटरनेशनल एस ए, स्विटजरलैंड
(iii) मै० एनीकैम एस पी ए, इटली

आयातक/उपयोक्ता संघ

- (i) मै० ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुट वियर मैन्यूफैक्चरर्स, नई दिल्ली
(ii) मै० ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मुम्बई
(iii) मै० न्यू इंडिया रबड़ वर्क्स प्रा० लि०, कलकत्ता
(iv) मै० वाणिक रबड़ इंडस्ट्रीज, कलकत्ता
(v) मै० पैरागोन रबड़
(vi) मै० पैरागोन पोलिमर्स
(vii) मै० मलाया इम्पैक्स
(viii) मै० स्मॉल स्कल रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
(ix) मै० ऋषिरूप पोलिमर्स प्रा० लि०
(x) मै० लिआ रबर्स

- (xii) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों, जिन्हें पहले अधिसूचित किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है, को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है। परन्तु हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और/या इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है।
- (xiii) सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए पी पी) के आधार पर तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गयी लागत संबंधी सूचना के विश्लेषण के आधार पर संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और भारत में माल को बनाने और बेचने की लागत का हिसाब लगाया गया।
- (xiv) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना को, जितना जरूरी था, उस सीमा तक सत्यापन किया और पोलैंड के एक निर्यातक मै0 फर्मा कैमिक्जना डोरी तथा द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की मौके पर जांच की।
- (xv) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष 22.11.2001 को प्रकट किया गया।
- (xvi) इस अधिसूचना में xxx चिह्न से हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गयी सूचना प्रदर्शित होती है और नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी ने इस गोपनीय ही माना है।
- (xvii) जांच की अवधि 1.1.2000 से 30.9.2000 तक मानी गयी है।

ख. घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपयोक्ता संघों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों में तथा प्रकटन विवरण पत्र में भी विचार किया गया है। जिन विचारों पर प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रकटन विवरण-पत्र में

पहले विचार नहीं किया गया है और जो अब प्रकटन विवरण-पत्र के जवाब में उठाए गए हैं, उन पर नियमों के अनुसार संगत सीमा तक और जहां तक ये इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, नीचे संगत पैराग्राफों में विचार किया गया है। कुछेक हितबद्ध पार्टियों द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा दिए गए तर्कों को प्रकटन विवरण में हिसाब में नहीं लिया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों की, जहां तक वे नियमानुसार संगत हैं, और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं, जांच की है और उन पर इन जांच परिणामों में समुचित विचार किया है। हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गयी, उन पर विचार किया गया और जहां उचित समझा गया, उन पर नीचे संगत पैराग्राफों में कार्रवाई की गयी है।

ग. 1 विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

(क) मै0 अपार इंडस्ट्रीज लिमि. तथा मै0 एफ्कोटेक्स लेटिसिज लिमि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

(i) इस जाच में शामिल उत्पाद हाई-स्टाईरिन बुटाडिन कोपोलिमर है। सामान्यतया इस एच एस आर या हाई स्टाईरिन रेजिन/रबड़ के नाम से जाना जाता है। इन अनुरोधों में इनका उल्लेख एच आर एस के रूप में किया गया है। एच आर एस विभिन्न ग्रडों में हो सकता है और इसकी आपूर्ति विभिन्न रूपों में की जा सकती है। वर्तमान जाच पोलैंड तथा यूरोपीय संघ (ई यू) से आयातित एच एस आर के सभी ग्रडों तथा रूपों के विरुद्ध है। एच एस आर का विनिर्माण केवल स्टाईरिन बुटाडिन रबड़ के उत्पादकों द्वारा ही किया जाता है और इसका उपयोग रबड़ उद्योग द्वारा किया जाता है। एच एस आर का उप-विभाजन दो श्रेणियों में किया जा सकता है:-

(क) एस बी आर 1900 श्रृंखला इमलशन रेजिन रबड़ मास्टर बैच को हाई स्टाईरिन रेजिन मास्टर बैच भी कहा जाता है

(ख) हाई स्टाईरिन रिडिफाईड पॉलिमर्स (एच एस बी आर)

एस बी आर 1900 श्रृंखला दो लटेक्सो का मिश्रण या मास्टर बैच है। एच एस बी आर एक ऐसा उत्पाद है जो बुटाडिन के साथ उच्च स्तर के स्टाइरिन के प्रत्यक्ष पोलिमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद अध्याय 39 और 40 के तहत आयात किया जाता है। अध्याय 39 और 40 के तहत आयातित वस्तुओं के बीच अंतर केवल उनमें स्टाइरिन की मात्रा की प्रतिशतता का अंतर है जिसके कारण उत्पाद का भिन्न नहीं कहा जा सकता है और इस उत्पाद के एक समान तकनीकी तथा वाणिज्यिक प्रयोग हैं।

- (ii) विरोधी पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने इस जांच में उत्पाद की परिभाषा पिछली जांच से अलग ही की है। इन पार्टियों ने यह औचित्य दर्शाने का प्रयास किया है कि अध्याय 39 और 40 के तहत आने वाले उत्पाद भिन्न हैं। यदि इसे दूसरे ढंग से लिया जाए तो इन पार्टियों ने तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद दो सीमाशुल्क अध्यायों के तहत नहीं आ सकता है। यह अनुरोध किया जाता है कि इस आशय के सभी तर्क निराधार हैं और उस प्रयोजन के लिए व्यर्थ हैं जिस प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है।
- (iii) प्रारंभ में यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता ऐसे उत्पाद की जांच की मांग और उस पर पाटनरोधी शुल्क की मांग करने के हकदार हैं जो भारत में आयात किया गया है और जिसकी समान वस्तु देश में उत्पादित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जांच के कार्यक्षेत्र का निर्णय करते समय समान वस्तु के मुद्दे को ध्यान में रखा जाता है। यदि समान वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है तो सारी कार्रवाई व्यर्थ हो जाएगी। इस बारे में ओक्सो अल्कोहल्स से संबंधित मामले में सीगेट के आर्डर का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार है:-

"निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे है कि सामान्य हैक्सानोल की विशेषताएँ जांचाधीन अन्य वस्तुओं से बिल्कुल मिलती-जुलती हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि सामान्य हैक्सानोल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पाद अन्य ओक्सो एल्कोहल्स द्वारा विनिर्मित उत्पादों के प्रतिस्थापित कर सकता है" (बल दिया गया है)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी उत्पाद की ऐसी किसी भी किस्म को, जो आयातित वस्तु की समान वस्तु है, मौजूदा जांच के कार्य क्षेत्र में शामिल करना होगा।

- (iv) सीमाशुल्क वर्गीकरण का प्रयोजन उत्पाद का समझने में सहायता करना है। इस बारे में नियम 12 (ii) और 17(2) (ii) में निम्नानुसार दिया गया है:-

"वस्तु का एक ऐसा विवरण जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए पर्याप्त है"

अतः वस्तु का विवरण सीमाशुल्क को समझने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त होना चाहिए। वस्तु का विवरण सीमाशुल्क वर्गीकरण के कार्यक्षेत्र को शासित करता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण उत्पाद के कार्यक्षेत्र को शासित नहीं कर सकता है।

- (v) निर्दिष्ट प्राधिकारी की शुल्कों से संबंधित नियम 4 (i) ख में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क के लिए पात्र वस्तु का पता लगाना निर्दिष्ट प्राधिकारी का कर्तव्य होगा। इस प्रकार सीमाशुल्क वर्गीकरण का मुद्दा निर्दिष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है।
- (vi) अध्याय 39 और 40 के अंतर्गत आने वाली वस्तु को शामिल करने अथवा अन्यथा हेतु वास्तविक जांच समान वस्तु के परीक्षण में निहित होती है। इस संबंध में अनुरोध है कि पोलिश उत्पादक (और संभवतः यूरोपीय संघ के उत्पादक) भिन्न भिन्न ग्रेडों के एच एस आर का उत्पादन करते हैं। (यद्यपि पोलिश उत्पादक द्वारा यह सूचना छिपाई गई है। कंपनी द्वारा उत्पादित ग्रेडों में के ई आर 1904, के ई आर 1909 और के ई आर 9000 शामिल हैं। पोलिश उत्पादन के साहित्य के अनुसार ये समस्त ग्रेड हाइस्टरीन रबड़ (एच एस आर) के अंतर्गत आते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वह खुलासा करने के लिए निर्यातक को निर्देश दें और यह जांच करें कि क्या सीमाशुल्क वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ इनमें से किसी का निर्धारण अध्याय 39 के अधीन किया जाएगा। इसके अलावा हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह इस बात की जांच करे कि क्या तीनों ग्रेडों समान वस्तुएं हैं हमारा अनुरोध है कि ए तीनों ग्रेड भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं उत्पादन प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वस्तु का वितरण एवं विपणन जैसी विशिष्टताओं के संबंध में समान वस्तुएं हैं। ये ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। हमारा अनुरोध है कि ये ग्रेड इन विशेषताओं के अनुसार समान वस्तुएं हैं।
- (vii) यह आवश्यक नहीं है कि जांच के क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए निर्यातक को उत्पाद के सभी ग्रेडों/स्वरूपों का निर्यात करना चाहिए। उत्पाद के अनिवार्यतः ऐसे अनेक प्रकार होंगे जिनकी जांच अवधि में निर्यात नहीं किया गया होगा तथापि जहां तक ये प्रकार शामिल उत्पाद के समान वस्तु हैं वहां तक इन्हें जांच के क्षेत्र में रखना अपेक्षित है।
- (viii) यह बताना तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना होगा कि पूर्ववर्ती जांच का एवं एच एस आर से कोई संबंध नहीं था। पूर्ववर्ती जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणाम इस संबंध में पूर्णतः सुस्पष्ट है और उनमें इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एस बी आर 1900 सीरीज पूर्ववर्ती जांच में जांच के क्षेत्र में थी।

- (ix) इस बात की परिकल्पना करते हुए यद्यपि स्वीकार न करते हुए कि पूर्ववर्ती जांच में शामिल उत्पाद में एच एस आर के अन्य प्रकार शामिल नहीं थे, इससे याचिकाकर्ता इन प्रकारों को वर्तमान जांच के दायरे में लाने से किसी भी हालत में वंचित नहीं हो जाता है। इस बात की परिकल्पना करते हुए यद्यपि स्वीकार न करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने पूर्ववर्ती मामले में शामिल उत्पाद पर पूरा ध्यान नहीं दिया था, इसका अर्थ यह नहीं निकलता है कि याचिकाकर्ता इस मामले में उसी का अनुपालन करेंगे। दोनों जांच विशिष्ट और अलग अलग जांच हैं और पूर्ववर्ती मामले में की गई जांच के क्षेत्र से विरोधी हितबद्ध पार्टियों को इस संबंध में वर्तमान जांच में कोई स्वतन्त्रता नहीं मिल जाती है। हम कोरिया के खिलाफ यूरोपीय संघ द्वारा पोलिस्टर फिल्म के मामले में की गई जांच पर भी विश्वास करते हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद को उसी उत्पाद के लिए उसी देश के खिलाफ बदल दिया गया था।

प्रकटन विवरण पत्र के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं

- (i) हम विचाराधीन उत्पाद से संबंधित अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराते हैं
- (ii) यह नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पाद को स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया है जिसमें पोलिस्टरीन थर्मो प्लास्टिक, इलास्टोमर, एक्रिलोनाइड्रिल बुटाडिन स्टरीन, को-पोलिमर्स और स्टरीन एक्रिलोनाइड्रिल, को पोलिमर्स शामिल नहीं हैं। घरेलू उद्योग को इस प्रकार के किसी स्पष्टीकरण में कोई आपत्ति नहीं है जिसमें अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले अन्य उत्पादों पर शुल्क की संभावित वसूली के बारे में विरोधी हितबद्ध पार्टियों द्वारा बार बार दिए गए तर्क को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्याय 39 के अंतर्गत आयात किए जा रहे किसी भी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की न तो घरेलू उद्योग ने मांग की है और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसे लगाया है। घरेलू उद्योग ने संबंधित वस्तु पर उस स्थिति में शुल्क की मांग की है यदि उसका आयात अध्याय 39 के तहत किया गया है। निश्चित रूप से विरोधी पार्टियों का यह मामला नहीं हो सकता है कि एच एस आर, यदि उसकी निकासी अध्याय 39 के तहत अपेक्षित हो, तो उस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए और मामला घरेलू उद्योग का नहीं है

कि अध्याय 39 के तहत आयातित अन्य उत्पादों पर भी शुल्क लगाया जाना चाहिए जबकि घरेलू उद्योग द्वारा केवल एच एस आर पर शुल्क लगाने की मांग की जा रही है।

- (iii) जहां तक निर्यातकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे एच एस आर (जांच अवधि में जिनका भारत को निर्यात नहीं किया गया है) का संबंध है, यह अनुरोध है कि इन सभी प्रकारों को शुल्क के दायरे में लाना अपेक्षित है क्योंकि संबंधित निर्यातकों द्वारा उत्पादित किए जा रहे एच एस आर के विभिन्न अन्य प्रकार जांच अवधि में भारत को निर्यातित एच एस आर के समान वस्तु है।
- (iv) जहां तक समान वस्तु के मुद्दे का संबंध है, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबंधित देशों से आयात की जा रही वस्तु के समान वस्तु है। हम अपने पूर्ववर्ती अनुरोध पर भरोसा करते हैं।
- (v) अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस तथ्य के बारे में न तो याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध करवाया गया है और न ही प्रारंभिक जांच परिणामों में कोई विश्लेषण किया गया है कि दोनों उत्पाद (अध्याय 39 और 40 के तहत आयातित) समान हैं, तथ्यतः गलत है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करवाए हैं और निम्नलिखित से निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह सूचना उपलब्ध हुई है जिसमें सीमाशुल्क के पत्रों के अनुसार अध्याय 30 और 40 के तहत उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होने का उल्लेख किया गया है; डौरी, पोलैंड के निर्यातक के साहित्य, आई आई एस आर पी के पत्र, जिनमें एस बी आर 1900 सीरीज के बारे में तकनीकी सूचना स्पष्ट की गई है और पी पी आर से सौदेवार आयातों के ब्यौरे से स्पष्टतः यह पता चलता है कि अध्याय 39 और 40 के तहत इन वस्तुओं का आयात अन्य देशों से किया गया है।

(ख) मै0 फर्मा कैमिकजना डौरी एस ए पोलैंड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- (i) लिखित अनुरोध में यह उल्लेख किया गया है कि अध्याय 39 और 40 के तहत आयातित वस्तु के बीच अंतर स्टेरीन तत्व के प्रतिशत का है जिससे उक्त उत्पाद भिन्न नहीं हो जाता है और उक्त उत्पाद के तब भी लगभग समान तकनीकी और वाणिज्यिक अनुप्रयोग बने रहते हैं (इस बात पर जोर दिया गया)। यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आशय का कोई आधार प्रस्तुत

नहीं किया गया है और न ही प्रारंभिक जांच परिणामों में ऐसा कोई स्पष्ट विश्लेषण किया गया है कि दोनों उत्पादों के लगभग समान तकनीकी और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हैं। इस संबंध में यह अनुरोध है कि समान वस्तुओं का निर्धारण सकारात्मक और निश्चयात्मक निष्कर्ष द्वारा करना होता है और न कि केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर।

- (ii) याचिकाकर्ताओं ने विरोधी हितबद्ध पार्टियों के इस तर्क को आगे बढ़ाया है कि पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद दोअलग अलग सीमाशुल्क शीषों के तहत नहीं आ सकता। यह उल्लेखनीय है कि जहां तक इस निर्यातक का संबंध है हमारा अनुरोध है कि हमारे द्वारा इस आशय का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था कि पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद दो अलग अलग सीमाशुल्क शीषों के तहत नहीं आ सकता। याचिकाकर्ताओं ने गलत ढंग से इस प्रकार के वक्तव्य का श्रेय विरोधी पार्टियों को दे दिया है और उसके बाद उन्होंने इसे सही ठहराने की कार्यवाही की है। लिखित अनुरोध में यह तर्क जोरदार ढंग से दिया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ प्रासंगिक नहीं है। मूल अभिकथन यह प्रतीत होता है कि चूंकि याचिका में और उसके बाद जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद में रेजिन और रबड़ दोनों शामिल हैं इसलिए जांच के क्षेत्र के बारे में कोई टिप्पणी अथवा तर्क स्पष्टतः गलत है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने की जरूरत है।

- (iii) इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि हमने कहीं पर भी यह वक्तव्य नहीं दिया है कि विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क वर्गीकरण के दो या उससे अधिक शीषों या उपशीषों के अंतर्गत नहीं आ सकता। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि इस मामले में दो अलग अलग अध्यायों का है न कि दो अलग अलग शीषों का जैसा कि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है इस हम आपसे यह अनुरोध करना चाहेंगे कि हमने इस विषय पर साहित्य की छानबीन की है और हमें ऐसी कोई समानता नहीं मिली है जिसके अनुसार दो अलग अध्यायों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को समान वस्तुएं माना गया हो। हमने भिन्न भिन्न प्रणालियों में ऐसे मामलों के बारे में जानने का प्रयास किया जिनमें विचाराधीन उत्पाद इतना व्यापक हो सकता है जिसे दो पूर्णतः अलग अलग अध्यायों में शामिल किया गया हो लेकिन हम ऐसा कोई संदर्भ पाने में समर्थ नहीं रहे हैं। इस संबंध में

हमने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में एच एस वर्गीकरण की प्रणाली को लाया है जो कि यद्यपि प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है । तथापि, उसका अपना काफी महत्व है । वर्गीकरण की योजना उत्पादों को उनकी भिन्नता के स्तर के अनुसार वर्गीकरण करने के लिए तैयार की जाती है इस प्रकार वर्गीकरण का स्तर जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक उस उत्पाद में भिन्नता होगी । उदाहरणार्थ दो अंकीय स्तर कार्बनिक रसायनों, अर्वरको, प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुओं इत्यादि के लिए होंगे जबकि छः अंकीय स्तर अध्याय शीर्ष के भीतर उत्पाद समूहों के लिए होंगे । इस प्रकार भिन्नता का स्तर स्पष्ट है और माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती । पाटनरोधी जांच के समूचे विधि शास्त्र में संभवतः यह पहला मामला होगा जिसमें दो अलग अलग अध्यायों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को समान वस्तु माना जाएगा ।

- (iv) अपार और एपकोटेक्स दोनों ही केवल हाइस्टरीन रबड़ बनाते हैं जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले "सिंथेटिक रबड़" के रूप में वर्गीकृत है, इसकी पुष्टि उनके तुलन पत्र में दिए गए विवरणों से होती है । वर्ष 1998-99 के अपार के तुलन पत्र के साथ संलग्न निदेशकों की रिपोर्ट और उसी तुल पत्र की अनुसूची 21 की संख्या (i) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जहां अपार ने अपने हाइस्टरीन रबड़ को सिंथेटिक रबड़ के रूप में वर्गीकृत किया है । अपार द्वारा एस बी आर 1900 सीरीज और हाइस्टरीन बुटाडीन मास्टर बैचों का उल्लेख कर प्राधिकारी को भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है । मामले की वस्तु स्थिति यह है कि वे "सिंथेटिक रबड़" बना रहे हैं जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 की अध्याय टिप्पणी संख्या 4 (क) में यथा निर्धारित परिभाषा के अनुरूप है और उनका उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के 39 की अध्याय टिप्पणी (i) की परिभाषा के अनुरूप नहीं है ।
- (v) स्टरीन बुटाडीन कोपोलीमर रेजिन अथवा पोलिमर्स अध्याय शीर्ष 3903.90 के अंतर्गत आते हैं और वे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले स्टरीन बुटाडीन रबड़ के समान नहीं हैं ।
- (vi) कोरिया गणराज्य सहित अनेक देशों से एस बी आर के मामले में पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच के दौरान प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक अंतिम जांच परिणामों में यह निर्णय लिया था कि उत्पाद हाइ

स्टरीन रेजिन" और स्टरीन बुटाडीन कोपोलिमर रेजिन उस स्थिति में विचाराधीन उत्पाद नहीं है जब वही तर्क उक्त कार्रवाई में उसी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए हों। रिलैक्सों रबड़ लि० द्वारा दायर एक अपील में सीगेट में इस मामले की पुष्टि भी की थी। 26.4.2001 के अपने अंतिम आदेश संख्या 164/165-2001-ए में सीगेट ने यह निर्णय दिया था कि उत्पाद "स्टरीन बुटाडीन को पोलीमर रेजिन" का अध्याय शीर्ष 4002 के अंतर्गत आने वाले "स्टरीन कुटाडीन रबड़" से कोई संबंध नहीं है। अतः अनुरोध है कि जहां तक अध्याय 4002 के अंतर्गत आने वाले अपार और एपकोटेक्स दोनों द्वारा उत्पादित उत्पाद स्टरीन बुटाडीन रबड़ का संबंध है विचाराधीन उत्पाद के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं हो सकता और चूंकि वे अध्याय 3903.90 के अंतर्गत आने वाले किसी स्टरीन बुटाडीन कोपोलीमर रेजिन का विनिर्माण नहीं करते हैं इसलिए वे यह दावा नहीं कर सकते कि ऐसे उत्पादों को वर्तमान जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।

- (vii) 23.5.2000 के अपने अनुरोधों के पैरा (i) में याचिकाकर्ताओं ने आक्सों एकोहल से संबंधित पाटनरोधी मामले में सीगेट के हाल ही के एक आदेश का उल्लेख किया है। अनुरोध है कि यह भ्रामक है। उल्लिखित सीगेट के आदेश जो 2001 (130) ई एल टी-58(ट्र-डेल) में प्रकाशित हुआ है, में न्यायाधिकरण में अपने निष्कर्ष के पैरा 9 में स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि "सामान्य हेक्सानोल" घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित अथवा उत्पादित सामान्य हेक्सानोल नहीं है। इस लिए इसके आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती। उत्पाद को "समान वस्तु" मानने के लिए प्राधिकारी को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि ऐसे उत्पादों में खुद व खुद एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती विशेषताएं हैं। वर्तमान मामले में चूंकि यह स्पष्ट और तकनीकी रूप से सुस्पष्ट है कि स्टरीन बुटाडीन कोपोलीमर रेजिन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 की अध्याय टिप्पणी 4(क) में यथा उल्लिखित स्टरीन बुटाडीन रबड़ की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है इसलिए उनमें एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं नहीं हैं। अतः वे समान वस्तुएं नहीं हैं।

- (viii) पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच परिणामों में यह पहले से ही निर्णित मामला है जिसमें प्राधिकारी ने यह माना है कि एस टी आर स्टरीन बुटाडीन कोपोलीमर रेजिन के समान वस्तु अथवा विचाराधीन उत्पाद नहीं है, यह निर्णय को अनिवार्यतः अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले किसी अथवा समस्त

स्टरीन बुटाडीन रबड़ तक सीमित रखा जाना है जो घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादित उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है ।

- (ix) उपरोक्त के होते हुए भी और किसी पूर्वाग्रह के बिना हमारा यह अनुरोध है कि अध्याय 3903.90 के अंतर्गत आने वाले अनेक अन्य स्टरीन बुटाडीन कोपोलीमर रेजिन हैं जिनका रबड़ उद्योग में कमी भी उपयोग नहीं किया जाता है और जो उस स्थिति में पाटनरोधी शुल्क के दायरे में आ जाएगा जब प्राधिकारी यह समझे कि वे एच एस आर के समान वस्तु है उदाहरणार्थ हम निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं-
- (i) स्टाइरोलक्स- वी ए एस एफ जर्मनी द्वारा उत्पादित
 - (ii) के- रेजिन- फिलिप पेट्रोलियम, यू एस ए द्वारा उत्पादित
 - (iii) एसेफलैक्स- असाही कसेई, जापान द्वारा उत्पादित
- (x) उपरोक्त स्टरीन बुटाडीन कोपोलीमर रेजिनों के उदाहरणों में से स्टाइरोलक्स का उत्पादन ई यू में किया जाता है और यदि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ाकर अध्याय शीर्ष संख्या 3903.90 तक करना हो तो उस पर पाटनरोधी शुल्क लग जाएगा । यह उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एच एस आर के समान वस्तु नहीं है और किसी भी स्थिति में इस पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता ।
- (xi) अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच परिणामों में पूर्णतः इन कारणों से कि दोनों उत्पाद दो अलग अलग अध्यायों के अंतर्गत आते हैं विचाराधीन उत्पाद के दायरे से रेजिनों को सोच विचारकर और जानबूझकर अलग रखा था ।
- (xii) कोरिया के खिलाफ यूरोपीय संघ द्वारा पोलिस्टर फिल्म के मामले के संदर्भ में देखना भी रोचक होगा जिसमें विचाराधीन उत्पाद को उसी उत्पाद के लिए उसी देश के विरुद्ध बदल दिया गया था । हमारा अनुरोध है कि पूर्ण संदर्भ के बिना और कम से कम संगत अंशों को संलग्न अथवा उद्धृत किए बिना ऐसे विवरणों को रिकार्ड में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती । किसी भी मामले में हम यह समझते हैं कि उपरोक्त मामले में उत्पाद विवरण को बदला गया था किन्तु प्रत्येक बार जांच की कवरेज अथवा उसके क्षेत्र को कम किया गया था । अतः याचिकाकर्ताओं

द्वारा उल्लिखित मामले से घरेलू उद्योग से अधिक निर्यातकों और उपयोक्ता उद्योग को समर्थन मिलता है ।

(xiii) हम यह भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी जानकारी के अनुसार ई यू द्वारा पी सी एन में आठ अथवा दस अंकीय स्तर पर अथवा उससे उच्च स्तर पर भी भेद किया जाता है और ऐसा ही इस मामले में भी किया गया था इसके विपरीत इस मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दो अंकीय (अध्याय) स्तर पर दोनों उत्पादों को जोड़ने की दलील दी जा रही है । यह अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र अथवा माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्ववर्ती दोनों निर्णयों से मेल नहीं खाता है यह तथ्य हमारे अनुरोध के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना है कि इस मामले में अलग मत व्यक्त करने के लिए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को रोकते हुए पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं से संबंधित अर्द्ध न्यायिक कार्रवाईयों में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक निर्धारण किया गया है ।

(xiv) इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित एस बी आर के मामले में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी का दृष्टिकोण निःसंदेह स्पष्ट है ।

प्राधिकारी यह पाते हैं कि अध्याय 3903.90 के अंतर्गत आने वाली मदे विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं और 1000 सीरीज में एस बी आर का उत्पादन याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है और इस प्रकार ये विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं (इस बात पर जोर दिया गया है) ।

(xv) उपरोक्त मामले में दिए गए निर्णय का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर भी बमुश्किल लागू होता है और उस सीमा तक ये माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी है । दोनों मामलों को जोड़े जाने की व्याख्या याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं अपने लिखित अनुरोधों में किए गए अनुरोधों से बेहतर ढंग से नहीं की जा सकती ।

लिखित अनुरोधों के पैरा 6 में याचिकाकर्ताओं ने निम्नानुसार उल्लेख किया है:-

"यह उल्लेख करना तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना होगा कि पूर्ववर्ती जांच का एच एस आर से कोई संबंध नहीं था ।"

पैरा 7, स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि

“दोनों जांच विशिष्ट और अलग प्रकार की जांच हैं और पूर्ववर्ती मामलों में जांच के दायरे से.....नहीं मिलता है (इस बात पर जोर दिया गया है)।”

(xvi) इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी सुविधानुसार अपने मतों को बदला है। जहां तक विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के मुद्दों का संबंध है वर्तमान जांच या तो घरेलू उद्योग द्वारा या फिर निर्यातकों द्वारा पूर्ववर्ती जांच से अलग जांच के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इस आधार पर भी पूर्वन्याय का सिद्धांत लागू होगा।

(xvii) हमने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इस आशय का एक विशिष्ट तर्क भी दिया था कि यदि सीमाशुल्क वर्गीकरण दो अलग अलग अध्यायों की सीमा तक और न कि केवल शीर्षों और उपशीर्षों तक अलग अलग है तो इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेवारी घरेलू उद्योग पर अधिक रहती है कि दो अलग अलग अध्यायों के अंतर्गत आने वाले उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुएं हैं। दुर्भाग्यवश जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि हमें याचिका और प्रारंभिक जांच परिणामों में इस तथ्य का कोई आधार नहीं मिलता है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न अध्यायों के उत्पादों की “समानता” की परख की गई है वस्तुतः प्रारंभिक जांच परिणामों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या इस प्रकार की कोई जांच लागू की गई थी। विधि सम्मत सिद्धांत यह है कि जो पक्ष अभिकथन देता है उससे साक्ष्य लिया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 को नोट किया जाए।

धारा 101- सिद्ध करने का दायित्व “जो भी व्यक्ति किसी न्यायालय से तथ्यों की मौजूदगी के आधार पर किसी कानूनी अधिकार अथवा दायित्व के बारे में न्याय की अपेक्षा करता है उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि उसके द्वारा बताए गए तथ्य मौजूद हैं —”

(xviii) हमने यह तर्क भी दिया था कि रेजिन को इस आधार पर शामिल किया गया कि अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाली रबड़ की निकासी अध्याय 30 के तहत भी की गई है। हम अब भी यह अनुरोध करते हैं कि जिस वस्तु की निकासी अध्याय 39 के तहत की गई थी वह वस्तुतः रेजिन

है न कि रबड़ यदि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई अलग साक्ष्य न हो। हमारा अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया सीमाशुल्क प्राधिकारियों से इस संबंध में तथ्यों को सुनिश्चित कर लें।

प्रकटन विवरण पत्र के उत्तर में मै. फर्मा कैमेक्जना डौरी एस ए ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

(i) मै. फर्मा ने इन मुद्दों पर उनके द्वारा पहले किए गए अनुरोधों को दोहराया है।

ग) मै0 बेयर इंटरनेशनल एस ए स्विट्जरलैंड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

(i) निर्यातक द्वारा आयातक की ~~खेप~~ की निकासी अध्याय 39 या 40 के अंतर्गत की जाती है लेकिन उसे निर्णायक रूप से केवल आयातक से सुनिश्चित किया जा सकता है। मै0 बेयर इंटरनेशनल ने जांच अवधि के दौरान उत्पादन और भारत को उनके निर्यातों का संकेत भी दिया है।

(घ) मै0 आल इंडिया फेडरेशन आफ रबड़ फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स और मै0 पैरागन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

(i) शुरु में यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिका में यथानिर्दिष्ट जांचाधीन उत्पादों के क्षेत्र को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है और यह औचित्य रहित है। पाटनरोधी जांच संबंधी विधिशास्त्र में यह उल्लेख है कि विचाराधीन उत्पाद हमेशा उत्पादों का अतिअल्प समूह होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को कोई अनुचित संरक्षण नहीं मिलता है। इस मामले में, जैसाकि अगले पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादों को शामिल करने का प्रयास किया है जिन्हें प्रथमतः जांच के दायरे में शामिल किया गया नहीं होना चाहिए।

(ii) यह उल्लेखनीय है कि जापान, कोरिया, तुर्की, ताईवान, यू एस ए, जर्मनी और फ्रांस से एस बी आर के आयात के बारे में पहली जांच में शामिल उत्पाद सीमाशुल्क उपशीर्ष 4002.19 के अंतर्गत वर्गीकृत स्टीरीन बूटाडिन रबड़ था।

- (iii) उक्त विशेष मामले में "घरेलू उद्योग" मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स था जिसने सभी प्रकार के एस बी आर का वेनिर्माण किया था ।
- (iv) एस एस आर (एस बी आर 1900 सीरीज) के इस वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं (मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 और मै0 एफकोटेक्स लैटिसेज लि0) ने हार्ड स्टिरीन बुटाडिन को पोलिमर्स की जांच करने के लिए कहा है । वे यह कह रहे हैं:-

"इसे हार्ड स्टिरीन रेजिन/रबड़(एच एच आर) भी कहा जाता है । एच एस आर में एस बी आर 1900सीरीज और एच एस बी आर शामिल है । एस बी आर 1900सीरीज का उल्लेख हार्ड स्टिरीन रेजिन मास्टर बैच (जिसे इन्सुलसन रेजिन रबड़ मास्टर बैच भी कहा जाता है) के लिए किया जाता है । एच एस बी आर का उल्लेख हार्ड स्टिरीन रिइन्फोर्समेंट पोलिमर्स के लिए किया जाता है । एच एस आर के विभिन्न ग्रेड हो सकते हैं और इनकी आपूर्ति विभिन्न स्वरूपों में की जा सकती है— "

- (v) यह उल्लेखनीय है कि एस बी आर से संबंधित पहले मामले में भी माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने रेजिन को जांच के दायरे से बाहर रखा था । माननीय सीगेट ने 26.4.2001 को इस जांच परिणाम की पुष्टि की थी (अंतिम आदेश सं.164-165/2001ए) । माननीय सीगेट ने 2 जून 1999 के निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम आदेश का उल्लेख किया । खासकर पैराग्राफ 7 को पुनः प्रस्तुत किया गया था ।

"इस साक्ष्य को प्रस्तुत करते समय कि एच एस आर 1900 सीरीज का आयात शीर्ष 39, के अंतर्गत भी किया जा रहा है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि अध्याय 39 के तहत निकासी की गई मद 'इलास्टोमर रेजिन के एस एच 68' है और इस प्रकार यह 'सिंथेटिक रबड़' की नामावली में नहीं आता है ।

स्पष्टतः माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की मंशा केवल सिंथेटिक रबड़ पर शुल्क लगाने की थी । तथापि, जैसाकि याचिका से स्पष्ट होता है, याचिकाकर्ताओं ने बहुत ही चालाकी से जांच के दायरे में न केवल एच एस आर के सभी स्वरूपों (अर्थात् 1500 और 1700 सीरीज) को लाने की मांग की है अपितु

रेजिनो, जिनके बारे में अंतिम रूप से यह निर्णय लिया जा चुका है किये सिंथेटिक रबड़ नहीं हैं, को भी शामिल करने की मांग की है। वे कोपोलिमर्स और रेजिनो का विनिर्माण नहीं करते हैं, जिन्हें शामिल करने की उनके द्वारा मांग की गई है। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता एच एस आर 1900 ग्रेड से इतर किसी अन्य वस्तु का विनिर्माण नहीं करते हैं।

जांचाधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ाकर, याचिकाकर्ताओं ने गुप्त रूप से उन उत्पादों को शामिल करने की मांग की है, जिनका वे विनिर्माण नहीं करते हैं।

(vi) अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद के विवरण में कोपोलिमर्स को शामिल करके, याचिकाकर्ता प्लास्टिक के कुछेक स्वरूपों को शामिल करने की अपेक्षा कर रहे हैं, जो स्पष्ट तौर पर सिंथेटिक रबड़ नहीं हैं। ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चल सके कि सिंथेटिक रबड़ अध्याय 39 के अंतर्गत आ रही है। हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह निवेदन करते हैं कि वह कृपया वित्त मंत्रालय से इस तथ्य की पुष्टि करें कि क्या सीमाशुल्क विभाग द्वारा अध्याय 39 के तहत किसी सिंथेटिक रबड़ की निकासी की गई है। जैसाकि सुनवाई के दौरान माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया गया था कि सिंथेटिक रबड़ के अध्याय 39 के अंतर्गत आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि पश्चातवर्ती उत्पाद में अध्याय 39 और 40 की टिप्पणियों के अनुसार उक्त अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत मर्दे ही आती हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए केवल आरोपों के आधार पर व्यापक रूप से शुल्क लगाए जाने से उपयोक्ता उद्योग पर श्रुतिकारी प्रभावी पड़ सकता है।

(vii) परिणामतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद केवल हाई स्टिरीन रबड़, अर्थात् एस बी आर 1900 सीरीज है, जो अध्याय शीर्ष 4002.19 के अंतर्गत आने वाले 2 लैटेक्सो-स्टिरीन बुटाडिन लेटेक्स और हाई स्टिरीन लैटेक्स के मास्टर बैच का मिश्रण है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किसी अन्य वस्तु का विनिर्माण नहीं किया जाता है और वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आ सकती है।

(viii) अनुरोध है कि कोई अन्य विवरण या शीर्ष जांच के क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। विचाराधीन उत्पाद स्टिरीन बुटाडिन रबड़ 1900 सीरीज अर्थात् एच एस आर है और इस संबंध में माननीय निर्दिष्ट

प्राधिकारी द्वारा एस बी आर के पहले मामले में निर्धारित किए गए सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

- (ix) सुनवाई के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया गया था कि हमें आशंका है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत और प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई सूचना तथ्यतः सही नहीं हो सकती है । हमारा निवेदन है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश पर किसी संभावित स्रोत से इस दावे की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाए कि सिंथेटिक रबड़ की निकासी अध्याय 39 के तहत भी की जा रही है । हमारा अभी भी यह विश्वास है कि सिंथेटिक रबड़ के अध्याय 39 के अंतर्गत आने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि पश्चात्तवर्ती उत्पाद में अध्याय 39 और 40 की टिप्पणियों के अनुसार उक्त अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत मदें ही आती हैं । याचिकाकर्ताओं के केवल आरोपों के आधार पर शुल्क को व्यापक रूप से लगाए जाने से उपयोक्ता उद्योग पर क्षतिकारी प्रभाव पड़ सकता है ।

प्रकटन विवरण पत्र के प्रत्युत्तर में मै0 आल इंडिया फेडरेशन आफ रबड़ मैन्युफैक्चरर्स ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

- (i) हमारे अनुरोधों में दिए गए हमारे तर्कों पर या तो ध्यान नहीं दिया गया है या फिर उनकी अनदेखी की गई है जिसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के बारे में नियम 23 में परिकल्पित समीक्षा के दायरे को गलती से पार कर गए हैं जबकि 2.6.1999 के मूल अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सीमित कर दिया है ।

2. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के बारे में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध व्यापक आधारित है और यह भी कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह उल्लेख किया गया है कि मै0

अपार इंडस्ट्रीज लि० और मै० एपफोटेक्स लैटिसेज लि०, दोनों ही हार्ड स्टिरीन रबड़ (एच एस आर) बनाते हैं और यह कि यह उत्पाद केवल सीमाशुल्क वर्गीकरण के अध्याय 40 के अंतर्गत आया और यह भी कि संबद्ध देशों से एस बी आर की पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में इस उत्पाद के संबंध में वर्गीकरण दिया जा चुका है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क दिया गया है कि यह उत्पाद काफी व्यापक है और यह सीमाशुल्क वर्गीकरण के दो अध्यायों में फैला हुआ है जबकि अध्याय 39 रेजिन से संबंधित है न कि रबड़ से, जिस उत्पाद का घरेलू उद्योग विनिर्माण करता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के किसी व्यापक कवरेज के कारण जापान के एसाप्लैक्स, जर्मनी के स्टाररोलस और यू एस ए के के-रेजिन जैसे उत्पादों की कुछेक श्रेणियों पर भी पाटनरोधी शुल्क लग जाएगा भले ही उन्हें जांच के दायरे में शामिल न किया जा सकता हो प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ईयू की पद्धति को विशिष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के संदर्भ में उद्धृत किया गया है।

उपरोक्त तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और जांच में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा ग(1) में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद पूर्वोक्त पैरा में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा उल्लेख किए जा रहे जापान, कोरिया, यू एस ए, तुर्की और ताईवान के एस बी आर से संबंधित पूर्ववर्ती जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद से व्यापक होने के कारण भिन्न है। विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए इस अनुरोध को नोट करते हुए कि वस्तु की कुछेक श्रेणी अर्थात् जापान का एसाप्लैक्स, जर्मनी का स्टाररोलस और यू एस ए का के-रेजिन जांच के दायरे में नहीं आएंगी, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा ग(1) में यथा निर्दिष्ट विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करते हैं किन्तु निम्नानुसार उत्पाद की कुछेक श्रेणियों को अलग रखते हैं। विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

" सभी ग्रेडों और स्वरूपों का हार्ड स्टिरीन बुटाडिन रबड़, जिसे हार्ड स्टिरीन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) भी कहा जाता है। एच एस आर में एस बी आर 1900 सीरीज जिसे हार्ड स्टिरीन रेजिन लेटेक्स मास्टर बैच भी कहा जाता है और एच एस बी आर जिसे हार्ड स्टिरीन रि-इन्फोर्समेंट पोलिमर भी कहा जाता है, शामिल हैं। इस उत्पाद में पोलिस्टिरीन, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, एक्रिलोनाईट्राइल बुटाडिन स्टिरीन कोपलीमर्स, स्टाईरिन एक्रिलोनाईट्राइल कोपलीमर्स शामिल नहीं हैं।

इसके अलावा एस बी आर 1500 और 1700 सीरीज उत्पाद में शामिल नहीं हैं।

जहां तक सीमाशुल्क वर्गीकरण और विचाराधीन उत्पाद का संबंध है, प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा विशिष्ट रूप से किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि स्टिरीन तत्व के अनुसार उत्पाद का आयात अध्याय 40, सीमाशुल्क शीर्ष 4002.19 (आई टी सी वर्गीकरण 4002.1902) (50% से अधिक स्टिरीन तत्व वाली स्टिरीन ब्यूटाडिन रबड़) और अध्याय 39 सीमाशुल्क शीर्ष 3903.90 (आई टी सी वर्गीकरण 3903.9000) (पोलिस्टिरीन, स्टिरीन एकीलोनाइ टाइल कोपोलीमर्स एवं एकीलोनाइड्राइल ब्यूटाडिन स्टिरीन कोपीलीमर्स) से भिन्न प्रार्थामिक स्वरूप में स्टिरीन के कोपीलीमर्स के द्रव्य किया जा सकता है।

माननीय सीगेट के दिनांक 2.2.2000 के आदेश सं.20 एवं 21/2000 का स्मरण करते हुए प्राधिकारी का यह भी मानना है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण उस सीमा तक संगत है, जिस सीमा तक उत्पाद को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है और यह कि सीमाशुल्क शीर्ष के तहत वर्गीकरण पर ध्यान न देते हुए उत्पाद का उक्त वर्णन, उपरोक्तनुसार, बाध्यकारी है। प्राधिकारी ने इस कैटिगोरी (उत्प्रेरक) मामले का भी स्मरण किया जिसमें संबद्ध वस्तु की निकासी सीमाशुल्क वर्गीकरण के दो अध्यायों के तहत की गई थी।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता और मानक के संबंध में कुछेक अनुरोध किए गए हैं। साथ ही साथ इस आशय के विचार भी व्यक्त किए गए हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की समग्र मांग को पूरा करने में असमर्थ है। इन अनुरोधों में इस हद तक अंतर्निहित विरोधाभास है कि एक ओर तो ऐसे उपयोक्ता घरेलू उत्पादों से सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता पर भी विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस लिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि उपयोक्ताओं के गुणवत्ता और मानक संबंधी दावे अप्रामाणिक, परिमाण रहित हैं और इसलिए इन्हें रद्द किया जाता है।

प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु का संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान न होने के बारे में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों को और इस बात को भी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों में समानता की व्याख्या नहीं की गई है। प्राधिकारी निर्यातक मै0 फर्मा कैमकजना डीरी एस ए, पोलैंड द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों को नोट करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि जांच

अवधिक के दौरान उनके द्वारा निर्यातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु में अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं हैं। पोलैंड से उत्पादित सखु का इस्तेमाल घरेलू उत्पाद जैसे समान उपयोगों में किया गया था और यह कि फुटवियर/अन्य अनुप्रयोगों में कुछेक सामान्य ग्राहकों द्वारा उपयोग के संदर्भ में इन वस्तुओं का तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ग्रेड के ई आर, 1904, जिसका निर्यात पोलैंड के निर्यातक द्वारा किया गया है, को छोड़कर उनके द्वारा विनिर्मित अन्य ग्रेडों अर्थात् के ई आर 1909 और के ई आर 9000 में भी उनके द्वारा निर्यातित अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं हैं और इनका इस्तेमाल एक जैसे अन्तिम उपयोगों में भी किया जाता है और इसलिए ये जांच के दायरे में आते हैं और समान वस्तु की जांच परा खरे उतरते हैं।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै0 बेयर इंटरनेशनल एस ए, स्विट्जरलैंड द्वारा निर्यातित वस्तु भी अन्तिम उपयोग के संबंध में अनुप्रयोग और ग्राहक वार दोनों तरह से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु से अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं रखने के कारण तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी है। अतः यथा- उल्लेखित समान वस्तु से संबंधित निष्कर्ष को समरण कर उसकी पुष्टि करते हैं।

घ.1 घरेलू उद्योग का आधार

(क) मै0 अपार इन्डस्ट्रीज लि0 और मै0 एक्कोटेक्स लैटिसेज लि0 ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

(i) हम घरेलू उद्योग के आधार के बारे में अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराते हैं, जिन्हें संक्षिप्तता की बजह से पुनः उद्धृत नहीं किया जा रहा है। याधिकाकर्ता आधार संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं और वे नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

(ख) आल इंडिया फेडरेशन आफ रबड़ फुटवियर मैनुफैक्चरर्स और मै0 पैरागन रबड़ ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

(i) इस याचिका में याधिकाकर्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लि0 ने हाल ही में अपना उत्पादन बंद कर दिया है किन्तु उन्हें आश्चर्यजनक ढंग से क्षति के प्रयोजनार्थ अपने आंकड़े शामिल करने की मांग की है।

- (ii) सबसे अधिक रोचक बात यह है कि याचिकाकर्ताओं ने 1999 में ताइवान से एन बी आर के आयात के विरुद्ध एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख किया गया था कि मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स ने पिछले कई वर्षों से अपना उत्पाद रोक दिया है ।
- (iii) मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लि0 को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने लगभग 3 वर्षों से अपना उत्पादन बंद कर दिया है और तदनुसार उसे क्षति के प्रयोजनार्थ भी शामिल नहीं किया जा सकता ।
- (iv) यदि मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स को क्षति हेतु घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल किया जाना है (जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया प्रतीत होता है) तो याचिकाकर्ताओं- मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 तथा एफकोटेक्स लैटिसेज लि0 के पास इस याचिका को दायर करने का पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लि0 का भारत में एच एस आर के घरेलू उत्पादन का 85% से अधिक का हिस्सा बनता है । यदि उनकी क्षमता को हिसाब में लिया जाना है तो स्पष्ट तौर पर 15% की क्षमता के साथ याचिकाकर्ता यह याचिका दायर नहीं कर सकते ।
- (v) इसके अलावा इस बात को मानते हुए किन्तु स्वीकार न करते हुए कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग हैं तो उसी सार्वजनिक स्रोत जिसे पर याचिकाकर्ता विश्वास करते हैं, से उन्हीं गोपनीय आंकड़ों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 ने स्वयं यू के जो यूरोपीय संघ का एक भाग है, से वर्गीकरण 4002.1900 के तहत आयात किया है । क्या अपार इंडस्ट्रीज को घरेलू उद्योग से हटा दिया जाए । अनुरोध है कि केवल इसी आधार पर माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचार करना चाहिए कि इससे यह भी पता चलता है कि जांच शुरुआत के समय समूहो तथ्य निर्दिष्ट प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाए गए थे ।

2. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछेक हिबतद्ध पार्टियों ने यह संकेत दिया है कि यदि लागत और क्षति के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ एस बी आर के एक घरेलू उत्पादक मै0 सिंथेटिक्स एंड कैमिकल्स लि0

के आंकड़ों को शामिल किया जाता है तो याचिकाकर्ता इस याचिका को दायर करने के आधार को पूरा नहीं करेगा और यह कि मै0 सुपार इंडस्ट्रीज लि0 ने भी जांच अवधि में ई यू के क्षेत्रों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। प्राधिकारी उपरोक्त अनुरोधों को नोट करते हुए यह दोहराते हैं कि मै0 अपार तथा मै0 एक्कोटेक्स ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और यह कि मै0 सिंथेटिक एंड कैमिकल्स लि0 ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है और उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं किया है और यह कि मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 और मै0 एक्कोटेक्स लैटिसेज लि0 नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग के आधार को पूरा करते हैं और वे नियम 5(क) और 5(ख) के अनुसार याचिका को दायर करने की अपेक्षित हैसियत भी रखते हैं। इसलिए इस संबंध में प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के आधार के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा ग(3) को स्मरण करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं।

ड.1 अन्य मुद्दे

- (क) मै0 अपार इंडस्ट्रीज लि0 और मै0 एक्कोटेक्स लैटिसेज लि0 मुंबई ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं—
- (i) याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में फैक्टरियों के पतों के बारे में सूचना को छिपाया नहीं गया था। यह मात्र भूल थी और जिसकी तरफ किसी हितबद्ध पक्ष ने संकेत नहीं किया था। वस्तुतः दोनों कंपनियों के संयंत्रों का पते भारत में संबद्ध वस्तु के अनेक उपभोक्ताओं को भलीभांति मालूम है। संगत पते इस प्रकार हैं—

अपार इंडस्ट्रीज लि0

धर्मसिंह देसाई मार्ग,

माहुल ट्राम्बे,

मुंबई-400074 महाराष्ट्र

संपर्क व्यक्ति: श्री जी आर करन्दिकर

दूरभाष-5951531/5544005

फेसीमाइल- 5541708

कंपनी ने अपने बालिआ संयंत्र में भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है, जिसका पता निम्नानुसार

है:-

गोंव-डुंगरी

लालुका-बालिआ

जिला- भरुच-गुजरात

संपर्क व्यक्ति: श्री दिनेश बाले

दूरभाष: 2643-70442/3/5

फेसी माइल 2643-70010

एप्कोटेक्स लैटिसेज लि०

प्लॉट सं० 3/1,

एम आइ डी सी का तालोजा औद्योगिक क्षेत्र

पौ०औ० तालोजा- जिला-रिगाड़ महाराष्ट्र

संपर्क व्यक्ति: श्री बी वी मंजुनाथ

दूरभाष सं. 7412239

फेसी माइल 7412360

- (ii) सार्वजनिक सुनवाई में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा मांगी गई सूचना के अनुसार अगोपनीय आधार पर सूचना देते समय घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उत्तर देने वाले निर्यातकों के संबंध में मिलती जुलती सूचना और एस एस आर की मांग के ए आइ आर आइ ए के आकलन के आधार को उपलब्ध कराया जाए ।
- (iii) यह मुद्दा विपक्षी हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाया गया था कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त सूचना नहीं दी थी ।

हमारा अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए आठ माह का समय लिया और जांच शुरू करने से पहले कई अतिरिक्त सूचनाओं के साथ-साथ कई स्पष्टीकरण भी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगे गए थे, जो घरेलू उद्योग ने उपलब्ध भी करा दिए थे । इस आठ माह की अवधि के

दौरान घरेलू उद्योग के आरोपों की विस्तार पूर्वक जांच की गई है। इसके अलावा हमारा अनुरोध है कि घरेलू उद्योग से पाटन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करना अपेक्षित है और यह निर्यातकों का दायित्व है कि वे बिना किसी छिपाव/छेड़-छाड़ के संपूर्ण सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराए ताकि वह यह प्रमाणित कर सकें कि कोई पाटन नहीं हुआ था। जांच शुरू करने से पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 20.12.2000 की जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित, याचिका में दी गई सूचना की प्रमाणिकता और सत्यता की जांच की। यह जांच नियमों के अनुसार शुरू की गई है। विरोधी हितबद्ध पक्षों का तर्क शायद यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच शुरू होने से पहले मामले की जांच कर लेनी चाहिए। हमारा अनुरोध है कि जांच शुरू करने का उद्देश्य क्षति पहुंचाने वाले आरोपित पाटन की मौजूदगी करना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच शुरू करने से पहले उक्त आरोप की जांच के लिए बाध्य नहीं हैं।

(iv) ए आई आर आई ए ने कंपनी के बारे में कुछेक सूचना प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को और हमें भी लिखा है हालांकि हम यह पाते हैं कि पोलैंड के निर्यातक द्वारा मिलती जुलती सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, तथापि हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध करा रहे हैं। हम इस सूचना को निर्यातकों, आयातकों और ए आई आर आई ए को खुलासा करने के इच्छुक हैं। तथापि हम गोपनीयता के मुद्दे पर निर्यातक और घरेलू उत्पादक के संबंध में इसी तरह का व्यवहार प्रदान करने का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि निर्यातक द्वारा गोपनीयता अनुरोध जरूरी है, तो हम भी समान व्यवहार का अनुरोध करते हैं। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से है कि इस सूचना का खुलासा विरोधी हितबद्ध पक्षों को कर दिया जाना चाहिए तो हम निम्नलिखित सूचना का अनुरोध करते हैं-

1. दो उत्तरदाता निर्यातकों के संबंध में सूचना की समानता ।
2. एच एस आर की मांग और उसके आधार का ए आई आर आई ए का निर्धारण। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि ए आई आर आई ए को उस स्थिति में यह निर्देश दिया जाए कि वह इस आशय की आगे सूचना उपलब्ध करवाए कि किस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा इस मांग को पूरा किया गया था जैसकि विदित है निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मांग को आयातों की धनराशि और घरेलू

उद्योग द्वारा बिक्री की रकम के रूप में परिभाषित किया है अतः आई आर आई ए द्वारा तदनुसार मांग प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है ।

3. प्रत्येक उत्तरदाता आयातक द्वारा आयातों की मात्रा के बारे में सूचना ।

प्रकटन विवरण पत्र के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

1. विरोधी हितबद्ध पार्टियों द्वारा अनेक ऐसे अनुरोध किए गए हैं जो या तो तथ्यतः सही नहीं है या फिर उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करने के प्रयास में किया गया है या फिर वे वर्तमान जांच से संगत नहीं है । उदाहरणार्थ यह उल्लेख किया गया है कि याधिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों अहस्ताक्षरित हैं और उनसे विवरण देने की जिम्मेवारी लेने वाले व्यक्तियों का पता नहीं चलता है उक्त तर्क में इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर लिखित अनुरोधों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित पत्र शीर्ष संलग्न था ।
2. अनेक अनुरोध ऐसे हैं जो पुष्टि हीन अथवा अनिर्णायक बने रहे अथवा उनसे कोई भी तर्क/अभिकथन हासिल नहीं हुआ । उदाहरणार्थ जब विरोधी हितबद्ध पार्टियों को यह निर्देश दिया जाता है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए तो विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने तत्पश्चात यह तर्क दिया है कि उत्पादन लागत के संबंध में सामान्य मूल्य का साक्ष्य केवल उदगम वाले देश में उत्पादन लागत के संबंध में होना चाहिए । वस्तुतः यह निर्यातक का तर्क भी नहीं है कि घरेलू उद्योग ने भारतीय लागत को संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य के रूप में लिया है ।
3. सूचना के प्रकटन और सूचना की गोपनीयता से संबंधित मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है । आश्चर्य इस बात का है कि इस प्रकार का तर्क उन हितबद्ध पार्टियों की ओर से दिया गया है जिनके आंकड़े दायर किए गए आंकड़ों से अत्यधिक भिन्न पाए गए हैं वस्तुतः घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि ऐसे निर्यातकों के उन उत्तरों को पूर्णतः रद्द कर दिया जाना चाहिए जिनमें बाद में की गई जांच के आधार पर यह पाया गया है कि आरंभ में प्रस्तुत की गई सूचना वस्तुतः गलत और भ्रामक थी ।

4. जहाँ तक गोपनीयता का संबंध है, ऐसी कोई सूचना जो गोपनीय स्वरूप की होती है, उसे प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाता है। यह उल्लेख करना संदर्भ के बाहर नहीं है कि निर्यातकों ने भी गोपनीयता का दावा करने हेतु किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है और फिर भी निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।
5. ऑल इंडिया फ़ैडरेशन ऑफ़ रबड़ फूटवियर मैन्यूफ़ैक्चर (फ़ॉर्म) द्वारा मांगी गई सूचना के बारे में यह अनुरोध है कि फ़ॉर्म ने अपनी सुविधानुसार यह उल्लेख नहीं किया है कि घरेलू उद्योग ने भी फ़ॉर्म को अनेकों पत्र भेजे हैं (पत्रों की प्रतियां निर्दिष्ट प्राधिकारी को भी पृष्ठांकित की गई थीं) जिनमें न केवल शामिल प्रमुख मुद्दों का जवाब ही नहीं दिया गया बल्कि उनमें घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अन्य सुझावों से बचा भी गया था।
6. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने ऐसा जाहिर किया है कि मानो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पूर्व मामले की पहले जांच करली हो। यह अनुरोध है कि जांच शुरू करने का प्रयोजन आरोप की जांच शुरू करने से है न कि प्राधिकारी को शुरूआत के बारे में पहल जांच करनी चाहिए।
7. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने मांग का मूल्यांकन करते समय अनुमानों का सहारा लिया है। जांच अवधि में सबद्ध उत्पाद की मांग वार्षिक आधार पर 17000 मी.टन की सीमा में थी।

(ख) मैसर्स फर्मा कैमिकजना डौरी एस0ए0, पोलेण्ड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- (i) अनुरोध है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अनुरोध किया गया है वह अहस्ताक्षरित हैं और इससे यह पता नहीं लगता है कि दिए गए वक्तव्यों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति कौन हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी है। इसका अलावा, दिए गए कुछेक बयान भ्रामक और गलत हैं। तदनुसार, बयान देने वाली पार्टी को स्वयं परिचय देना चाहिए।
- (ii) नियम 5(3) (क) में कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के तहत प्रस्तुत किसी आवेदन के अनुसरण में कोई जांच तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि (क) समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में समर्थन अथवा विरोध की सीमा की जांच के आधार पर यह निर्धारित न हो जाय कि आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

(ख) आवेदन में प्रदत्त साक्ष्यों की यथार्थता और पर्याप्ता की जांच न हो जाये और वह स्वयं की इस तथ्य से संतुष्ट न कर ले कि निम्न के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है :-

- i) पाटन,
- ii) क्षति, जहाँ लागू हो, और
- iii) जहाँ लागू हो, वहाँ किसी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए इस प्रकार के पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध ।

उपरोक्त प्रावधानों पर एक नजर डालने पर यह स्पष्ट होता है कि जांच के प्रत्येक चरण में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जरूरत पड़ती है । जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ केवल एक अन्तर यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्ण सतुष्टि के बजाय पर्याप्त साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है । तथापि, यह बात भी नोट की जाय कि यद्यपि जांच शुरुआत और अनंतिम/अंतिम जांच परिणामों के बीच साक्ष्यों के स्तर में भिन्नता हो सकती है तथापि प्राधिकारियों को जांच शुरुआत के समय अथवा अनंतिम/अंतिम जांच परिणामों के समय साक्ष्य के "स्वरूप" को बदलने की स्वतंत्रता नहीं है । इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए अनुरोध है कि कोई जांच शुरू करने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य साक्ष्यों के साथ-साथ सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए । प्रथम विकल्प यह है कि निर्यातक देश के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमते होनी चाहिए । कतिपय शर्तों के तहत अन्य दो विकल्प हैं :-

- तीसरे देश की निर्यात कीमत
- उद्गम वाले देश की उत्पादन लागत जमा उचित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत तथा लाभ ।

यह मानते हुए कि जांच शुरुआत के लिए उक्त तीनों विकल्पों में से किसी एक पर निर्भर होना पर्याप्त था याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लिए यह आवश्यक था कि वह उस विशेष विकल्प विशेष के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराए । वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने "उत्पादन लागत" पद्धति पर विश्वास किया है । ईयू और पोलैंड जैसी अर्थव्यवस्था वाले किसी बाजार के लिए "उत्पादन लागत" पद्धति के चयन करने के गुण-दोषों और उपयुक्तता पर हमारी आपत्तियों पर पूर्वाग्रह किए बिना हमारा निवेदन है कि घरेलू उद्योग न केवल उद्गम के देश की उत्पादन लागत जमा व्यय एवं लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया होगा ।

(iii) नम्र निवेदन है कि उस सूचना, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय रखा गया है, के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया गया है वह सभी पाटनरोधी जांचों की आधारशिलाओं अर्थात् पारदर्शिता एवं प्रतिपक्षीय जांच पर एक सबसे बड़ा अघात पहुँचाता है। अपेक्षित सूचना न देने के लिए यह तर्क दिया गया है कि निर्यातक से कहा जाय कि वह भी इसी प्रकार की सूचना प्रदान करें। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्यातक द्वारा क्या सूचना मांगी जा रही है जिसे गोपनीय रखने का वह हकदार नहीं है। यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग ही विशिष्ट स्रोतों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास गया था। यह कानून का एक सुस्थापित तथ्य है कि मामला दायर करने वाली पार्टी के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। घरेलू उद्योग को प्रथमतः अपर्याप्त और गलत सूचना देने की अनुमति नहीं हागी और जब यह कहा जाता है कि इस विषय पर मौजूदा नियमों और निर्देशों के तहत इसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता है तो यह तर्क दिया जाता है कि निर्यातक को इस प्रकार की सूचना देने के लिए कहा जाना चाहिए। गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने के बार में घरेलू उद्योग की जिम्मेदारी की इतने हल्के तरीके से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमारा अनुरोध है कि घरेलू उद्योग के दृष्टिकोण की वजह से इन नियमों के तहत हमारे अधिकारों को गंभीर क्षति पहुँचती है। माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से पुनः अनुरोध है कि वे कृपया नियमों के तहत यथापेक्षित घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कारणों से हमें अवगत कराएं ताकि निम्नलिखित सूचना गोपनीय रखी जा सके और क्या इन कारणों को प्राधिकारी ने पर्याप्त माना है :-

- i) यह कहने का आधार कि एचएसआर की निकासी भी अध्याय 39 के तहत की जा रही है।
 - ii) अध्याय 39 के तहत एचएसआर के कथित आयातों का स्रोत और आधार।
 - iii) तथाकथित सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर आयात संबंधी आकड़े।
 - iv) अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य।
 - v) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन मात्रा।
 - vi) घरेलू उद्योग द्वारा अन्य संबद्ध उत्पादों की उत्पादन मात्रा।
- (iv) कई स्थानों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा जा उद्धरण, विवरण और उल्लेख किए गए हैं वे गलत हैं और उन्हें उस सच्चे संदर्भ को छुपाकर, चुनिंदा बनाया गया है जिस संदर्भ में उनका जिक्र किया गया है। तदनुसार, नम्र निवेदन है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उन्हें अंतिम मूल्य पर स्वीकार करने की बजाय उनकी यथार्थता और उसके संदर्भ की जांच करें।

(✓) निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्न के कारण जांच समाप्त कर सकते हैं

- (क) जांच शुरू करते वक्त गलत और अपर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं थी ।
- (ख) कोई पाटन नहीं हुआ है ।
- (ग) याधिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है ।
- (घ) कथित पाटन और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।
- (ङ) घरेलू उद्योग अपने तर्कों को सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है और वह

निर्यातक/प्रयोक्ता उद्योग द्वारा उठाए गए तथ्यपरक और विधिसम्मत के मुद्दों का जवाब देने में विफल रहा है ।

(ग) मैसर्स बेयर इंटरनेशनल एस0ए0 स्विटजरलैण्ड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(i) मैसर्स बेयर इंटरनेशनल एस0ए0 ने संकेत दिया है कि जिस महत्वपूर्ण मुद्दे का निराकरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को करने की जरूरत है वह गोपनीयता के स्वरूप का है और नग्न निवेदन है कि प्राधिकारी को उन आंकड़ों को रखने की गोपनीय जरूरत है जिनका प्रतिस्पर्धियों अथवा हितबद्ध पक्षों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए नुकसान देय है । प्राधिकारी को स्पष्ट यह निर्धारित करना आवश्यक है कि पार्टियों द्वारा गोपनीय रूप में प्रदत्त कौन सी सूचना वास्तव में गोपनीय स्वरूप की सूचना नहीं है और इस तथ्य के बावजूद उसे प्रकट करना कि सूचना प्रदान करने वाली पार्टी ने उसे गोपनीय चिह्नित किया है । ऐसा न करने से प्रभावी प्रति सूचना देने में पार्टियां असमर्थ होंगी जिसका प्रयोग किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए उनके विरुद्ध किया जा सकता है और इससे अन्याय हो सकता है और अज्ञात गलत निर्णय पर पहुँचा जा सकता है ।

(ii) वास्तव में शिकायत में दिए गए सभी आंकड़ों को गोपनीय माना गया है जिसमें पॉलीमर प्लास्टिक एण्ड रबड़ जर्नल द्वारा संकलित आंकड़े भी शामिल हैं जो सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध एक विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज और प्रकाशन नहीं हैं । अतः अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इसका विश्लेषण कर ऐसी सूचना प्रदान करनी चाहिए जिसे अपने विवेक से गोपनीय न समझा जाय ।

(घ) मैसर्स ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्युफैक्चर्स और मैसर्स पैरागन रबड़ ने

निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- (i) पाटनरोधी नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना गोपनीय रखने की जरूरत के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए । विशेष रूप से पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) और नियम 6 संगत हैं ।
- (ii) जिन पहलुओं को घरेलू उद्योग ने गोपनीय रखा है उनमें इस विषय पर उपरोक्त निर्देशों, नियमों और विधिशास्त्र की अनदेखी की गई ।
- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग को विशेषरूप से कहा था कि वह प्रयोक्ता उद्योग को मूल सूचना प्रदान करे । इससे प्रोत्साहित होकर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्युफैक्चर्स (फोर्म) ने घरेलू उद्योग को पत्र लिखा था कि वह माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार संगत सूचना प्रदान करे । हम आपको सचूत करना चाहेंगे कि फोर्म को कोई सूचना नहीं मिली है ।
- (iv) नियम 5(3) (क) में कहा गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के तहत प्रस्तुत किसी आवेदन के अनुसरण में कोई जांच तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि (क) समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में समर्थन अथवा विरोध की सीमा की जांच के आधार पर यह निर्धारित न हो जाय कि आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) आवेदन में प्रदत्त साक्ष्यों की यथार्थता और पर्याप्तता की जांच न हो जाय और वह स्वयं को इस तथ्य से संतुष्ट न कर ले कि निम्न के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है

(क) पाटन,

(ख) क्षति, जहाँ लागू हो, और

(ग) जहाँ लागू हो, वहाँ किसी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए इस प्रकार के पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध ।

- (v) पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना की यथार्थता और पर्याप्तता संबंधी पहलू डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-5.3 से उत्पन्न एक दायित्व है। यह मुद्दा ग्वाटेमाला-मैक्सिको सीमेंट मामले में पैनल के निर्णय से संबंधित एक विवाद में भी उठाया गया था। उस मामले में माननीय पैनल की राय थी कि जिस पहलू पर किसी विशेष मामले की शुरुआत करते समय विचार किए जाने की जरूरत है, उस पर बाद में भूतलक्षी प्रभाव से सुधार नहीं किया जा सकता। पैनल के निर्णय का पैरा 8.62 संगत है।
- (vi) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ पूर्णरूप से अपर्याप्त और गलत है। आयातों से संबंधित सूचना मात्र अनुमानों पर आधारित है और इसमें अनेक भ्रामक विवरण हैं।
- (vii) इस स्वः सृजित भ्रम का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता गौण स्रोतों से आयात की सूचना संकलित करता जाता है जिसे गोपनीय रखा गया है। ऐसा करते समय, उसने स्वीकार किया है कि गौण स्रोतों की सूचनाओं में सभी भारतीय पत्तनों की सूचना प्रदर्शित नहीं होती है।
- (viii) नम्र निवेदन है कि याचिका दायर करने हेतु प्रयोग में लाए जा रहे आंकड़ों के स्वः प्रेषण और चुनिंदा प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए नियम 5(3) (ख) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी पर जो जिम्मेदारी डालता है, उसका वस्तुतः रिपोर्ट के पैरा 8.31 के अनुसार ग्वाटेमाला मैक्सिको सीमेंट मामले में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
- (ix) पाटनरोधी नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना गोपनीय रखने की जरूरत के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। विशेष रूप से पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) और नियम 6 संगत हैं।
- (x) हम यह दोहराना चाहेंगे कि जिन पहलुओं को घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय रखा गया है वह इस विषय पर उपरोक्त निर्देशों, नियमों और विधिशास्त्र के पूर्णतः विपरीत हैं।
- (xi) पुनः दोहराया जाता है निर्दिष्ट प्राधिकारी न सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग को विशेषरूप से कहा था कि वह प्रयोक्ता उद्योग को मूल सूचना प्रदान करे। इससे प्रोत्साहित

होकर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्यूफक्चर्स (फोर्म) ने घरेलू उद्योग को पत्र लिखा था कि वह माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार संगत सूचना प्रदान करे। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि फोर्म को कोई सूचना नहीं मिली है।

- (xii) यह दर्शाया गया था कि घरेलू उद्योग ने "यह कहने का आधार कि एचएसआर की निकासी अध्याय 39 के तहत की जा रही है, अध्याय 39 के तहत एचएसआर के कथित आयातों का स्रोत और आधार, तथाकथित सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर आयात आंकड़े, अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मात्रा, घरेलू उद्योग द्वारा अन्य संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा और विनिर्माता एककों के नाम और पत्तों" के बारे में गोपनीय सूचना रखी है। यह अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि वह कम से कम उपरोक्त सूचना अगोपनीय आधार पर प्रस्तुत करे।
- (xiii) हमने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया था कि वे कृपया हमें बताएं कि क्या घरेलू उद्योग ने इस मामले में नियम की स्थिति और निर्देशों के अनुसरण में ऐसी सूचना को उपरोक्तानुसार गोपनीय रखने के कारण बताए थे। दुर्भाग्यवश इस मामले में हमें कोई जबाब नहीं मिला है। हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि सार्वजनिक फाइल की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने मूल सूचना गोपनीय रखने का ऐसा कोई कारण नहीं बताया। अतः नम्र निवेदन है कि इस मामले पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट निर्णय लिए जाने का प्रश्न नहीं उठेगा। अतः केवल इस आधार पर इस मामले की जांच समाप्त किए जाने की जरूरत है।
- (xiv) उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता मैसर्स पोलिमर्स प्लास्टिक एण्ड रबड़ जर्नल द्वारा प्रदत्त आयात संबंधी आकड़ों पर विश्वास करने का दावा करते हैं। प्रयोक्ता उद्योग ने जनवरी से सितम्बर, 2001 के दौरान किए गए पोलिमर्स प्लास्टिक एण्ड रबड़ जर्नल के आयात आंकड़ों की एक प्रति प्राप्त कर ली है। एसआर 1900 का पोलैण्ड से जा एकमात्र आयात हुआ था वह 30 अगस्त, 2000 को 43.68 रुपये प्रति किग्रा की निर्यात कीमत पर किया गया था जबकि याचिकाकर्ताओं ने पोलैण्ड से 38.93 रुपये प्रति किग्रा की निर्यात कीमत पर आयात होना दर्शाया है।

- (xv) इसके अतिरिक्त, आयात आंकड़े घरेलू उद्योग को हुई स्पष्ट क्षति दर्शाते हैं, इस प्रकार इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह सुनिश्चित करने की क्षमता बाधित होती है कि क्या वर्तमान याचिका में पाटन हुआ है अथवा वास्तव में क्षति हुई है। मात्रा में वृद्धि करके और निर्यात कीमत घटाकर प्रत्यक्ष क्षति को गंभीर प्रदर्शित किया गया है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- (i) यह कि सम्पूर्ण कार्रवाई त्रुटिपूर्ण आवेदन के आधार पर शुरू की गई है अर्थात् प्रारंभिक जांच परिणाम पूरे होने के पश्चात् याचिकाकर्ता द्वारा लिखित में अपने संयंत्र के स्थान के बारे में बताना स्वतः ही त्रुटिपूर्ण आवेदन का प्रमाण है। केवल इसी आधार पर जांच बंद कर देनी चाहिए थी लेकिन पाटनरोधी प्राधिकारी द्वारा जांच बन्द न करने का कारण उन्हें अच्छी तरह मालूम है।
- (ii) सिंथेटिक रबड़ की निकासी अध्याय 39 के तहत की जा रही है, इस दावे की प्रामाणिकता के बारे में हमारे अनुरोध का जवाब हमें न तो याचिकाकर्ता से और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त हुआ है।

(ड.) मैसर्स शर्मा एसोसिएट्स नई दिल्ली ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- (i) प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना के जवाब में मैसर्स शर्मा एसोसिएट्स ने कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा जिन आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है वे आंकड़े प्रदान किए गए हैं, जो आंकड़े उन्होंने मांगे थे वे नहीं दिए गए हैं और यह कि वास्तविक आंकड़े छुपा लिए गए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी न मात्र डाकघर का कार्य किया है और उसने लिखित अनुरोध के संलग्नक के निमित्त कुछेक सूचना भेजी है। यह सूचना अत्यन्त अपर्याप्त, अपूर्ण और भ्रामक है। यह जांच प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का सम्मान किए बिना चल रही है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वह हमें क्षति मार्जिन निकालने की विधि और अन्य मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए मौखिक सुनवाई का मौका दे। कोई भी अंतिम निर्णय किए बिना हमारी व्यक्तिगत सुनवाई के न दे।

(च) मैसर्स बाणिक रबड़ इंडस्ट्रीज, कलकत्ता ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

- (i) मैसर्स बाणिक रबड़ इंडस्ट्रीज ने कहा है कि याचिकाकर्ता की याचिका अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है और यह कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की यथार्थता का सत्यापन नहीं किया गया था और

इसलिए जांच परिणाम 1995 के नियमों के अनुसार नहीं है और पूर्णरूप से दोषपूर्ण, गैर-कानूनी और अधिकारातीत है ।

2. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी एक प्रभावी बचाव के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षों को कतिपय अगोपनीय सूचना न देने के बारे में विभिन्न अनुरोध नोट करते हैं । प्राधिकारी नियमों के प्रावधान और ऐसी स्थिति से निपटने में निर्दिष्ट प्राधिकारी की भूमिका के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट करते हैं । प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 को ध्यान में रखते हुए, यह बात नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा यथा प्रदत्त अगोपनीय याचिका/और सूचना सार्वजनिक फाइल में रखी गई है और अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध करायी गई है । यह तरीका एक समान और सतत रूप से अपनाया जा रहा है ।

इस प्रकार प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों और एक प्रभावी बचाव के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की उनकी इच्छा पर ध्यान देते हुए मांगी गई अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु हितबद्ध पक्षों से अनुरोध किया था ताकि उचित निर्धारण के लिए सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रभावी बचाव किया जा सके । इस बारे में प्राधिकारी स्मरण करते हैं कि एक हितबद्ध पक्ष, अर्थात् मैसर्स शर्मा एसोसिएट्स, जिसने सूचना और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया था, को न केवल सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण करने का अवसर दिया गया था बल्कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी मौका दिया गया था । तथापि, यद्यपि इस प्रकार का अवसर प्रदान किया गया था तथापि हितबद्ध पक्ष पेश नहीं हुआ और निर्दिष्ट प्राधिकारी का एक डाकघर बताते हुए थोड़ी आलोचना की ।

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि कतिपय पक्षों द्वारा यथा निवेदित विभिन्न पहलुओं पर सभी अगोपनीय सूचना इच्छुक पक्षों को प्रदान की गई थी और उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा गया था । प्रकटन विवरण पत्र के प्रत्युत्तर में मैसर्स शर्मा एसोसिएट्स ने कहा है कि वे अपेक्षित आंकड़ों के अभाव में तर्क देने की स्थिति में नहीं थे और इसलिए वे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए । प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि उपरोक्तानुसार यथावांछित सभी आवश्यक तथ्य उनकी अगोपनीयता की सीमा तक, विभिन्न हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराए गए थे । घरेलू उद्योग और पोलैण्ड के सहयोगी निर्यातक दोनों के लिए कच्ची सामग्री जैसे संघटकों समेत लागत के बारे में गोपनीय सूचना मैसर्स शर्मा एसोसिएट्स को प्रदान नहीं की जा सकी क्योंकि ये आंकड़े गोपनीय थे । घरेलू बिक्री कीमत की कच्ची

सामग्री के अनुपात सम्बन्धी सूचना देने से कच्ची सामग्री के बारे में गोपनीय सूचना प्रकट हो जाएगी । इस आयातक द्वारा की गई व्यक्तिगत सुनवाई की मांग, क्षति और क्षति रहित कीमत के निर्धारण की विधि के बारे में थी, जिस पर विधि सम्बन्धी तर्क हमेशा प्रदान किए गए हैं । कच्ची सामग्री की कीमतों के बारे में आंकड़ों की उपलब्धता के मुद्दे से हितबद्ध पक्ष को ऐसे तर्क देने में रूकावट नहीं आनी चाहिए । इसके अलावा, प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण, जो कीमतों में ह्रास के कारण क्षति की मात्रा का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है, घरेलू उद्योग के गोपनीयतागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया गया है और जो इस प्रकार की अन्य जाँचों में भी किसी तरह से हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध नहीं है । अतः प्राधिकारी का मानना है कि प्रभावी बचाव के लिए इन हितबद्ध पक्षों को उचित अवसर और सभी संगत सूचना पाटनरोधी नियमों के तहत प्रदान की गई थी ।

अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि इस हितबद्ध पक्ष ने कोई महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान किए बिना और प्राधिकारी की मदद किए बिना मात्र कोरी आलोचना की है । प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में यथा उपबंधित समुचित क्रियाविधि का अनुसरण किया गया है ।

सीबीइसी के आयात आंकड़ों सम्बन्धी सूचना जिसके लिए कुछेक हितबद्ध पक्षों ने अनुरोध किया था, सीबीइसी ने उपलब्ध नहीं कराया था । तथापि डीजीसीआईएस के अद्यतन आंकड़े, जो केवल सीमा शुल्क आंकड़ों के आधार पर संकलित किए जाते हैं, डीजीसीआईएस द्वारा जारी किए गये हैं ।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह उल्लेख किया गया है कि जाँच की शुरुआत नियम 5(3)(क) के अनुसार विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर नहीं की गई थी । इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की शुरुआत में काफी अधिक समय, वस्तुतः सात माह से अधिक का समय लगा क्योंकि प्राधिकारी को पाटन, क्षति और कारणात्मक सम्बन्ध के बारे में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों की उपलब्धता के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करना पड़ा और जाँच शुरुआत सम्बन्धी सभी मापदण्डों से सन्तुष्ट होने के बाद ही प्राधिकारी ने नियम 5(3)(क) के अनुसार पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की थी जैसाकि सभी मामलों में हमेशा किया जाता है ।

जहाँ तक घरेलू उद्योग समेत विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा दायर आंकड़ों की यथार्थता और प्रामाणिकता का संबंध है, प्राधिकारी ने विधिवत सत्यापन करने और संतुष्ट होने के बाद आंकड़ों को स्वीकार किया है ।

घ. 1 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटनय मार्जिन

क) मै० अपार इंडस्ट्रीज लि० तथा मै० एपकोटेक्स लैटिक्स लि० द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा भारत में संबद्ध देश/क्षेत्र के दूतावासों को प्रश्नावली भेजी थी । तथापि, पोलैंड के केवल एक निर्यातक और यूरोपीय संघ के एक निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर दिया है । निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर पाटन तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है । निर्यातकों ने एक पूर्ण और पूर्व निर्णीत दृष्टिकोण अपनाया है और उसने निर्दिष्ट प्राधिकारी को महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की है । जबकि जर्मनी के निर्यातक ने पूर्ण सूचना न दिए जाने की बात को स्वीकार भी किया है, तथापि पोलैंड के निर्यातक द्वारा दायर उत्तर का अस्वीकार्य है क्योंकि यह अपूर्ण एवं अपर्याप्त है ।
- ii. मै० फरमा कैमिकना डबोरी एस ए, पोलैंड ने प्रश्नावली में यथानिर्धारित पूर्ण सूचना दायर नहीं की है और दायर की गई सूचना अपूर्ण, अपर्याप्त तथा गैर- भरोसेमंद है । उनके द्वारा दायर किया गया अगोपनीय उत्तर अगोपनीय आधार पर सूचना के प्रकटन के बराबर नहीं है ।

- iii. निर्यातक मै0 फरमा कैमिकना डवोरी एस ए द्वारा दायर उत्तर से यह स्पष्ट है कि निर्यातक ने घुनिदा आधार पर सूचना उपलब्ध करवाई है और पूरी सूचना दिए बगैर उसने कई मुद्दों पर पहले से ही निर्णय ले लिया है ।
- iv. उत्तरेकों के मामले में अंतिम जांच परिणाम जिनकी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गयी थी, संगत हैं ।
- v. दिनांक 20 दिसम्बर, 2000 की जांच आरंभ करने की अधिसूचना के अनुसार यह कहा गया है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद हाई स्टाइरीन बुटाडीन कोपीलीमर है, जिसे सभी ग्रेडों और स्वरूपों के हाई स्टाइरीन रेजिन/रबड़ (एचएसआर) भी कहा जाता है....." यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एच एस आर के सभी ग्रेड और किस्में उत्पाद के क्षेत्र में शामिल हैं । तथापि, प्रश्नावली का उत्तर देते समय निर्यातक ने यह निर्णय लेते हुए कि घरेलू बाजार के संबंध में सूचना केवल भारत को निर्यातित ग्रेड के लिए दी जानी है, एच एस आर के केवल एक ग्रेड के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । अपने उत्तर में निर्यातक ने निम्नानुसार उल्लेख किया है:

"पिछले वर्षों और संगत अवधि के दौरान भारत, बाजार (पोलैंड) तथा अन्य तीसरे देशों को के ई आर 1904 (संगत उत्पाद) की बिक्री की कुल मात्रा तथा उससे प्राप्त निवल बिक्री राजस्व, के ब्यौरे परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं ।"

निर्यातक ने एचएसआर की अन्य किस्मों/ग्रेडों के संबंध में पूर्ण सूचना रोक ली है (वास्तव में निर्यातक ने इस तथ्य को भी प्रकट नहीं किया है कि उसके पास एचएसआर के अन्य ग्रेड हैं) । निर्यातक द्वारा लिया गया विचार नियमों और उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा समर्थित नहीं है और

यह निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामले पर निर्णय लेने से रोकेगा। उदाहरण के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को अब उत्पादन लागत (बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक खर्चों) के संबंध में सूचना की उपयुक्तता तय करने और उचित लाभों के स्तर का आकलन करने से रोका गया है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, पूरी सूचना प्रकट न करके निर्यातक प्रारंभिक जांच परिणामों के स्तर पर कम पाटन मार्जिन हासिल करने में सफल रहा है।

vi. निर्यातक द्वारा दायर उत्तर में एक अन्य प्रमुख खामी यह है कि निर्यातक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना और प्रश्नावली में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना में काफी अंतर है।

क) हमने पोलैंड के निर्यातक की उत्पादन लागत का आकलन किया है और यह पाया है कि किसी भी हाल में निर्यातक अपनी पूरी उत्पादन लागत प्राप्त नहीं कर सका है।

(ख) पोलैंड के निर्यातक ने स्वयं सामान्य मूल्य के संबंध में प्रारंभिक पांच परिणामों के अनुसार कुछेक ग्राहकों को की गई बिक्रियों में घाटा होने को स्वीकार किया है। हमारा मत यह है कि सभी सौदे एचएसआर की पूरी लागत से कम पर हुए हैं।

निर्यातक ने आगे सभी सौदों के स्थान पर ग्राहकवार बिक्रियों के ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से निर्यातक को सभी बिक्री सौदों के ब्यौरे उपलब्ध करवाने का अनुरोध करते हैं। यद्यपि एक ग्राहक को की गई बिक्री लाभ पर की गई थी तथापि इस बात की काफी संभावना है कि कुछ सौदे उसी ग्राहक को लाभ पर हुए हों और कुछ घाटे पर हुए हों, जिससे उक्त ग्राहक को लिए औसत लाभ हुआ है। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू बाजार में बिक्री कीमत का

आकलन करते समय सभी घाटा देने वाले सौदों पर ध्यान नहीं देना होगा । यह अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनायी जा रही सुसंगत प्रक्रिया भी है ।

(ग) निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घाटा देने वाले सौदों को अनुबंध । के अनुसार केवल तब छोड़ा जा सकता है जब निर्दिष्ट प्राधिकारी ने बिक्री के समय इन बिक्रियों की उत्पादन लागत के साथ तुलना की है । एक्रिलिक फाइबर के मामले में थाइलैंड के विरुद्ध सी गेट के आदेश का इस संबंध में उल्लेख किया गया था । हम यह कहना चाहते हैं कि:

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभित जांच परिणामों में यह पाया है कि एक ग्राहक को औसत बिक्री कीमत घाटे पर थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नहीं पाया है कि सौदे घाटे पर हुए थे । प्रारंभिक निष्कर्षों में बिक्री के समय उत्पादन लागत की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता ।
2. हालांकि एक ओर निर्यातक ने घरेलू बाजार में सौदे-वार बिक्रियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए हैं तथापि दूसरी ओर निर्यातक ने बिक्री के समय उत्पादन लागत की तुलना करने के बारे में तर्क दिया है ।
3. हालांकि निर्यातक ने बिक्री के समय उत्पादन लागत की तुलना के संबंध में तर्क दिया है तथापि निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना (बिक्री के समय उत्पादन लागत) उपलब्ध करना उचित नहीं समझा है । अतः निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से संगत सूचना उपलब्ध करवाए बिना ही बिक्री के समय की उत्पादन लागत पर विचार करने का अनुरोध किया है अथवा वैकल्पतः , निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुबंध । के अनुपालन की

अनदेखी करने की अपेक्षा करता है क्योंकि उसके द्वारा बिक्री के समय की उत्पादन लागत निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाई गयी थी ।

4. निर्यातक द्वारा घरेलू और निर्यात बिक्रियों के संबंध में उपलब्ध करवाए गए आंकड़े भिन्न आधार पर हैं । जबकि निर्यातक ने भारत को हुए निर्यातों के सीदे-वार ब्यौरे उपलब्ध करवाए हैं तथापि घरेलू बाजार में बिक्रियां ग्राहक वार हुई हैं। अतः निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के उचित तुलना सुनिश्चित करने के प्रयास को विफल करते हुए भिन्न आधार पर आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं ।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए हम यह अनुरोध करते हैं कि निर्यातक द्वारा पूरे और पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं । हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से त्रुटिपूर्ण मुख्य सूचना के मददेनजर निर्यातक द्वारा दायर पूरे उत्तर को अस्वीकृत किए जाने का अनुरोध करते हैं । निर्यातक को उत्तर का अनुपूरक जवाब प्रस्तुत करने अथवा नई सूचना प्रस्तुत करने का और अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चुनिंदा सहयोग के लिए प्रोत्साहन देने के समान होगा । इस स्थिति को मौके पर जांच करके भी नहीं हल किया जा सकता है क्योंकि मौके पर जांच का उद्देश्य सूचना संकलित करना नहीं है । मौके पर जांच हेतु किए जाने वाले दौरे आंकड़ों के संकलन हेतु किए जाने वाले दौरे नहीं होते हैं , मौके पर जांच का उद्देश्य निर्यातक द्वारा पहले से प्रदत्त सूचना की केवल जांच करना है । जब निर्यातक ने पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है तो जांच का प्रश्न नहीं उठता है । हम इस संबंध में डब्ल्यू टी ओ करार के अनुबंध I पर भरोसा करते हैं ।

VII. चूंकि निर्यातक मै0 बेयर इंटरनेशनल एसए ने पूर्ण सूचना दायर नहीं की है और इसे निर्यातक द्वारा स्वीकार भी किया गया है इसलिए निर्यातक को शेष सूचना उपलब्ध कराने

के लिए एक और अवसर प्रदान करने का कोई कारण नहीं है, न ही समूचे विश्व में कोई अन्य जांचकर्ता प्राधिकारी किसी हितबद्ध पक्ष को बार-बार अवसर प्रदान करता है। अतः इस कंपनी के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण पूर्णतः न्यायोचित है और इसकी पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है।

VIII. बेयर के संबंध में हमने सुनवाई में भी यह समझा है कि वे इस स्तर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहते हैं। बेयर के वकील ने उल्लेख किया था कि ई यू तथा भारत में उनकी एच एस आर की बिक्री कीमतों में अधिक अंतर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि बेयर भी ई यू में घाटे पर बिक्री कर रहा था क्योंकि लागत विवरण (जैसा कि डवोरी से संबंधित उपरोक्त खंड में दिया गया है) बेयर के लिए भी लागू होते हैं। अतः हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से बेयर द्वारा विनिर्मित एच एस आर की उत्पादन लागत की जांच करने का भी अनुरोध करते हैं।

प्रकटन विवरण पत्र के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. यद्यपि प्रकटन विवरणक मै0 फरमा कैमिकना डवोरी द्वारा दायर पूर्णतः अपूर्ण, अपर्याप्त तथा भ्रामक सूचना के संबंध में स्वतः स्पष्ट है, तथापि यह पाया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का निर्यातक द्वारा दायर उत्तर के अनुसार आगे कार्यवाई करने का प्रस्ताव है। याचिकाकर्ता सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए निर्यातक के उत्तर और उसकी सूचना स्वीकार किए जाने का कड़ा विरोध करते हैं। निर्यातक के प्रति निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा सहानुभूतिपूर्वक विचार और व्यवहार देना निर्यातक के लिए एक बड़ा बोनस होगा। इसके अतिरिक्त, इससे अन्य निर्यातकों द्वारा भी इसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहन

- मिलेगा । यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि कोरिया से शुल्क की समीक्षा से संबंधित जांच के मामले में घरेलू उद्योग ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में खामियों की ओर बार-बार उल्लेख किया था और फिर भी निर्यातक की सूचना को स्वीकार किया गया था ।
- ii. याचिकाकर्ताओं ने बार-बार यह तर्क दिया है कि विशेषकर पोलैंड के निर्यातक और सामान्यतः सभी निर्यातक उन कीमतों जिन पर इन पार्टियों द्वारा भारत को एच एस आर का निर्यात किया गया था तथा कच्चे माल की प्रचलित कीमतों को देखते हुए अपनी उत्पादन लागत प्राप्त नहीं कर सकते थे । वस्तुतः यह बात नोट करना रोचक है कि निर्यातक ने उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने का जोरदार विरोध किया है और यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस निष्कर्ष को प्रदर्शित करता है कि निर्यातक की अधिकतर बिक्री घाटे पर हुयी थी ।
- iii. यह अनुरोध किया जाता है कि मै0 फरमा कैमिकना डवोरी के लिए प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन अपर्याप्त है । इसके अतिरिक्त, निर्यातक की संपूर्ण सूचना को अस्वीकृत करने का पर्याप्त आधार हैं । साथ ही साथ, हमें यह नहीं पता है कि सार्वजनिक सुनवाई तथा उसके बाद के अनुरोधों में निर्यातक को हमारे उत्तर के संबंध में निर्यातक द्वारा क्या अनुपूरक सूचना दायर की गयी है । हम अधिकारियों के दौरे के पश्चात् निर्यातक द्वारा दायर सूचना के पूरे सैट के लिए अनुरोध करते हैं ।
- iv. यह अनुरोध किया जाता है कि बेयर इंटरनेशनल यूरोपीय संघ से बाहर की एक कंपनी है, जो कि वास्तव में एक व्यापारी है और संबद्ध उत्पादक की एक संबद्ध इकाई है । कंपनी द्वारा दायर उत्तर पूरी तरह से अपर्याप्त है । यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संबद्ध उत्पादक ने

उत्तर दिया था । तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि सामान्य मूल्य का केवल नियम 6(8)के अनुसार निर्धारण किया जा सकता है ।

v. एनिकेम द्वारा किए गए निर्यातों की कम मात्रा के संबंध में दिया गया तर्क अस्वीकार्य है। यदि एनिकेम उत्तर देने का इच्छुक नहीं है तो इसे महत्वपूर्ण न मानते हुए प्राधिकारी से नियम 6(8) के अनुसार इस कंपनी के संबंध में पाटन मार्जिन की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है ।

vi. जहां तक संबद्ध देशों के अन्य असहयोगी निर्यातकों का संबंध है निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया की अंतिम जांच परिणामों में पुष्टि की जानी चाहिए ।

(ख) मै0 एनिकैम इलास्टोमेरी एस.आई.आई. इटली ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. मै0 एनिकैम इलास्टोमेरी एस.आई.आई. इटली ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने वर्ष 2000 में 22 मी0 टन का निर्यात किया है और इस नगण्य मात्रा से घरेलू उत्पादक को क्षति नहीं पहुंच सकती है और इसलिए वे दृढ़ता से यह महसूस करते हैं कि एनिकैम इलास्टोमेरी इटली से एच एस आर की आपूर्तियों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से न केवल उनको वरन भारत में उनके प्रमुख ग्राहकों के साथ भी अन्याय हुआ है ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में, निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. बिक्रियों के हमारे डाटाबेस रिकार्डों के अनुसार हमने केवल वर्ष 1999 में जुलाई, अगस्त और अक्तूबर माह के दौरान अपनी एचएसआर किस्म अर्थात् एचएस 65 की बिक्री की है

जिसकी कुल मात्रा लगभग 328 टन बनती है, आप सारांश शीट में इन बिक्रियों के सभी व्यौरे बाएँ जो हमने अलग से आपके ध्यानार्थ भेजे थे।

- ii. ए.एम.दस्तावेज के अनुसार भारत को 1999 में हुई इन बिक्रियों के लिए एनिकैम की निर्यात कीमत 840 अमरीकी डालर/मी० टन थी, यह कीमत जुलाई-अक्तूबर की पूरी अवधि के लिए रखी गयी है। हम बाद में संबद्ध बीजकों के साक्ष्य दर्शाने की स्थिति में हैं।
- iii. इस अवधि की विनिमय दर पर, ए.एम. दस्तावेज के अनुसार हमारी बिक्री कीमत 1510-1591 लिरे/किग्रा० के बीच है।
- iv. इटली के बाजार के लिए दिनांक 15.6.99 (1999 की तीसरी तिमाही) के एच एस 65 की एनिकैम की आधिकारिक कीमत सूची 1420 लिरे/किग्रा० थी। इस कीमत के संदर्भ में हमारे इटली के बिक्री प्रबंधकों के पास इटली में एचएस 65 की बिक्री करने के लिए हमारी आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम 5 % (अर्थात् 1349 लिरे/किग्रा०)की छूट सीमा थी। हम बाद में संबद्ध दस्तावेज (अर्थात् ए.एम. कीमत सूची) का साक्ष्य दिखाने की स्थिति में हैं। हमने अन्य एशियाई देशों को भी समान कीमतों पर आपूर्ति की है।
- v. जून, 1999 तथा अक्तूबर 1999 के बीच हमने अपने घरेलू बाजार इटली में 1300 लिरे/किग्रा० (प्रबंधन के अनुमति के तहत) तथा 1480 लिरे/किग्रा० के बीच की कीमतों पर प्रतिनिधि ग्राहकों को लगभग 50 टन/माह की बिक्री की है। हम बाद में संबद्ध बीजकों के साक्ष्य दर्शाने की स्थिति में हैं।
- vi. ए.एम. कीमतों की तुलना (घरेलू कीमतों की तुलना भारत को निर्यात कीमतों के साथ) के आधार पर हम भारतीय बाजार में पाटन की स्थिति में शामिल होने का कोई कारण नहीं

देखते हैं ; इटली में हमारी बिक्री कीमतें हमेशा कम रही थी और कम से कम भारत को हमारी निर्यात कीमतों के साथ तुलनीय थीं ।

- vii. हमने वर्ष 2000 तथा 2001 के दौरान किसी मात्रा की बिक्री नहीं की है ।
- viii. उपरोक्त को देखते हुए हम यह महसूस करते हैं कि एनिकैम एसपीए इटली से आपूर्ति किए गए एच एस आर पर पाटनरोधी शुल्क लगा कर प्राधिकारी ने न केवल हमारे साथ बल्कि भारत में हमारे प्रमुख ग्राहकों के साथ भी अन्याय किया है ।
- ix. हम इस पर सहमत तो हैं कि इटली, यूरोपीय संघ का एक भाग है किन्तु संघ के सभी देशों पर एक समान शुल्क लगाना उस देश के लिए अनुचित है जो पाटन क्रियाकलापों में नहीं लगा हुआ है ।
- x. अतः हम एचएसआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क न लगाने का अनुरोध करते हैं ।
- xi. हमारे निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क हटाकर तथा उन देशों से हुए निर्यातों पर ऐसे शुल्क लगाकर जो ऐसे कदाचार में लगे हुए हैं, प्राधिकारी उन देशों तथा भारतीय क्रेताओं के साथ न्याय करेंगे जो ऐसी अनुचित प्रक्रिया में नहीं लगे हुए हैं ।

(ग) मै0 बेयर इंटरनेशनल एस.ए., स्विट्जरलैंड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

मै0 बेयर इंटरनेशनल एस.ए. स्विट्जरलैंड ने यह संकेत दिया है कि सुनवाई के समय यह उल्लेख किया गया था कि वे असहयोगी हैं और यह भ्रामक है ।

- i. हम एसबीआर के संबंध में पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं में इसी उत्पाद की जांच के अधीन रहे हैं और
- ii. सभी संगत दस्तावेज और आंकड़े उन प्रक्रियाओं में पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

- iii. तथापि, प्रारंभिक जांच परिणामों में हमारे उत्तर पर प्राधिकारी द्वारा असंतुष्टि जाहिर करने के तुरंत बाद हमने 19 अप्रैल, 2001 के अपने उत्तर के द्वारा अपेक्षित निर्यातक प्रश्नावली सहित संपूर्ण ब्यौरे उपलब्ध करवा दिए थे ।
- iv. उपरोक्त को देखते हुए हम अपनी गलतफहमी के लिए क्षमा मांगते हैं और आदरपूर्वक यह अनुरोध करते हैं कि हमें असहयोगी निर्यातक न माना जाए । प्राधिकारी के साथ सहयोग न करने की हमारी कभी भी मंशा नहीं रही थी ।
- v. शुरु में यह उल्लेख किया गया था कि हम क्राइलीन एचएस 260 के नाम से बेचे जाने वाले उत्पाद का उत्पादन करते हैं । यही उत्पाद नामतः क्राइलीन एच एस 260 पिछली जांच में संगत उत्पाद था । हमारे द्वारा जांचाधीन एसबीआर के किसी अन्य ग्रेड का निर्यात नहीं किया गया है । वर्तमान जांच में जांच के अधीन एस बी आर का एकमात्र ग्रेड वही उत्पाद नामतः क्राइलीन एच एस 260 है ।
- vi. पिछली कार्रवाई में अंतिम जांच परिणाम निकाले गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया था कि फ्रांस से निर्यातित एस बी आर के सभी ग्रेडों के लिए पाटन मार्जिन 28.2 % है । आगे रिकार्ड किए गए निष्कर्ष में यह पाया गया था कि हमारे उत्पाद का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत की तुलना में काफी अधिक था और इसलिए उस घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी ।
- vii. उपरोक्त से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसी उत्पाद की वास्तव में जांच की गयी थी, पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था, किन्तु निर्यात कीमत से घरेलू बोजार को कोई क्षति नहीं पहुंची थी ।

- viii. सुनवाई के दौरान वास्तविक उपयोक्ताओं और व्यापार एसोसिएशनों द्वारा आगे यह उल्लेख किया गया था कि रबड़ बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इसकी मांग 30600 मी० टन प्रति वर्ष के आस-पास थी । हमारे द्वारा किया गया कुल निर्यात जो 437 मी० टन (सभी बीजक प्रस्तुत) बनता है, 9 महीनों की अवधि के लिए अनुपातिक प्रतिशत अथवा जांच मांग से 2 % कम होगा जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 की अपेक्षाओं से काफी कम है । इसके अतिरिक्त, यदि ईयू को एक ब्लाक के रूप में माना जाता है तो हम यह अनुरोध करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार भारत को अत्यधिक निर्यात करने वाला और कोई निर्यातक नहीं है और इसलिए संचयी रूप से भी ईयू के आयात उक्त नियम में निर्धारित प्रतिशत से कम होंगे । हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि 850 डालर/मी० टन की कीमत एसबीआर के इस ग्रेड के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है और यह एस बी आर की अन्य किस्मों से संबद्ध हो सकती है ।
- ix. हम यह कह सकते हैं कि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ताओं के उत्पादन संबंधी आंकड़े प्रकट अथवा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं और इसलिए याचिकाकर्ता की सुविधा एक बहु उत्पादीय होने के कारण इसका आकलन करना असंभव है । इसके अतिरिक्त, 850 डालर प्रति मी० टन की आरोपित कीमत तथ उस उत्पाद के ब्यौरे भी हमें उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं जिन पर कीमतें आधारित हैं । यह अनुरोध किया जाता है कि जब तक ऐसे आंकड़े प्रकट नहीं किए जाते हैं तब तक हमारे लिए अपने बचाव के संबंध में कोई पर्याप्त अथवा यथार्थपूर्ण निवेदन करना संभव नहीं है ।

- (x) इसके अलावा, प्रारम्भिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन 103.3% बनता है। हम इस आशय के विचार का विरोध नहीं कर सके कि हमारे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए क्या निर्यात कीमत ध्यान में रखी गई है। यदि यह वही निर्यात कीमत है जिसका याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है अर्थात् 850 डालर प्रति मी० टन, तो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजकों का ध्यान में रखते हुए यह स्पष्टतः भ्रांतिपूर्ण है।
- (xi) हमारे इस तर्क के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना कि घरेलू बाजार में कीमत निर्यात कीमत से तुलनीय है जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का प्रस्तुत घरेलू कीमत संबंधी बीजकों से स्पष्ट होता है, अनुरोध है कि सामान्य मूल्य निकालने के लिए इस पर ही विचार किया जाए न कि याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों पर।
- (xii) प्राधिकारी ने घरेलू बाजार के लिए उपलब्ध कराई गई कीमत को अस्वीकृत कर दिया है। तथापि, इसे अस्वीकार करने का आधार यह प्रतीत होता है कि उत्पादन की लागत के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और इसलिए सौदे व्यापार के सामान्य दौर में नहीं हुए हैं। यह आश्चर्यपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध कराई गई कीमत को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है।

प्रकटन विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- (i) एसबीआर के संबंध में पहले की कार्रवाई में हमें इसी उत्पाद की जांच के अधीन रखा गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज और आंकड़ें पहले ही हमने प्रस्तुत कर दिए हैं।
- (ii) उस समय के जांच परिणामों में यह सफाया दिया गया था कि हमारी निर्यात कीमत से घरेलू उद्योग का कोई क्षति नहीं हुई है।
- (iii) हम यह समझने में असफल हैं कि घरेलू बाजार और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से तुलनीय कीमत पर कॉफी मात्राओं का निर्यात किए जाने पर इस बार जांच परिणाम भिन्न क्यों हैं।
- (iv) हम हमेशा सहयोग दिया है और प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सभी आंकड़ें प्रस्तुत किए हैं।

(घ) मै0 फर्मा कैमिकजना डोरी एस0ए0, पोलैंड द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- (i) याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि पोलिश निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोध अपूर्ण और अपर्याप्त होने के कारण अस्वीकार होने चाहिए। इस संदर्भ में, यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने शायद डब्ल्यूटीओ करार के विशिष्ट प्रावधानों अनुबंध-॥ के पैरा-5 और 6 की अपनी सुविधानुसार व्याख्या कर ली है, जिसे सुनवाई के दौरान पढ़ा गया था। हमने अपने दावे के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी सर्वोत्तम समझ और सामर्थ्य के साथ निर्यातक प्रश्नावली में यथा अपेक्षित समस्त सूचना प्रस्तुत की थी। हम अपनी इस स्थिति को दोहराते हैं और आगे किसी अन्य सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी प्रकार का सहयोग देंगे जो कि भारतीय नियमों और डब्ल्यूटीओ प्रावधानों के तहत अब अथवा सत्यापन दौर की अवधि के दौरान आवश्यक होगी। डब्ल्यूटीओ करार के विशिष्ट प्रावधानों (अनुबंध-॥ के पैरा 5 और 6) को नीचे पुनर्उद्धृत किया जा रहा है:-

" 5. भले ही उपलब्ध कराई गई सूचना सभी प्रकार से अभीष्ट न हो फिर भी प्राधिकारियों को इसकी अवहेलना करना उचित नहीं होगा, बशर्ते कि हितबद्ध पार्टी ने अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार कार्रवाई की हो।

6. यदि साक्ष्य अथवा सूचना का स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे सप्लाई करने वाली पार्टी को उसके बारे में उसके कारणों सहित सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें एक उचित समयावधि के भीतर आगे और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए जिसमें जांच की समय-सीमा का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि दिए गए स्पष्टीकरणों का प्राधिकारी संतोषजनक नहीं मानते हैं तो ऐसे साक्ष्यों या सूचना को रद्द करने के कारण भी किसी प्रकाशित निष्कर्षों में दिए जाने चाहिए।"

- (ii) यह खेदजनक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय (हलदोर टोप्सो मामला) के निर्णय का उल्लेख संदर्भ से पूरी तरह हटकर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इस संदर्भ में था कि इस विशेष मामले में निर्यातक ने एक उपयुक्त तीसरे देश का संबंधित कंटेलिस्ट की निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रकट नहीं करने का प्राथमिकता दी थी जबकि ये ब्यौरे प्रतिवादी के पास उपलब्ध थे। इसके अलावा सूचना नहीं प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारणों

को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं समझा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख और विनिश्चय आधार इस मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सारी सूचना निर्यातक ने अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार प्रस्तुत की है और निर्यातक कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करने का भी इच्छुक है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस मामले में जांच-परिणामों के लिए आवश्यक समझा जाए।

(iii) लिखित अनुरोधों के पृष्ठ 9 पर हमें निर्यातकों द्वारा दी जाने वाली सूचना के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का देखकर आश्चर्य हुआ। यदि कोई विशेष ग्रेड का निर्यात नहीं होता है तो उस उत्पाद पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। याचिकाकर्ताओं की यह स्वीकृति कि "निर्दिष्ट प्राधिकारी को अब उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना की उपयुक्तता का निर्धारण करने से वंचित होना पड़ा है" बिना किसी तार्किक आधार के है। ऐसे विवरण केवल माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को भ्रमित करने और दबाव डालने के लिए दिए गए हैं, जिसे हम आदरपूर्वक निवेदन करते हैं कि इन्हें अनदेखा कर दिया जाना चाहिए।

(iv) याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि निर्यातकों को दूसरा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चुनिन्दा सहयोग के लिए बानस के समान होगा। आगे यह भी कहा गया है कि स्थान पर जांच करने के पश्चात् भी स्थिति का समाधान नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थान पर जांच कर उद्देश्य सूचना एकत्र करना नहीं है। डब्ल्यूटीओ करार के अनुबंध-1 पर भरोसा किया जा सकता है। इस संबंध में इस करार के अनुबंध-1 के संबंधित प्रावधानों को पुनर्उद्घृत करना चाहेंगे:-

"...स्थान पर जांच का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध कराई गई सूचना को सत्यापित करना अथवा और ब्यौरे प्राप्त करना है.....

यह अनुबंध आगे यह भी उल्लेख करता है कि:-

... दौरे पर जाने से पूर्व यह आम प्रथा होनी चाहिए कि संबंधित फर्मों को सत्यापित किए जाने वाली सूचना के सामान्य स्वरूप के बारे में और आगे प्राप्त की जाने वाली आवश्यक सूचना के बारे में सलाह दी जाए। यद्यपि प्राप्त की गई सूचना के संदर्भ में और ब्यौरे मंजूर कराने के लिए मौक पर किए जाने वाले अनुरोध भी इसमें शामिल होने चाहिए।

करार का अनुबंध-॥ निम्नानुसार उल्लेख करता है:-

" 5. भले ही उपलब्ध कराई गई सूचना सभी प्रकार से अभीष्ट न हो फिर भी प्राधिकारियों को इसकी अवहेलना करना उचित नहीं होगा, बशर्ते कि हितबद्ध पार्टी न अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार कार्रवाई की हो।

6. यदि साक्ष्य अथवा सूचना को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे सप्लाई करने वाली पार्टी का उसके बारे में उसके कारणों सहित सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें एक उचित समयावधि के भीतर आगे और स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए जिसमें जांच की समय-सीमा का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि दिए गए स्पष्टीकरणों का प्राधिकारी संतोषजनक नहीं मानते हैं तो ऐसे साक्ष्य या सूचना को रद्द करने के कारण भी किसी प्रकाशित निष्कर्षों में दिए जाने चाहिए।"

(v) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डब्ल्यूटीओ प्रावधानों ने बिना किसी शक के यह सिद्ध कर दिया है कि तथा-कथित कमियों के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(vi) याचिकाकर्ताओं ने अनुमान के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों को सही प्रकार से चुना है लेकिन यह स्वीकार करते हुए याचिका में अगोपनीय अंशों के पैरा-॥॥ में उनके द्वारा किए गए व्यय के आधार पर "सभी अन्य लागतों" के बारे में अनुमान लगाकर ईयू और पोलैंड में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में अत्यन्त विफल रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जांच शुरुआत के समय भी निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना पारिक्त और वैध रूप से अपर्याप्त थी और इस आधार पर कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती थी। हम आदरपूर्वक यह भी अनुरोध करते हैं कि जांच शुरुआत के समय यह त्रुटि असाध्य है और किसी बाद की स्थिति में इसे सुधारा नहीं जा सकता। हम ग्वाटे माला-मैक्सिको सीमेंट मामले पर भरोसा करते हैं, जिसका उल्लेख हमारे लिखित अनुरोधों में पर्याप्त रूप से किया गया है और संक्षिप्तता के कारण

इसे दोहराया नहीं जा रहा है। सार्वजनिक सुनवाई के समय दिए गए अन्य तर्कों को घरेलू उद्योग द्वारा उठाया नहीं गया है।

प्रकटन विवरण के जवाब में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- (i) हमारे दिनांक 26.11.2001 के जिस पत्र में सामान्य मूल्य के ब्यौरों के लिए अनुरोध किया गया था, उसके जवाब में, चूंकि हमें महानिदेशालय से कोई पत्र नहीं मिला है, इसलिए हम इस समय अन्य मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दोहराया गया है कि प्राधिकारी कृपया हमें वे ब्यौरे उपलब्ध कराएं, जोकि हमारे पहल पत्र में अपेक्षित हैं।
 - (ii) विस्तृत प्रकटन विवरण प्राकृतिक न्याय के सद्वांता और साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ के दिशानिर्देशों के भी अनुरूप होगा।
 - (iii) हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि प्रकटन विवरण का प्रभावी ढंग से जवाब दे सकें और यह उल्लेख करना चाहेंगे कि जबकि प्रकटन विवरण में जांच की शुरुआत के समय सूचना की गोपनीयता, पर्याप्तता और स्पष्टता के मुद्दों तथा कुछ जरूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मुद्दों पर कुछ तर्कों का उल्लेख किया गया है फिर भी प्रकटन विवरण में इनका समाधान नहीं किया गया है।
- (ड) **मै0 आल इंडिया फंडेशन ऑफ रंबड़ फुटवियर मैन्यूफैक्चर्स तथा मै0 पैरागोन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-**
- (i) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में पोलिश निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछेक सौदों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि घरेलू बाजार में कुछेक ग्राहकों की बिक्री उत्पादन की लागत से कम है जैसाकि उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा किया गया है और इस प्रकार यह व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है।
 - (ii) आदरपूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि क्या उत्पादन की लागत से कम पर विशेष सौदे दो-स्तरीय जांच के अधीन हैं जैसाकि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 में निर्धारित किया गया है।
 - (iii) इस पहलू पर हाल ही में मै0 थाई एक्रिलिक फाइबर कं0 लि0, बनाम वित्त मंत्रालय, निर्दिष्ट प्राधिकारी (2001(75) ईसीसी 197 (ट्रि0)) के मामले में माननीय सीगेट द्वारा भी विचार किया गया था। माननीय सीगेट ने उल्लेख किया है:-

"अनुबंध-1 की धारा (2) में विहित प्रावधानों के आशय को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उन सभी बिक्रियों को अस्वीकार करके स्पष्ट गलती की थी, जो बिक्रियां जांच अवधि में प्रति इकाई उत्पादन लागत से कम कीमतों पर की गई थीं। केवल उन बिक्रियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था जो संबंधित समय में प्रति इकाई उत्पादन लागत से कम कीमतों पर की गई थीं जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हुई हैं। इस पर उप-धारा (1) और (2) में विहित प्रावधान लागू होने चाहिए थे। इसे लागू करते हुए भी इस बात की जांच की जानी चाहिए थी कि क्या ऐसी बिक्रियां उचित अवधि के दौरान, जो छः महीने से कम न हो, की गई थीं और क्या ऐसी बिक्रियां काफी मात्रा में हुई थी जो कुल मात्रा का 20% से कम न हो।

- (iv) आदरपूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ऊपर उल्लिखित यह दा स्तरीय जांच अवश्य की जानी चाहिए। हम आशा हैं कि अगर पोलैंड के निर्यातक के मामले में यह स्तरीय जांच लागू की जाए तो कोई पाटन मार्जिन नहीं होगा।
- (v) इसके अतिरिक्त, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल घरेलू बिक्री के कारण हुए खर्चों के लिए किए गए कुछेक समायोजन अस्वीकार कर दिए हैं। आदरपूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि पोलैंड के निर्यातक ने गोपनीय आधार पर दिए गए दस्तावेजों के साथ समायोजन को सिद्ध किया है। तदनुसार, आदरपूर्वक यह भी अनुरोध किया जाता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया उस पूरी तरह से लागू करें।

प्रकटन विवरण के जवाब में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

- (i) मै0 बेनिक रबड, इंडस्ट्रीज ने उल्लेख किया है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण करने से पहले कुछेक आधारों पर पोलिश निर्यातकों द्वारा किए गए कुछेक सौदों को अस्वीकार किए जाने के मामले की पाटनरोधी नियमों के अनुसार उत्पादन की लागत के संबंध में गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता है। निर्यातकों द्वारा की गई घरेलू बिक्री के लिए किए गए समायोजनों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए दा स्तरीय जांच की जानी चाहिए और उन्हें हिसाब में भी रखा जाना चाहिए।

- (ii) मै0 आल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और स्मॉल स्केल रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा मै0 न्यू इंडिया वर्क्स प्रा0 लि0 ने भी मै0 बेनिक रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों को दोहराया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

2(क) मै0 फर्मा कैमिकजना डोरी एसए, पोलैंड

(i) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी ने मै0 फर्मा कैमिकजना डोरी एसए, पोलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के जवाब में, जिसमें सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के बारे में एक गोपनीय प्रकटन निर्यातक को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें विभिन्न लागत तत्वों को आधार और प्रक्रिया का वर्णन किया गया था, निर्यातक ने उल्लेख किया था कि प्रकटन विवरण अस्पष्ट है और उसने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें विस्तृत गणना और लागत संघटक उपलब्ध कराए जाएं। प्राधिकारी ने निर्यातक के निवेदन को ध्यान में रखते हुए महानिदेशालय के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क करने की अनुमति प्रदान की। निर्यातक के प्रतिनिधि न महानिदेशालय के साथ सम्पर्क किया जिसमें यह दोहराया गया था कि उत्पादन लागत की गणना की विस्तृत पद्धति और आधार पहले ही प्रकटन पत्र में दिया गया है। इस संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी नियमों और महानिदेशालय की मानक पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना के लिए विस्तृत प्रणाली और आधार गोपनीय प्रकटन पत्र में दिया गया है, जो कि वास्तव में स्वयं निर्यातक द्वारा सत्यापन टीम का उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर है और जिसका उल्लेख निर्यातक का जारी किए गए गोपनीय प्रकटन विवरण में स्पष्ट रूप से किया गया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली का जवाब निर्यातक के मूल रिकार्ड से मेल नहीं खाता है और इसलिए मै0 फर्मा कैमिकजना डोरी एसए द्वारा स्थापित सत्यापन के समय सत्यापन टीम का उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का संदर्भित किया गया है और सत्यापन टीम का उपलब्ध कराए गए इन आंकड़ों के आधार पर जांच अवधि में संबद्ध वस्तु (कईआर 1904 ग्रड) के उत्पादन की लागत ₹ 100/मी0टन बैठती है। उत्पादन की यह लागत ग्रड कईआर 1904 के लिए जांच की अवधि में भारत औरसत घरेलू बिक्री कीमतों से अधिक है। इसलिए प्राधिकारी न जांच की अवधि में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमतों को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि ये पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-

के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हुई हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री सौदे लागत वसूल करने में भी सफल नहीं रहे हैं जैसाकि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 में दर्शाया गया है और इसलिए वसूली टैस्ट, जैसाकि निर्यातक द्वारा तर्क दिया गया है अनिवार्य नहीं है। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का परिकलन उत्पादन की लागत के ब्यूरो के आधार पर किया है जोकि पाटनरोधी नियमों के अनुसार जांच की अवधि में सम्बद्ध वस्तु के लिए सत्यापन टीम को उपलब्ध कराए गए थे।

जांच अवधि में सम्बद्ध वस्तु के लिए भारत और सत आमत सामान्य मूल्य ... डालर/मी.टन बनता है।

(ii) निर्यात कीमत

जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक न जांच अवधि में सम्बद्ध वस्तु के लिए भारत को भारत और सत सीआईएफ कीमत उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक न स्वदेशी भाड़े, समुद्री भाड़ा, पैकिंग, कमीशन और वीएटी के लिए ... , ... , ... और ... डालर/मी.टन की सीमा तक समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सत्यापन टीम द्वारा यथा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर इन समायोजनों के लिए विचार किया है। परिवहन लागत के कुल मूल्य, जिसमें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और अन्य पत्तन व्यय शामिल हैं, पर समायोजन के रूप में विचार किया है, जैसाकि सत्यापन टीम को उपलब्ध कराया गया था। जहाँ तक वीएटी के संबंध में समायोजनों का संबंध है, यह नोट किया गया है कि निर्यातक न इस समायोजन का दावा ... डालर/मी.टन की सीमा तक किया है। सत्यापन के दौरान निर्यातक द्वारा सत्यापन टीम को सूचित किया गया था कि वीएटी का दावा केवल निर्यात उत्पादन में लगी विभिन्न निविष्टियों के लिए किए गए भुगतान के अनुसार वास्तविक आधार पर किया गया है। इसलिए प्राधिकारी ने वीएटी की वापसी के लिए ... डालर/मी.टन की सीमा तक समायोजन की अनुमति दी है।

भारत और सत कारखानागत निर्यात कीमत ... डालर/मी.टन बैठती है।

(ख) पोलैंड के अन्य गैर-सहयोगी निर्यातक/उत्पादक

(i) सामान्य मूल्य

जहाँ तक 10 फर्मा कैमिकजना डारी, एसए, पोलैंड के अलावा गैर-सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों का संबंध है, प्राधिकारी ने जांच अवधि में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य की गणना पोलैंड में सम्बद्ध वस्तु के लिए उत्पादन लागत आंकड़ा के आधार पर की है।

गैर-सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य डालर/मी०टन मानी गई है ।

(ii) निर्यात कीमत

जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है, प्राधिकारी ने जांच अवधि में भारत को पोलैंड से सबद्ध वस्तु की न्यूनतम निर्यात बिक्री कीमत पर विचार किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों तथा मै० फर्मी कैमिकजना डौरी एसए, पोलैंड द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर समायोजन की अनुमति दी गई है । ये समायोजन हैं :- समुद्री भाड़ा, स्वदेशी भाड़ा, पत्तन प्रभार, कमीशन और समुद्री बीमा ।

भारत औसत कारखानागत निर्यात कीमत डालर/मी०टन मानी गई है ।

(ग) यूरोपीय संघ (ईयू) का क्षेत्र

मै० बेयर इंटरनेशनल एसए, स्विटजरलैंड और मै० बेयर इंटरनेशनल, फ्रांस (मै० बेयर)

(i) सामान्य मूल्य

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के मूल्यांकन के संबंध में घरेलू उद्योग और मै० बेयर इंटरनेशनल एसए, स्विटजरलैंड द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० बेयर द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणामों से पहले पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै० बेयर ने कुछेक अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराई है । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसमें काफी कमियां पाई गईं । प्राधिकारी ने मै० बेयर से उत्पादन की लागत और सूचना निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया । मै० बेयर द्वारा ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।

प्राधिकारी ने निर्यातक को जारी गोपनीय प्रकटन विवरण में उल्लेख किया है कि जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं कराई गई और उनके द्वारा की गई घरेलू बिक्रियों को व्यापार के सामान्य कारोबार में रखने में असमर्थता बताई है। जांच अवधि में संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन का आधार भी दर्शाया गया था। प्रकटन विवरण के उत्तर में निर्यातक ने यह सूचित किया है कि एसबीआर की पूर्ववर्ती जांच में उन्होंने सभी आंकड़े मुहैया कराए थे। तथापि, वर्तमान जांच अवधि में कोई उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं कराई गई।

जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत संबंधी विशिष्ट आंकड़ों के उपलब्ध न होने के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत से इतर तीसरे देशों के लिए निर्यात कीमतों को जैसाकि मै0 बेयर ने सूचित किया है, सामान्य मूल्य के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है और जैसाकि मै0 बेयर ने सूचित किया है घरेलू कीमतों को भी व्यापार के सामान्य कारोबार के रूप में नहीं लया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जैसाकि मै0 बेयर ने उपलब्ध कराया है घरेलू बिक्री कीमतों और कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत संबंधी सूचना के आधार पर भी जांच अवधि में संबद्ध वस्तु के पाटन की पुष्टि होती है। प्राधिकारी इस प्रयोजन से यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार प्राधिकारी के पास नियम 6(8) के अनुसार मै0 बेयर के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि उक्त निर्धारण लागत संबंधी विभिन्न तत्वों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची सामग्रियों इत्यादि के आंकड़ों और याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों से यथाप्राप्त अन्य मानकीकृत लागत संबंधी तत्वों के आधार पर किया जाए।

निर्यातक मै0 बेयर इंटरनेशनल एसए., स्विट्जरलैंड और उत्पादक मै0 बेयर इंटरनेशनल, फ्रांस के लिए भारित औसत परिकलित सामान्य मूल्य ***डालर/मी0 टन निकलता है।

ii. निर्यात कीमत

जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है प्राधिकारी ने जांच अवधि में संबद्ध वस्तु (केएस 260) के लिए भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है जैसाकि निर्यातक ने सूचित किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, विदेशी बीमा, रखरखाव, बिक्री कर और ऋण के लिए समायोजनों की अनुमति दी है। जांच अवधि में संबद्ध वस्तु के लिए भारित औसत कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत *** डालर/मी0टन मानी गई है।

(घ) मै0 एनीकेम इलास्टोमेरी एसआरआई इटली (मै0 एनीकेम): प्राधिकारी मै0 एनीकेम, इटली द्वारा निर्यातों की कम मात्रा के बारे में उनके द्वारा किए गए अनुरोधों और प्रकटन विवरण के बाद किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। चूंकि यह जांच एक प्रदेश के रूप में यूरोपीय संघ के लिए है और यह कि ईयू से हुए सकल आयात नियमानुसार न्यूनतम से अधिक हैं इसलिए एनीकेम को जांच के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 एनीकेम ने सूचित किया है कि उनके द्वारा वर्ष 2000 और 2001 के दौरान संबद्ध वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं की गई है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में कोई निर्यात नहीं किए जाने की स्थिति में निर्यातक को पाटनरोधी नियमों के नियम 22 के अधीन रखा जाएगा। निर्यातक नियम 22 के अधीन अनुरोध कर सकते हैं हालांकि नियम 22 के तहत जांच पूरी होने तक निर्यातक को मै0 बेयर इंटरनेशनल से इतर श्रेणी के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों के साथ माना जाएगा जैसा कि नीचे बतलाया गया है।

(ड.) मै0 बेयर इंटरनेशनल एस ए, स्विट्जरलैंड को छोड़कर अन्य असहयोगी निर्यातक

i. सामान्य मूल्य:

प्राधिकारी ने निर्यातकों/आयातकों के संबंध में सामान्य मूल्य के लिए उसी पद्धति को अपनाया है जैसाकि मै0 बेयर के मामले में किया गया है अर्थात् नियम 6(8) के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर लागत संबंधी विभिन्न तत्वों अर्थात् कच्ची सामग्री इत्यादि से संबंधित आंकड़ों और याचिकाकर्त्ताओं के आंकड़ों से उपलब्ध हुए विधिवत मानकीकृत लागत संबंधी अन्य तत्वों से संबंधित आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

भारित औसत सामान्य मूल्य *** डालर/मी0टन माना गया है।

ii. निर्यात कीमत:

जहां तक निर्यात कीमत का संबंध है प्राधिकारी ने जांच अवधि में यूरोपीय संघ से न्यूनतम निर्यात कीमत पर विचार किया है जिसमें भारत स्थित एजेंट को दिया गया कमीशन के लिए तथा मै0 बेयर द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार समुचित समायोजन किया गया है।

कारखाना द्वारा पर भारित औसत निर्यात कीमत ***डालर/मी0 टन मानी गई है।

5. पाटन-सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार व्यवस्था है:

* पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वारा स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी जो अंतर तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर समुचित छूट दी जाएगी ; अन्तर में शामिल हैं - बिक्री की शर्तें, कराधान व्यापार के स्तर, मात्राएं, वास्तविक विशेषताएं तथा कोई अन्य अन्तर जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना जांच अवधि में कारखाना द्वारा पर भारत औसत निर्यात कीमत के साथ की है।

जांच अवधि में संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य (डालर/मी0टन)	निर्यात कीमत (डालर/मी0टन)	पाटन मार्जिन (%)
यूरोपीय संघ क्षेत्र			
मै0 बेयर इंटरनेशनल एसए स्विट्जरलैंड और मै0 बेयर इंटरनेशनल फ्रांस	****	****	87.2
यूरोपीय संघ क्षेत्र के अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	107.48
पोलैंड			
मै0 फर्मा कैमिक्जना डोरी एसए	****	****	26.7
पोलैंड के अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	****	****	55.68

उपरोक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक हैं ।

छ.1. क्षति और कारणात्मक संबंध

उपरोक्त नियम 11, अनुबंध- II के अंतर्गत क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव, ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभावों समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा । मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होती ।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों के अनुबंध- II (iv) के अनुसार उत्पादन क्षमता, उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन इत्यादि जैसे संकेतकों पर विचार किया है जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं ।

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

(क) मै0 एपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै0 एपकोटेक्स लैटिसेज लिमिटेड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

- i. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा यथा आकलित वर्ष 1999-2000 में देश में एचएसआर की मांग जो 30601मी0 टन के करीब बतलायी गई है वह रबड़ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार गलत है । यह सूचित किया गया है कि 30601 मी0 टन के आंकड़े में सभी प्रकार की सिंथेटिक रबड़ अर्थात् एनबीआर, ईबीए इत्यादि शामिल हैं । हमारे मूल्यांकन के अनुसार देश में एचएसआर की मांग 17000 मी0 टन के करीब है ।
- ii. हालांकि प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले ही इस बात की पुष्टि होती है कि संबद्ध देश/क्षेत्र के निर्यातक भारतीय बाजार में एचएसआर का पाटन कर रहे हैं, फिर भी यह

कहा गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है। हम यह उल्लेख करते हैं कि घरेलू उद्योग को पूर्व में भी वास्तविक क्षति अनेक ऐसे देशों से पाटन के परिणामस्वरूप हुई है जिनपर कि इस समय पाटनरोधी शुल्क लगता है। घरेलू उद्योग को इतनी गंभीर क्षति हुई थी कि उत्पादकों में से एक उत्पादक मै0 सिन्थेटिक्स एंड कैमिकल्स को अपना उत्पादन रोक देना पड़ा था। उस कंपनी द्वारा दायर याचिका के परिणामस्वरूप पूर्व में एसबीआर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के अपने कड़े विरोध और तर्कों के होते हुए भी मै0 सिन्थेटिक्स एंड कैमिकल्स द्वारा उत्पादित सामानों में ग्राहकों द्वारा जो रुचि दिखाई जा रही है उसे याचिकाकर्त्ताओं ने बड़े रोचक ढंग से नोट किया है। इसके अलावा कुछेक देशों से एसबीआर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति को देखते हुए घरेलू उद्योग से हुई क्षति को मौजूदा शुल्कों और उनके प्रभाव के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है।

- iii. मौखिक सुनवाई के दौरान निर्यातक/आयातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एनबीआर की पाटनरोधी जांच में घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि एनबीआर उसकी कम लाभप्रदता का कारण है जबकि घरेलू उद्योग अब यह दावा कर रहा है कि उसकी कम लाभप्रदता का कारण एचएसआर है।
- iv. हमारा अनुरोध है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए सत्यापित आंकड़ों/सूचना के आधार पर अनेक जांच की हैं। विभिन्न जांच विभिन्न जांच-अवधि से जुड़ी हैं और यह मान लेना उचित नहीं रहेगा कि कंपनी का वित्तीय निष्पादन विभिन्न अवधियों के दौरान समान रहा है। कंपनी द्वारा विभिन्न जांचों के लिए प्रस्तुत की गई सूचना सत्य सटीक और लेखों के अनुसार है। हम और कोई ऐसी सूचना देने के लिए तैयार हैं जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मानते हैं।
- v. पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति होने का खतरा निम्नलिखित मानकों से स्पष्ट है:-

- घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन संख्यी रूप से करना अपेक्षित है।

- इन दोनों देशों से आयातों में निरपेक्ष रूप में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पोलैण्ड से आयातों की वास्तविक मात्रा बढ़कर लगभग 1000मी० टन तक हो गई है जबकि 1999 तक कोई आयात नहीं होता था।
- संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि भारत में इस उत्पाद की मांग की तुलना में हुई है।
- भारत में उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- भारत में इस उत्पाद की मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटा है।
- संबद्ध देशों से पाटित आयातों में बहुत कम अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि भविष्य में आयातों में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।
- संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।
- संबद्ध देश/क्षेत्र में मुक्त रूप से बिक्री योग्य पर्याप्त क्षमता है। यह ज्ञात हुआ है कि पोलैण्ड की कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में एचएसआर के अपने उत्पादन व बिक्री को कम कर दिया है। इसके अलावा कंपनी के पास पर्याप्त बेशी क्षमता है।
- संबद्ध देश/क्षेत्र में मौजूद क्षमता संबद्ध देश/क्षेत्र में एचएसआर की मांग से काफी अधिक है।
- निर्यात कीमत घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती/कीमत ह्रास हुआ है।
- आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत कटौती हुई है। इस कीमत कटौती से घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर हो रहा है और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को बनाए रखने में कठिनाई हो रही है।
- घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि हुई है। उद्योग को अपने उत्पादन की इष्टतम लागत और निवेशों पर समुचित प्राप्ति से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- भारी कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के व्यापार के मार्जिन में पर्याप्त गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग के पास स्टॉक में बढ़ोत्तरी हुई है।

- उद्योग का क्षमता उपयोग इष्टतम से कम रहा है। दूसरे देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद उद्योग अपने संयंत्र का इष्टतम उपयोग नहीं कर सका।
- घरेलू उद्योग के कर्मचारी हतोत्साहित हुए हैं। बाजार में इस उत्पाद का पाटन जारी रहने के परिणामस्वरूप कंपनी अपने योग्य कर्मचारियों को रखने में कठिनाई महसूस कर रही है।
- घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में इस उत्पाद का पाटन जारी रहने के परिणामस्वरूप उन्नति करने में असमर्थ है। यह स्थिति उत्पाद की बढ़ती हुई मांग के बावजूद है।
- पूर्व में दूसरे देशों से और अब संबद्ध देश/प्रदेश से अत्यधिक पाटन व घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण एक विनिर्माता ने पहले ही बी आईएफआर को आवेदन दिया है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त सभी मानकों से अलग-अलग व संचयी रूप से यह प्रमाणित होता है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का गंभीर खतरा है। हमारा अनुरोध है कि अब पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की जरूरत है अन्यथा घरेलू उद्योग को अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं होगा।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

हम पूर्व में अग्रेषित अपने तर्कों पर भरोसा करते हैं जिसे संक्षिप्तता की दृष्टि से यहां नहीं ब्रुहशया जा रहा है। क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे पर हमारे विभिन्न तर्कों से यह प्रमाणित होता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

(ख) मै0 शर्मा एसोसिएट्स, नई दिल्ली ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

- i. अधिसूचना में क्षति संबंधी विश्लेषणों के ब्यौरे नहीं दिए गए हैं जिसके अभाव में हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि क्षति कैसे हुई।
- ii. उत्पादन संबंधी सूचना, घरेलू उद्योग के आंकड़े, सीबीईसी के आयातों का ब्यौरा, कच्ची सामग्री का अनुपात, घरेलू उत्पादकों व निर्यातकों की लागत बनाम बिक्री कीमतों को उपलब्ध कराया जाए।

(ग) मै0 बानिक रबड़, कलकत्ता ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

- i. एचएसआर की मांग व आपूर्ति के बीच अंतर है और यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचएसआर की गुणवत्ता विश्व बाजार के वैश्वीकरण के समय रबड़ उत्पादों के विनिर्माण

के लिए मानकों के स्तर की नहीं है। इसलिए घरेलू उद्योग के पास आयातित स्रोतों से प्राप्त बेहतर गुणवत्ता की एचएसआर पर निर्भर करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) मै0 आल इंडिया फ़ैडरेशन ऑफ़ रबड़ फ़ुटवियर मैनुफ़ैक्चरर्स और मै0 पारागोन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. यह उल्लेखनीय है कि इस विशेष मामले में प्रारंभिक जांच परिणाम में प्रयुक्त मूल सूचना को प्रकट नहीं किया गया है जैसाकि नियम 12 या पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत प्रावधान है। यह प्रारंभिक जांच परिणाम में भी क्षति विश्लेषण के ब्यौरे देने की पहले से चली आ रही व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण रूप से अनदेखी करना है जैसाकि सिंथेटिक रबड़ के पूर्व के मामलों में भी किया गया था। आप इसे स्वीकार करेंगे कि इससे घरेलू उपयोगिता उद्योग किसी प्रकार की टिप्पणी करने से वंचित हो गया है।
- ii. अतः यह नम्र निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुबंध II (iv)में यथाउल्लिखित क्षति के सभी पहलुओं पर अवश्य विचार करना चाहिए।
- iii. वस्तुतः बेड लिनेन के मामले में डब्ल्यू टी ओ पेनल ने जिसका भारत एक पार्टी था, इस पहलू पर विचार किया था।
- iv. इस प्रावधान को विशेष रूप से भारतीय पाटनरोधी नियमों में पूर्णतः शामिल किया गया है। अनुबंध II (iv)में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ' घरेलू उद्योग की चिंताओं पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों का एक मूल्यांकन करना और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों को मूल्यांकन करना शामिल होगा, इसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्राप्ति या क्षमता का उपयोग: कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा: नकद प्रवाह, सामान, रोजगार, मजदूरी वृद्धि, पूंजीगत निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है।
- v. यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता एक बहु-उत्पाद कंपनी है जो एचएसआर (एसबीआर1900) सहित सिंथेटिक रबड़ की विभिन्न किस्मों का विनिर्माण करते हैं। यह

नोट किया जाए कि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता एसबीआर के 1500 या 1700 सीरीज का विनिर्माण नहीं करते हैं ।

- vi. इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि मै0 गुजरात एपार/एपार ने सिंथेटिक रबड़ की अन्य किस्मों अर्थात् एनबीआर पर अनेक पाटनरोधी मामले दायर किए हैं । स्पष्टतः मै0 एपार के संयंत्रों का उपयोग विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन के लिए अदल-बदल कर किया जा सकता है ।
- vii. पहला मामला जापान के विरुद्ध अक्टूबर, 1994 के आसपास दायर किया गया था ।
 - (i) एनबीआर से संबंधित दूसरा मामला पुनः कोरिया के विरुद्ध मार्च, 1995 के आसपास दायर किया गया ।
 - (ii) तीसरा मामला जनवरी, 1999 के आसपास ताइवान के विरुद्ध दायर किया गया था ।
- viii. एनबीआर 1 (जांच अवधि 1.4.1993 से 31.3.1994) में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ताओं को गैर-एनबीआर उत्पादों के उत्पादन का सहारा लेना पड़ा था (जिसके लिए अन्यथा ऐसे संयंत्रों और प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं होती जैसाकि याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध है + एनबीआर के उत्पादन के लिए)..... यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1.4.94 तक एसबीआर संयंत्र मै0 एपार लिमिटेड (एक निजी लिमिटेड कंपनी) के पास था, 1.4.94 को मै0 एपार लिमिटेड का हस्तांतरण मै0 गुजरात एपार के हाथ कर दिया गया था ।

एनबीआर II में जांच अवधि 1 अक्टूबर, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक थी । इस समय तक एसबीआर की क्षमता को एकीकृत कर दिया गया था । इस मामले में भी प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिकाकर्ताओं को गैर-एनबीआर मर्दों के उत्पादन के लिए बाध्य होना पड़ा जिसे अन्यथा ऐसे संयंत्र और मशीनरी की जरूरत नहीं होती जैसाकि याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रकाशित वार्षिक लेखों में लाभ दर्ज किया था फिर भी यह गैर एनबीआर मर्दों की बिक्री के कारण है ।

- ix. एनबीआर III मामले जिसकी जांच अवधि 1 अप्रैल, 1998 से 31 दिसम्बर, 1998 तक की है। तीसरी बार में रिकार्ड लाभ और क्षमता उपयोग के बावजूद याचिकाकर्ता ने एक बार फिर इस आधार पर क्षति का दावा किया है कि सिंथेटिक रबड़ के कारोबार में हुआ लाभ और उच्च क्षमता उपयोग गैर-एनबीआर उत्पादों के कारण था।
- x. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मौजूदा मामले में मै0 एपार ने एक बार फिर 11600 मी0 टन की स्थापित क्षमता के साथ रिकार्ड क्षमता उपयोग और उत्पादन किया था ; वर्ष 1999-2000 में मै0 एपार ने 12203 मी0 टन सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन किया था।
- xi. एनबीआर II में मै0 गुजरात एपार/एपार ने यह भी अभिज्ञात किया है कि सिंथेटिक रबड़ के लिए कुल 11600 मी0 टन की स्थापित क्षमता में से उसकी पोलिमेर क्षमता 6250 मी0 टन थी। इस प्रकार, यह नोट करना आश्चर्य की बात है कि मै0 एपार के एक निदेशक ने सार्वजनिक सुनवाई में सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि सिंथेटिक रबड़ सहित एचएसआर (एनबीआर 1900)। यह उल्लेखनीय है कि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्ता एनबीआर के 1500 या 1700 सीबीज का विनिर्माण नहीं करते हैं। यह कहा गया है कि गोपनीयता प्रक्रिया का दुरुपयोग करके मै0 गुजरात एपार/एपार उनके द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की बार-बार मांग करते रहे हैं। अगर याचिका एनबीआर के लिए है तो उत्पादन पर रिकार्ड लाभ का श्रेय सिंथेटिक रबड़ की दूसरी किस्मों पर डाल दिया जाता है। इस मौजूदा मामले में भूमिका बदल गई है और अब क्षति एनबीआर से भिन्न रबड़ अर्थात् एचएसआर को हो रही है।
- xii. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रमाण पूर्णतः अपर्याप्त है और प्रत्येक मापदंड यह दर्शाता है कि निष्पादन में पहले से सुधार हुआ है।
- xiii. इस विशेष मामले के तथ्यगत आधार के तहत याचिकाकर्ताओं ने आयात की मात्रा, आयात कीमतों इत्यादि के बारे में अपर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षति और क्षति संबंधी खतरे के बारे में कुछेक दावे बिना किसी प्रमाण के किए गए थे। ये प्रथम दृष्टया स्पष्टतः और पूर्णतः अपर्याप्त हैं और इन्हें जांच शुरू करने या आगे जांच करने के उद्देश्य से

' पर्याप्त ' नहीं माना जा सकता है । इसके अलावा, हम यह अनुग्रहपूर्वक कहते हैं कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह जरूरी था कि वे जांच शुरू करने या आगे जांच करने के उद्देश्य से ' पर्याप्त ' नहीं माना जा सकता है । इसके अलावा, हम यह अनुग्रहपूर्वक कहते हैं कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह जरूरी था कि वे जांच शुरू करने से पहले के नियम 5(3) के अनुसार याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच करते । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत याचिका की इस असाध्य खामियों के कारण और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की पर्याप्तता और शुद्धता की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नहीं किए जाने के कारण हम अनुग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि इस जांच को अविलम्ब समाप्त कर दिया जाए ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में मै0 आल इंडिया रबर फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. संबद्ध मामले में पूरी कार्यवाई को बचाव के रूप में छुपाया गया है । घरेलू उद्योग समय-समय पर की गई हमारी पूछताछ के स्पष्ट उत्तर देने में असफल रहा है अर्थात् इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है कि एचएसआर की निकासी अध्याय 39 के अंतर्गत क्यों की जा रही थी ।
- ii. याचिकाकर्त्ताओं का यह तर्क कि एचएसआर की निकासी अध्याय 39 और 40 दोनों के तहत की जा सकती है अत्यन्त भ्रामक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।
- iii. जब सरकारी स्रोत अर्थात् डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़े उपलब्ध थे तब घरेलू उद्योग ने गौण स्रोतों के आंकड़ों पर भरोसा क्यों किया ।
- iv. याचिका में याचिकाकर्त्ताओं ने सूचित किया है कि एचएसआर का कुल उत्पादन 4996+2759 टन के बराबर है जबकि उसने अपने बाद के उत्तर में यह सूचित किया था कि वास्तविक मांग 18000 से 20000मी0 टन प्रतिवर्ष थी । तथापि दोनों घरेलू उत्पादकों की क्षमता को एक साथ जोड़ने पर 10000 से 12000 मी0 टन प्रति वर्ष से अधिक नहीं है ।

- v. हम याचिकाकर्त्ताओं के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि आयातों में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ आयात वर्ष 1998-99 में 11083 मी० टन से वस्तुतः घटकर वर्ष 1999-2000 में 7383 मी० टन रह गए हैं।

(ड) मै० फर्मा केमिकल्स जॉइन्ट एन्ड, पोलैण्ड ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. याचिकाकर्त्ताओं ने याचिका में उनके द्वारा दिए गए तर्कों को ही मात्र दोहराया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि तथाकथित क्षति के व्यौरों का उल्लेख सभी अलग-अलग आर्थिक और वित्तीय मानकों को हिसाब में लेते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, "क्षति के खतरे" संबंधी अपेक्षाएं मौजूदा मामले में पूरी नहीं होती हैं। इस बात में कि कथित पाटित आयातों से क्षति का खतरा है, मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए केवल दावे से अधिक कुछ भी नहीं है। यह भी कहा गया है कि मौखिक सुनवाई और लिखित अनुरोधों में निर्यातक/आयातकों और उपयोक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों का याचिकाकर्त्ताओं ने कोई खंडन नहीं किया है।
 - ii. हम राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे बेड लिनेन मामले में नियमों और उसमें भारत द्वारा अपनाई गई स्थिति का अनुपालन करें।
 - iii. हम माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे विभिन्न प्रकार के रबड़ के लिए याचिकाकर्त्ताओं के विभिन्न संयंत्रों की निश्चित उत्पादन क्षमताओं को हिसाब में लें। मै० एपार द्वारा उत्पादन किए जा रहे विभिन्न सिन्थेटिक की क्षमताओं के बारे में हमारे अनुरोध पर घरेलू उद्योग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। हम इस पहलू को सूचना के गोपनीयता और पर्याप्तता एवं शुद्धता से संबंधित भाग में अलग से शामिल कर रहे हैं।
- (घ) मै० स्माल स्केल रबड़ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली रबड़ वर्क्स प्रा० लिमि०, मै० बनिक् रबड़ इंडस्ट्रीज और आल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-
- i. घरेलू उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उत्पादकों को कोई घाटा नहीं हुआ है और स्टॉक में यदि कोई वृद्धि हुई है तो वह उनके उत्पाद की खराब गुणवत्ता के कारण हुई है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता और अपनी बिक्री कीमतों में भी वृद्धि की है।

प्रकटन विवरण के उत्तर में नई दिल्ली रबड़ वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड और मै० बनिक रबड़ इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं—

- i. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है खासकर घरेलू उद्योग द्वारा खपत की गई कच्ची सामग्री की निविष्टि-लागत में उतार-चढ़ाव पर विचार करने के बाद अगर एक उचित और विस्तृत जांच की जाती है। यहां इस बात का पुनः उल्लेख किया जा सकता है कि घरेलू उत्पादकों में से एक मै० एपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कम निविष्टि लागत के कारण भारी लाभ कमाया है (कृपया इसके लिए दिनांक 7.11.2001 के दि इकोनोमिक टाइम्स, कोलकाता का संदर्भ लें)।
 - ii. घरेलू उद्योग द्वारा पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादन किए गए उत्पाद की लाभकारी बिक्री के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता का खामियाजा उपभोक्ता उद्योग को भुगतने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि उसकी अक्षमता के कारण हुई थी इसलिए इसकी अनदेखी की जानी चाहिए और इसलिए उसकी उत्पादन लागत की गणना के समय इसे हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। प्राधिकारी को एक अथवा दो घरेलू उद्योग द्वारा लाभ कमाने वाले यंत्र के रूप में अपना इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो लाखों कामगारों को रोजगार देनेवाली लघु उपभोक्ता इकाईयों की तुलना में कुल 1000 कामगारों को रोजगार देते हैं। स्पष्टतः इसके लिए हमारे जैसे एक विकासशील देश के मामले में अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि हमेशा बेरोजगारी, गरीबी और अन्य सामाजिक समस्याओं से जूझता रहता है। यहां भी हम अनुग्रहपूर्वक यह अनुरोध करना चाहेंगे कि देश के रबड़ उपभोक्ता उद्योग को प्रभावित करने वाला कोई अनुचित निर्णय देश के ऐसे प्राकृतिक रबड़ के उपजकर्ताओं की स्थिति पर भी प्रभाव डालेगा जिनके हितों की देखभाल को सरकार हमेशा तरजीह देती है।
2. प्राधिकारी द्वारा जांच
- प्राधिकारी उपरोक्त अनुरोधों, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और आयातों के आंकड़ों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित मत व्यक्त करते हैं :

- i. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तु का आयात डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार 3487मी0 टन है और गौण स्रोत पॉलीमर्स प्लास्टिक रबड़ (पीपीआर) व्यापार पत्रिका के अनुसार यह जांच अवधि में 4039 मी0 टन हैं । इन दोनों स्रोतों पर विचार करने के बाद गैर-संबद्ध देशों से अधिकतम आयात 5073 मी0 टन (डीजीसीआईएस का अध्याय 40 आयात आरपीपीआर का अध्याय 39 आयात) बैठता है । इस आंकड़े के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं ।
- ii. घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 1997-98 में 5490 मी0 टन से बढ़कर 1998-99 में 6532 मी. टन, 1999-2000 में 9224 मी. टन और आगे जांच अवधि में 7627 मी. टन (वार्षिक रूप से 10169 टन) हो गया ।
- iii. क्षमता उपयोग 1997-98 के 72.73 % से घटकर 1998-99 में 42.14 % , 1999-2000 में 59.5% हो गया और जांच अवधि में यह घटकर 57.13% हो गया ।
- iv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री वर्ष 1997-98 में 6109 मी0 टन थी जो 1998-99 में बढ़कर 7617मी0 टन, 1999-2000 में 8960मी0 टन और जांच अवधि में 8352 मी0 टन (वार्षिक रूप में 11136 मी0 टन) हो गई ।
- v. पोलैण्ड से आयात जो 1998-99 में शून्य मी0 टन थे, जांच अवधि में निरपेक्ष रूप में बढ़कर 1160 मी0 टन (वार्षिक रूप में 1546 मी0 टन) और यह यूरोपीय संघ क्षेत्र से इसी अवधि में 1152 मी0 टन से बढ़कर 1250 मी0 टन (वार्षिक रूप में 1667मी0 टन) हो गए । बाजार हिस्से के रूप में पोलैण्ड से आयात 1998-99 में 0 % से बढ़कर जांच

अवधि में 7.3 % हो गए जबकि यूरोपीय संघ क्षेत्र से ये इसी अवधि में 6.16 % से बढ़कर 7.9 % हो गए ।

कुल आयातों के अनुपात के रूप में पोलैण्ड से आयात जो 1998-99 में 0 % थे जांच अवधि में बढ़कर 15.5 % हो गए जबकि यूरोपीय संघ के क्षेत्र के मामले में यह हिस्सा इसी अवधि में 10.4 % से बढ़कर 16.7 % हो गया । आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से संदर्भित किए गए हैं और इनका तालमेल पीपीआर के आंकड़ों व निर्यातकों के उत्तर के साथ संभव स्तर तक बैठाया गया है ।

- vi. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 1998-99 में 40.7 % था जो बढ़कर 1999-2000 में 55.87 % और जांच अवधि में 52.74 % हो गया ।
- vii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 1997-98 और 1998-99 की तुलना में जांच अवधि में काफी गिरावट आई है ।
- viii. हालांकि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बिक्री कीमत में 1998-99 और 1999-2000 की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है लेकिन घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कम पहुंच कीमत के कारण गिरावट आई है और यह क्षति रहित कीमत से काफी कम रही है जिससे वित्तीय घाटा हुआ ।

2. प्राधिकारी ने क्षमता और क्षति विश्लेषण के मुद्दे पर विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा घरेलू उद्योग के लिए किए गए क्षति-विश्लेषण को भी नोट किया है । इस संबंध में प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण सर्वोत्तम खपत मानदंडों की बेंच मार्किंग करके और विभिन्न लागत संबंधी धृष्टकों का मानकीकरण करके तथा घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध संबद्ध वस्तुओं की समर्पित क्षमता पर विचार करके किया गया है । इसलिए इस संबंध में पाटित आयातों के कारण हुए कीमत ह्रास की

वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण जांच अवधि में केवल संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में किया गया है।

3. प्राधिकारी देश में एचआरएस की मांग से संबंधित विभिन्न तर्कों को नोट करते हैं। प्राधिकारी जांच अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस और पालीमर्स प्लास्टिक व्यापार पत्रिका जानकारी (पीपीआर) से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर घरेलू बिक्री और किए गए आयातों के आधार पर एचएसआर की मांग लगभग 18000 मी० टन निर्धारित करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अगर संबद्ध वस्तु के लिए पीपीआर के अध्याय 39 के आयात आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस के अध्याय 40 के आयात आंकड़ों पर विचार किया जाता है तो देश में मांग का सर्वोच्च स्तर लगभग 21000 मी० टन माना जा सकता है। इस मांग के आधार पर और उपलब्ध कुल क्षमता के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए वास्तविक उत्पादन के आधार पर मांग आपूर्ति में अंतर है। उपलब्ध क्षमता दर्शाती है कि इस मांग-आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सकता है अगर घरेलू उद्योग उच्चतर क्षमता प्राप्त कर लेता है। डीजीसीआईएंडएस से यथाप्राप्त पूर्ववर्ती वर्ष के आयात आंकड़ों और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ रही है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई कारक नहीं है। विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर भी प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग कोई बाधक कारक नहीं रहा है।

उपरोक्त आर्थिक कारक सामूहिक तथा संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि पाटित आयातों से भारतीय बाजार में घरेलू कीमतों में कमी बनी रही है। जिसके कारण क्षति रहित कीमत से कम निवल बिक्री प्राप्ति के द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँची है, जिससे वित्तीय घाटा हुआ है।

ज.1 भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

- (क) मै0 इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्यूफैक्चरर्स ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं -
 - (i) घरेलू उद्योग पाटनरोधी प्रणाली का अनुचित फायदा उठा रहा है और देश में निहित स्वार्थों द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर सकें।
 - (ii) सादर निवेदन है कि लोक हित एक ऐसा पहलू है जिसे माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए।
 - (iii) आगे यह अनुरोध है कि यह मानना पूर्णतः एकांगी है कि लोक हित के किसी विचार से पाटन की अनिवार्यतः अनदेखी कर दी जाएगी जो केवल अल्पावधि के लिए ही फायदेमंद है। अतः उपयोक्ता उद्योग पर इसके परिणाम का ध्यान रखे बगैर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
 - (iv) वास्तव में पाटनरोधी नियमों में यह अपेक्षित है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी उपभोक्ता उद्योग के हित को, खासकर नियम 6(5) को ध्यान में रखे।
 - (v) स्पष्टतः उपभोक्ताहित की उपेक्षा न की जाए।
 - (vi) विशेष मामले के तथ्यात्मक आधार के अनुसार घरेलू उद्योग निश्चित रूप से घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उपयोक्ता उद्योग ने इस बात की पुष्टि की है कि घरेलू उद्योग की क्वालिटी इतनी घटिया है कि इससे उनके स्लिपरो की ब्रांड में प्रभाव पड़ता है।
 - (vii) इसके अतिरिक्त, अंत्य उत्पाद रबड़ के स्लिपर हैं जिनकी मांग घरेलू बाजार में अत्यधिक उच्च पाटनरोधी

प्राधिकारी उपभोग करने वाली जनता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार कर सकते हैं।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं -

- (i) यह कि याचिकाकर्ताओं का एकमात्र प्रयोजन किसी न किसी बहाने से एच एस आर की कीमत में वृद्धि करना है। घरेलू उद्योग ने पिछले दो वर्षों में चार मौकों पर अपनी कीमतों में वृद्धि की है जो 60 रुपए प्रति किग्रा० से बढ़कर 88 रुपए प्रति किग्रा० तक हो गयी है।
- (ii) अपार इंडस्ट्रीज लि० तथा एपकोटैक्स उनके द्वारा उत्पादित एच एस आर के उचित कीमत पर मुहैया नहीं कर रहे हैं और वे किसी न किसी बहाने प्रायः कीमतों में वृद्धि करते रहते हैं जिससे स्थानीय रबड़ उद्योग की व्यवहार्यता पर चोट पहुँचती है। उनकी गुणवत्ता का स्तर भी कम है। उनकी आपूर्ति की स्थिति भी उतनी ही खराब है।

ख. मै० बानिक रबड़ इंडस्ट्रीज, कलकत्ता ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं -

- (i) मै० बानिक रबड़ इंडस्ट्रीज द्वारा यह भी संकेत दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क, उपयोक्ता उद्योग जो 4 लाख कामगारों को रोजगार देता है, के हितों को ध्यान में रखे बगैर लगाया गया है, यह न केवल विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है अपितु अधिकांशतः भी है।
- (ii) यह भी संकेत दिया गया है कि भारत में एच एस आर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार को हड़प रहे नेपाल, बंगलादेश, कोरिया तथा थाइलैंड के उत्पादों को अवसर मिला है।
- (iii) मै० बानिक रबड़ इंडस्ट्रीज ने संकेत दिया है कि रबड़ के विनिर्माता पाटनरोधी शुल्कों का गंभ उठा रहे हैं और उन्होंने पिछले तीन वर्षों में विभिन्न आधारों पर अपनी कीमतों में किया है। घरेलू उद्योग द्वारा जिन वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है वे अपेक्षित गे के अनुरूप भी नहीं हैं। मै० स्मॉल स्केल रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

ने भी गणरोक्त अनुरोधों का समर्थन किया है।

2. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी फुटवियर विनिर्माताओं पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव के बारे में उपयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह संकेत किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क से लघु इकाइयों में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गयी वस्तुओं की गुणवत्ता तथा मानक से संबंधित समस्याओं और देश में मांग आपूर्ति की असमान स्थिति के बारे में अनुरोध किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने यह भी तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग न संबद्ध वस्तु की कीमतों में वृद्धि की है। यह भी अनुरोध किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन तैयार उत्पादों के आयात होंगे जिसका उपयोक्ता उद्योग द्वारा किया जा रहा है और यह कि पाटनरोधी विनिर्माण शुल्क जिससे केवल दो इकाइयों की सुरक्षा होनी है, वैश्वीकरण तथा डब्ल्यू टी आ की भावना के विरुद्ध है।

प्राधिकारी विभिन्न उपयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोध को नोट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन सामान्यतः उस क्षति को दूर करना है जो पाटन के अनुचित व्यवहार के कारण घरेलू उद्योग को हुई है और भारतीय बाजार में खुली तथा समुचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित करना है जो देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और इसलिए इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कीमत स्तर भी प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे और घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेंगा औद्योगिकी पर उद्योग तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के लिए व्यापक विकल्प की रखने में सहायता मिलेगी। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से स्वतंत्र भारत के आम नागरिक सभी प्रकार कम नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं की उत्तुल्लेख लगाते समय माननीय निर्दिष्ट

जहां तक यह मांग और आपूर्ति में असमानता का संबंध है, प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी उपायों के फलस्वरूप संबद्ध देशों से उचित कीमत पर वस्तुओं के आयात विनियमित किए जाएंगे और इन उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से होने वाले आयातों को किसी भी रूप में प्रतिबंधित करना नहीं है। जहां तक उपयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए संकेत के अनुसार संबद्ध वस्तुओं की गुणवत्ता तथा मानकों का संबंध है, पूर्वोक्त पैरा में किए गए उल्लेखानुसार प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि ये दावे निराधार हैं, अतः इन पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग विगत में तथा जांच अवधि के दौरान उपयोक्ता उद्योग को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करता रहा है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित प्रक्रिया के कारण हुयी क्षति को दूर करना है इसलिए प्राधिकारी ने उपयोक्ता उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए कम शुल्क के नियम के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अ. पहुँच मूल्य

संबद्ध वस्तुओं के लिए पहुँच मूल्य का निर्धारण भारत औसत सी आई एफ निर्यात कीमत, सीमाशुल्कों के लागू स्तर (धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) तथा एक प्रतिशत उतराई प्रभारों को जोड़ने के बाद किया गया है।

अ. निष्कर्ष

पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद यह देखा गया है कि:-

- (क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी स्वरूपों का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है।
- (ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित संबद्ध वस्तुओं का कम पहुँच कीमतों द्वारा कीमत में हुए ह्रास के कारण कम निवल बिक्री प्राप्ति के रूप में वास्तविक क्षति हुई है, जिससे वित्तीय घाटा हुआ है।
- (ग) संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को उक्त क्षति हुई है। प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 40 और अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी स्वरूपों/ग्रेडों के

आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं जैसा कि नीचे उप पैरा (घ) में भी उल्लेख किया गया है।

- (घ) पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया गया था ताकि घरेलू उद्योग को हुयी क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार यह प्रस्ताव है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 सीमाशुल्क उपशीर्ष 4002.19 (आई टी सी वर्गीकरण 4002.1902) तथा अध्याय 39, सीमाशुल्क उपशीर्ष 3903.90 (आई टी सी वर्गीकरण 3903.9000) के अंतर्गत आने वाले यूरोपीय संघ के क्षेत्र और पोलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी स्वरूपों और ग्रेडों के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे यथा निर्धारित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। तथापि, पूर्वोक्त पैरा ग (2) में उल्लिखित वस्तुओं को शामिल नहीं किए जाने के कारण उन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है।

क्र.सं.	निर्यातक/उत्पादक का नाम	उत्पाद	शुल्क की राशि अमरीकी डालर/मी टन
पोलैंड			
मै0	फर्मा	हाई स्टाइरिन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) के केई आर	248.14
कैमिकज्जा	डौरी	1904, 1909, 9000 सहित सभी ग्रेड जिसमें एस बी	
एस ए		आर 1900 श्रृंखला शामिल है, जिन्हें हाइ स्टाइरिन रेजिन लैटेक्स मास्टर बेंच/हाई स्टाइरिन रीइनफोर्समेंट पालीमर कहा जाता है। पालीस्ट्रीन, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, एक्रीलानाइड्राइल-बुटाडिन स्टाइरिन कापोलीमर्स और स्टाइरिन एक्रीलानाइड्राइल कापोलीमर्स आर एस बी आर 1500 और 1700	

श्रृंखला शामिल नहीं है ।

सभी	अन्य	हाई स्टाइरिन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) क केई आर	421.05
निर्यातक/उत्पादक	1904, 1909, 9000	सहित सभी ग्रेड जिसमें एस बी आर 1900 श्रृंखला शामिल है, जिन्हें हाइ स्टाइरिन रेजिन लैटेक्स मास्टर बैच/हाई स्टाइरिन रीडनफोर्समेंट पोलीमर कहा जाता है । पोलीस्ट्रीन, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, एक्रिलोनाइड्राइल-बुटाडिन स्टाइरिन कोपोलीमर्स और स्टाइरिन एक्रिलोनाइड्राइल कोपोलीमर्स और एस बी आर 1500 और 1700 श्रृंखला शामिल नहीं है ।	

यूरोपीय संघ का

क्षेत्र

2	मै0	बेयर	हाई स्टाइरिन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) के क्राइलिन	359.70
	इंटरनेशनल एस ए,	एच एस 260	सहित सभी ग्रेड जिनमें एस बी आर	
	स्विटजरलैंड और	1900	श्रृंखला शामिल है, जिन्हें हाई स्टाइरिन रेजिन	
	मै0	बेयर	लैटेक्स मास्टर बैच/हाई स्टाइरिन रीडनफोर्समेंट	
	इंटरनेशनल, फ्रांस	पोलीमर्स	कहा जाता है । इनमें पोलीस्ट्रीन, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, एक्रिलोनाइड्राइल बुटाडिन स्टाइरिन कोपोलीमर्स और स्टाइरिन एक्रिलोनाइड्राइल कोपोलीमर्स और एस बी आर 1500 और 1700 शामिल नहीं हैं ।	

सभी	अन्य	हाई स्टाइरिन रेजिन/रबड़ (एच एस आर) क क्राइलिन	430.08
-----	------	---	--------

निर्यातक/उत्पादक एच एस 260 सहित सभी ग्रेड जिनमें एस बी आर 1900 श्रृंखला शामिल है, जिन्हें हाई स्टाइरिन रेजिन लेटैक्स मास्टर बैच/हाई स्टाइरिन रीइनफोर्समेंट पोलिमर्स कहा जाता है । इनमें पोलिस्ट्रीन, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडिन स्टाइरिन कोपोलीमर्स और स्टाइरिन एक्रिलोनाइट्राइल कोपोलीमर्स और एस बी आर 1500 और 1700 शामिल नहीं हैं ।

(ड.) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी दिनांक 13.3.2001 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

(च) इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेंगी ।

एल. वी. सप्तश्रृषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****FINAL FINDINGS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th Decmber, 2001

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of High Styrene Butadiene Copolymer/High Styrene Resin/Rubber (HSR) originating in or exported from Poland and Territory of European Union.

No. 22/1/2000-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A PROCEDURE

The procedure described below has been followed:

- i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, received a written application from M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd. (hereinafter also referred to as petitioner) having registered offices at Apar House, Corporate Park, Sion-Trombay Road, Chambur, Mumbai-400021 and 49-53, Mahavir Centre, Plot No.77, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400073 respectively on behalf of domestic industry, alleging dumping of High Styrene Butadiene Copolymer/High Styrene Resin/Rubber (HSR) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Poland and Territory of European Union (hereinafter referred to as subject countries).
- ii) Preliminary scrutiny of the application filed by the petitioners revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner. The petition was, therefore, considered as properly documented.
- iii) The Authority on the basis of prima-facie evidence submitted by the petitioner decided to initiate the investigation against imports of subject goods from Poland and Territory of European Union. The Authority notified the Embassy of Poland and Delegation of the European Commission in New

Delhi(hereinafter also called Embassies of the subject countries) about the receipt of the dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules.

- iv) The Authority issued a public notice dated 20.12.2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under Custom Code 4002.1902 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from Poland and Territory of European Union.
- v) The Authority notified preliminary findings dated 13.3.2001 and forwarded a copy of the preliminary findings to the known interested parties, who were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter.
- vi) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the subject countries in New Delhi with a request that the exporters/producers of subject goods and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings in the time frame as stipulated in (v) above.
- vii) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by petitioner) and industry/user associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2), 6(3) and 6(4) .
- viii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 9.5.2001 in accordance with Rule 6(6). All parties presenting views were requested to file written submissions of the views expressed. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any;
- ix) The Authority made available the public file as per Rule 6(7) to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request. Also on request of certain interested parties regarding additional information from the petitioner for offering comments was also made available to the extent it was relevant, feasible and permissible within the Rules;
- x) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years, including the period of investigation.

- xi) Response/information to the preliminary findings/disclosure were filed by the following interested parties:-

Domestic Industry

- (i) M/s Apar Industries Ltd.
- (ii) M/s Apcotex Lattices Ltd.

Exporter

- (i) M/s Firma Chemiczna Dwory SA, Poland
- (ii) M/s Bayer International S.A. Switzerland
- (iii) M/s Enichem S.p.A. Italy

Importers/User Associations

- (i) M/s All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers, New Delhi
- (ii) M/s All India Rubber Industries Association, Mumbai
- (iii) M/s New India Rubber Works Pvt. Ltd., Calcutta
- (iv) M/s Banik Rubber Industries, Calcutta
- (v) M/s Paragon Rubber Industries
- (vi) M/s Paragon Polymers Products Ltd.
- (vii) M/s Malaya Trade Impex Polymers
- (viii) M/s Small Scale Rubber Industries Association
- (ix) M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.
- (x) M/s Leo Rubbers

- xii) Arguments raised by the interested parties before announcing the preliminary findings, which have been brought out in the preliminary findings notified have not been repeated herein for sake of brevity. However, the arguments raised by the interested parties subsequently to preliminary finding and disclosure have been appropriately dealt in these findings;
- xiii) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India was worked out on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and by analysing the cost information furnished by the petitioners.
- xiv) The Authority verified the information provided by the petitioners to the extent considered necessary and also conducted on spot verification of the data furnished by M/s Firma Chemiczna Dwory SA., the exporter from Poland .

- (xv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 22.11.2001.
- (xvi) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xvii) The period of investigation (POI) considered is **1.1.2000 to 30.9.2000**

B. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY, EXPORTERS, IMPORTERS, USER ASSOCIATIONS AND OTHER INTERESTED PARTIES & EXAMINATION BY AUTHORITY

The views expressed by various interested parties have been discussed in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been discussed earlier in the preliminary findings and disclosure statement and those now raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. Certain interested parties have indicated that views expressed by them are not taken into account in the disclosure statement. The Authority has considered all views expressed by the interested parties to the extent they are relevant as per rules and have bearing on the case and have been appropriately considered in these findings. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

C.1 PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE

a) **The following submissions have been made by M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd**

- (i) The product involved in this investigation is High Styrene Butadiene copolymer. It is also commonly known as HSR or High Styrene Resin / Rubber. It has been referred to as HSR in these submissions. HSR can be of various grades and can be supplied in various forms. The present investigations is against all grades and forms of HSR imported from Poland and European Union (EU). HSR is manufactured by producers of Styrene Butadiene Rubber (SBR) only and is consumed in the rubber industry. HSR can be sub-divided into two categories:
- (a) SBR 1900 series – Emulsion Resin Rubber Masterbatch also called High Styrene Resin Masterbatch,
- (b) High Styrene Reinforcement Polymers (HSBR).

The SBR 1900 series is a blend or masterbatch of two latexes – Styrene Butadiene Latex and High Styrene Resin Latex. HSBR is a product prepared by direct polymerization of high levels of styrene with butadiene. The product under consideration is imported under Chapter 39 and 40. The difference between the goods imported under Chapter 39 & 40 is that of percentage content of styrene, which does not render the product as different and the product still has almost similar technical and commercial applications.

- (ii) It has been argued by the opposing interested parties that the petitioners have defined the product differently in this investigation as compared to the previous investigation. These parties have further attempted to justify that the product falling under Chapter 39 and 40 are different. To put otherwise, these parties have argued that the product under consideration can not fall under two Customs Chapters. It is submitted that entire argument on this account is without basis and without appreciation of the purpose for which the customs classification is mentioned.
- (iii) At the outset, it is submitted that the petitioners are entitled to seek investigations and anti-dumping duty on that product which has been imported into India and like article of which is being produced in the Country. Further, while deciding the scope of the investigations, the issue of like article has to be kept in mind. In case like product is not included, the entire exercise may become futile. It would be relevant to refer to the order of the CEGAT in this regard in the matter relating to Oxo Alcohols, which states as under:

*“ The Designated Authority has not come to the conclusion that **Normal Hexanol has characteristics closely resembling those of the other articles under investigation.** What the Authority found is that the product manufactured by use of Normal Hexanol can substitute the product manufactured by other Oxo Alcohols.” (emphasis added).*

It is evident from the above that any product type which is like article to the imported article has to be included within the scope of the present investigations.

- iv) The purpose of customs classification is to help in understanding the product. Rule 12(ii) and 17(2)(ii) states as under in this regard:-

“a description of the article which is sufficient for customs purposes”

Thus, the description of the article should be sufficient for the purpose of customs understanding. The description of the article governs the scope of the customs classifications. The customs classification can not govern the scope of the product.

- (v) Rule 4(1)b dealing with the duties of the Designated Authority provides that it shall be the duty of the Designated Authority to identify the article liable for anti-dumping duty. Thus, *the issue of customs classification is not binding on the Designated Authority.*
- vi) The real test for inclusion or otherwise of goods falling under Chapter 39 and 40 lies in the test of like article. It is submitted in this regard that the Polish producers (and possibly the European Union producers) produces different grades of HSR (even though this information has been suppressed by the Polish producer). The grades produced by the company include KER 1904, KER 1909 and KER 9000. As per literature of Polish producer, all these grades fall under High Styrene Rubber (HSR). We request the Designated Authority to direct the exporter to disclose the composition and specifications of these products and examine whether any of these would be assessable under Chapter 39 for the purpose of customs classification. Further, we request the Designated Authority to examine whether these three grades are like articles. We submit that these three grades are like articles in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, production technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing of the goods. These grades are technically and commercially substitutable and the consumers can use them interchangeably. We submit that the grades are like articles in terms of these characteristics.
- vii) It is not necessary that the exporter should have exported all grades/forms of the product for being included in the scope of the investigations. There are invariably a number of types of the product which would not have been exported in the investigation period, yet the same are required to be kept within the scope of the investigations, in so long as these are like article to the product involved.
- viii) It would be misrepresentation of facts to state that the previous investigations did not have any connection with HSR. The preliminary findings notified by the Designated Authority in the previous investigations are quite elaborate on this account and clearly indicate that SBR 1900 series was within the scope of the investigations in the previous investigations.
- ix) Assuming though not admitting that the product involved in the previous investigation did not include other types of HSR, the same does not in any event prevent the petitioners from including these types within the scope of the present investigations. Assuming though not admitting that the petitioners in the previous case did not take due care of the product involved, the same does not imply that the petitioners in this case should follow the same. The two investigations

are distinct and different investigations and the scope of the investigations in the previous case does not grant any liberty to the opposing interested parties on this account in the present investigations. We rely upon the investigations in the case of polyester film by European Union against Korea also, wherein the product under consideration was changed against the same country for the same product.

In response to the disclosure, the following submission has been made:-

- i) We reiterate our earlier submissions on the product under consideration.
- ii) It is noted that the Designated Authority has proposed to clarify that the product does not include Polystyrene, Thermoplastic elastomer, Acrylonitrile – Butadiene Styrene copolymers and Styrene acrylonitrile copolymers. The Domestic Industry has no objection to such a clarification, which should take care of the repeated argument of opposing interested parties with regard to possible charging of duties on other products falling under Chapter 39. However, it is clarified that neither the Domestic Industry has demanded nor Designated Authority has imposed anti dumping duty on any product being imported under Chapter 39. The Domestic Industry has demanded duty on the subject goods, if imported under Chapter 39. It cannot certainly be the case of the opposing parties that HSR if sought to be cleared under Chapter 39 should not attract duty and it is not the case of the Domestic Industry that if other products if imported under Chapter 39 should also attract duty, when the Domestic Industry is seeking duties only on HSR.
- iii) With regard to other types of HSR being produced by the exporters (which have not been exported to India in the investigation period), it is submitted that all these types are required to be included within the scope of duties, as these various other types of HSR being produced by the subject exporters are like article to HSR exported to India in the investigation period.
- iv) With regard to the issue of like article, it is submitted that the goods being produced by the Domestic Industry are like article to the goods being imported from subject countries. We rely upon our earlier submission.
- v) It has been argued by the other interested parties that no evidence has been provided by the petitioners nor any analysis carried by the Designated Authority in the preliminary findings that the two products (imported under Chapter 39 and 40) is like article. This is factually incorrect, as the petitioners have provided sufficient evidence in as much as the following have been provided to the Designated Authority

showing interchangeability of the goods imported under Chapter 39 and 40 as per letters of Customs; Literature of Dwory, the exporter from Poland, letter from IISRP clarifying the technical information about SBR 1900 series and details of transaction-wise imports from PPR, clearly showing that the goods have been imported from other countries under Chapter 39 as well as 40.

b. **M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland have made the following submissions:-**

- (i) It has been mentioned in the written submissions that “the difference between goods imported under chapter 39 & 40 is that of percentage content of styrene, which does not render the product as different and the product still has almost similar technical and commercial applications” (emphasis added). It is observed that no basis has been supplied by the petitioners nor is any such analysis visible in the preliminary findings that the two products have ‘almost’ similar technical and commercial applications. In this connection, it is submitted that the determination of like articles has to be made by a positive and affirmative finding and not only on the basis of the contentions made by the petitioners.
- (ii) The petitioners have further attributed to the opposing Interested Parties the contention that the product under consideration for the purpose of anti-dumping cannot fall under two different customs headings. It may be stated that as far as this exporter is concerned, we submit that no statement was made by us that the product under consideration for the purpose of anti-dumping investigation cannot fall under two different customs headings. The petitioners have inaccurately attributed such statement to the ‘opposing parties’ and then have gone ahead to justify the same. It has been vehemently argued in the written submissions that the customs classification is not relevant for the purpose of anti-dumping investigations. The basic assertion seems to be that since the product under consideration in the Petition and consequently the initiation notification covers both resins as well as rubber, there cannot be any comments or arguments advanced on the scope of investigations. This, it is submitted is clearly erroneous. The Hon’ble Designated Authority needs to record a finding on the product under consideration and the like article.
- (iii) In this connection, it is our submission that nowhere have we made the statement that the product under consideration cannot fall under two or more headings or sub-headings of the customs classification. It may also be mentioned that in this case the issue is that of two different ‘*chapters*’ and not two different *headings* as made out by the domestic industry. We would like to respectfully submit to your Honour that we have painstakingly surveyed the literature on the subject and we could not find any parallel where

two products falling under two different chapters have been held as like articles. We have made effort to look for cases in different regimes where the product under consideration could be as broad as covering two entirely different chapters but have not been able to locate any such reference. It is in this connection that we brought to the kind attention of the Hon'ble Designated Authority the system of HS Classification which though not binding on the Authority certainly has tremendous persuasive value. The scheme of classification is designed to classify the products according to their degree of differentiation. Thus, the higher the level of classification, higher would be the product differentiation. For example, the two digit level would be for Organic Chemicals, Fertilizers, Plastics and Articles thereof, etc., while the six digit level would be the product groupings within the chapter heading. The degree of differentiation is thus obvious and cannot be ignored by the Hon'ble Designated Authority. This would perhaps be the first case in the entire jurisprudence of anti-dumping that products falling under two different Chapters are considered as like articles.

- (iv) Both Apar and Apcotex make "High Styrene Rubbers" only which are classified as "Synthetic Rubbers" falling under Chapter 40 of the Custom Tariff Act. This is confirmed by their own statements in their Balance Sheet. Kind attention is invited to the Directors' report attached to Apar's Balance Sheet of 1998-99 as well as Schedule 21 of the same Balance Sheet at Serial (i) where APAR have clearly classified their high styrene rubber as "Synthetic Rubber". Apar is trying to confuse the Authority by talking of SBR 1900 series and High Styrene Butadiene masterbatches. The fact of the matter is that they are making "Synthetic Rubber" which meet the definition as stipulated under Chapter Note No. 4(a) to Chapter 40 of the Customs Tariff Act and their product does not meet the definition of Chapter note (i) to Chapter 39 of the Custom Tariff Act.
- (v) Styrene Butadiene Co-polymer resins or Polymers fall under Chapter heading 3903.90 and they are not the same as Styrene Butadiene Rubbers falling under Chapter 40 of the Customs Tariff Act.
- (vi) During a previous Anti-dumping investigation in the matter of SBR from several countries including Korea RP, the Authority had held in its preliminary and final findings that the product "High Styrene Resin" and Styrene Butadiene Co-Polymer Resin are not the product under consideration when the same arguments were put forth by the same petitioner in that proceedings. This matter was further confirmed in the CEGAT in an appeal filed by Relaxo Rubber Ltd. In their final Order No. 164/165- 2001-A dated 26/4/2001, the CEGAT Tribunal held that the product "Styrene Butadiene Co-Polymer Resin" has no relation with "Styrene

Butadiene Rubber” falling under Chapter heading 4002. Thus, it is respectfully submitted that there can be no controversy on the issue of the product under consideration in so far as the product produced both by Apar and Apcotex is “Styrene Butadiene Rubber” falling under Chapter 4002 and since they do not manufacture any “Styrene Butadiene Co-Polymer resins” falling under Chapter 3903.90, they cannot claim that such products should be included under the scope of present investigation.

- (vii) In their submissions dated 23/5/2001, at Para (i) the Petitioners have cited a recent CEGAT order in the antidumping matter related to Oxo Alcohols. It is submitted this is mis-leading. In the referred to CEGAT order, as published in 2001 (130) ELT-58 (Tri-Del), the Tribunal has clearly held at Para 9 of their finding that “Normal Hexanol is not one manufactured or produced by Domestic Industry. So, its import cannot cause injury to Domestic Industry”. In order for the product to be treated as “like article” the Authority must arrive at finding that such products themselves have characteristics closely resembling each other. In the present case since it is clearly and technically obvious that Styrene Butadiene Co-Polymer Resins do not meet the characteristics of Styrene Butadiene Rubber as outlined in Chapter Note 4 (a) of Chapter 40 in the Customs Tariff Act that they do not have characteristics closely resembling each other. Therefore, they are not “like articles”.
- (viii) It is already a settled matter in the previous anti dumping finding where the Authority held that SBR as not like articles or product under consideration with “Styrene Butadiene Co-Polymer Resins” the same applies in this proceeding as well and the product under consideration, therefore, has necessarily to be restricted to any or all Styrene Butadiene Rubbers falling under Chapter 40 only which represent the product actually produced by the domestic industry.
- (ix) Notwithstanding the above and without prejudice, we submit that there are several other Styrene Butadiene Co-Polymers Resins falling under Chapter 3903.90 which are never used in the rubber industry and which would fall under ambit of Anti-dumping duty were the Authority to ever consider that they were like articles to HSR. By way of examples, we cite the following products:-
- i. “Styrolux”- produced by BASF, Germany
 - ii. “K-Resin” – produced by Phillips Petroleum, USA
 - iii. “Asaflex”- produced by Asahi Kasei, Japan.
- (x) Out of the examples of Styrene Butadiene co-Polymer resins cited above, “Styrolux” is produced in EU and antidumping duty would become leviable on it were the Authority to enlarge the scope of the product under consideration to Chapter heading no. 3903.90. This

product is not “like article” to the HSR produced by the domestic industry and under no circumstances can any antidumping duty be levied on it.

- (xi) It is submitted that the Designated Authority had consciously and deliberately kept resins out of the purview of the product under consideration in the earlier findings obviously for the reasons that the two products fell under two different chapters.
- (xii) It is also interesting to see the reference to the ‘case of polyester film by European Union against Korea also, wherein the product under consideration was changed against the same country for the same product’. We earnestly submit that such citations without giving the full reference and attaching or quoting at least the relevant extracts cannot be permitted to be taken on record. In any case, it is our understanding that in the above-referred case, the product description was changed but each time the coverage or scope of investigation was narrowed down. The case referred by the petitioners, therefore, support the case of the exporters and the user industry more than that of the domestic industry.
- (xiii) We also wish to submit that as per our understanding, the EU distinguishes the PCN at the eight or ten-digit or even higher level and the same was done in this case also. In contrast, the domestic industry in this case has been pleading for clubbing of two products at the two digit (Chapter) level. This is not borne out of the international jurisprudence nor from the earlier two decisions of the Hon'ble Designated Authority. This is without prejudice to our submission the fact that *res judicata* will operate prohibiting the Hon'ble Designated Authority to take a different view in the instant case as a positive determination has been made by the Hon'ble Designated Authority in quasi-judicial proceedings on product under consideration as well as like articles.
- (xiv) Further, in the case of SBR cited by the petitioners, the position of the Hon'ble Designated Authority is clear beyond any doubt:

“The Authority observes that items falling under 3903.90 are not the product under consideration and **SBR in 1000 series is not produced by petitioner and thus are not product under consideration**” (emphasis added).
- (xv) The ratio of the decision in the above case is squarely applicable on the facts of this case also and to that extent are binding on the Hon'ble Designated Authority. The linkage of the two cases cannot be better explained than the submissions made by the Petitioners themselves in their written submissions:

In para 6 of the written submissions, the petitioners have stated as under:

"It would be a misrepresentation of facts to state that the previous investigations did not have any connection with HSR"

In para 7, it has been categorically asserted that:

"The two investigations are distinct and different investigations and the scope of the investigations in the previous case does not grant any....." (emphasis added)

(xvi) Thus, while it would be clear from the above that the petitioners have taken shifting stands as and when it suited them. The current investigation is not being seen as a different investigation from the previous one either by the domestic industry or by the exporters in so far as the issues of product under consideration and like articles are concerned. The doctrine of *res judicata* will be applicable on this ground also.

(xvii) We had also made a specific argument during the public hearing to the effect that if the customs classification is different to the extent of two different chapters and not merely headings or sub-headings, the responsibility on the domestic industry to prove that the two products falling under two different chapters are like articles is much more. Unfortunately, as stated earlier, we do not find any basis in the petition or in the preliminary findings as to how the test of 'likeness' for products belonging to two different chapters was passed. In fact, the preliminary findings are not clear whether any such test was applied. It is a well settled principle of law that the evidence is to be led by the party that makes the assertion. Note on Section 101 of the Evidence Act 1872:

Section 101 – Burden of Proof: "Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist . . ."

(xviii) We had also contended that resins have been included on the grounds that rubber falling under chapter 40 has been cleared under Chapter 39 also. We still submit that what was cleared under chapter 39 was indeed resins and not rubber unless the Hon'ble Designated Authority has any different evidence. We earnestly request that the Designated Authority may kindly ascertain the facts in this regard from the customs authorities.

In response to the disclosure, M/s Firma Chemcizna Dwory SA have made the following submissions:-

(i) M/s Firma have reiterated the submissions made by them on these issues earlier.

c) **M/s Bayer International SA Switzerland have made the following submissions.**

- (i) The importer consignment are cleared by the exporter under Chapter 39 or 40 which however can be ascertained conclusively only from the importer. M/s Bayer International has also indicated their exports to India and production during POI.

d) **M/s All India Federation of Rubber Footwear Manufactures and M/s Paragon have made the following submissions:**

- (i) At the outset it must be pointed out that the products under investigation as are set out in the petition is unduly broad and without justification. The jurisprudence on anti dumping suggests that the product under consideration should always be the narrowest group of products in order to ensure that there is no undue protection to the domestic industry. In this case, as elaborated in the following paras, the Domestic Industry has attempted to include products, which should not have been included in the scope of investigations in the first place.
- (ii) It may be pointed out that in the first investigation concerning the import of SBR from Japan, Korea, Turkey, Taiwan, USA, Germany and France the product involved was Styrene Butadiene Rubber classified under custom sub-heading 4002.19.
- (iii) In that particular case, the “domestic industry” was M/s Synthetics and Chemicals, who manufactured all types of SBR.
- (iv) In this present case on HSR(SBR 1900 Series) the Petitioners (M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd.) have in the petition asked for investigation in to High Styrene Butadiene Copolymers. They go on to state:-
- “This is also called High Styrene Resin/Rubber (HSR). HSR covers SBR 1900 series and HSB. SBR 1900 series refers to High Styrene Resin Masterbatch(also called Emulsion Resin Rubber Masterbatch). HSB refers to High Styrene Reinforcement Polymers. HSR can be of various grades and can be supplied in various forms...”
- (v) It is noteworthy that even in the first case concerning SBR the Hon'ble Designated Authority excluded Resin from the scope of the investigation. The Hon'ble CEGAT on 26.4.2001 confirmed this finding (Final Order No.164-165/2001-A). The Hon'ble CEGAT cited with approval the final order of the Designated Authority dated 2nd June, 1999. In particular paragraph 7 was reproduced.

“While submitting the evidence that HSR 1900 series is also being imported under Chapter 39, the Authority observes that the item cleared under Chapter 39 is “Elastomer Resin KHS 68” and thus is not under the nomenclature of “Synthetic Rubber.”

Clearly the Hon'ble Designated Authority intended to only impose duty on Synthetic Rubber. However, as is evident from the petition, the petitioners have through a very convoluted manner sought to include not only all types of HSR within the purview of the investigation (i.e. 1500 and 1700 series) but also Resins which have been conclusively held not to be “Synthetic Rubber”. They do not manufacture the co-polymers and resins, sought to be included by them. It is admitted that the petitioners do not manufacture any thing other than HSR 1900 grade.

By broadening the scope of the product under investigation, the petitioners have surreptitiously sought to include products, which they do not manufacture.

- (vi) It is submitted that by including co-polymers in the description of the product under consideration, the petitioners are seeking to include certain types of plastics, which are clearly not “Synthetic Rubber”. Not one iota of evidence is produced to show that synthetic rubber is coming under Chapter 39. We urge the Hon'ble Designated Authority to kindly get the facts ascertained from the Ministry of Finance if any Synthetic Rubber has been cleared by the Customs under Chapter 39. As was submitted to the Hon'ble Designated Authority during the hearing, there is no question of synthetic rubber coming under Chapter 39 as the latter covers only the items classified under that chapter in terms of the Notes to Chapters 39 and 40. Broad based imposition of duties based on mere allegations by the Petitioners can have a devastating effect on the user industry.
- (vii) Consequently it must be clarified that the product under consideration is only High Styrene Rubber, i.e. SBR 1900 Series which is a blend of masterbatch of 2 Latexes - Styrene Butadiene Latex and High Styrene Latex falling under the Chapter Heading 4002.19. Anything else is not manufactured by the Petitioners and cannot fall under the purview of the Product Under Consideration.
- (viii) It is submitted that any other description or heading will be ultra vires the scope of the investigation. The product under consideration is Styrene Butadiene Rubber 1900 series i.e., HSR, and the same must follow the precedent as laid down by the Honourable Designated Authority in the first SBR case.
- (ix) As was submitted to the Designated Authority during the hearing, we apprehend that the information submitted by the Domestic

Industry and accepted by the Designated Authority for the purpose of preliminary findings may not be factually correct. We would most respectfully submit that the authenticity of the claim that synthetic rubber is being cleared under Chapter 39 also, may be verified from any possible source at the command of the Designated Authority. We still believe that there is no question of synthetic rubber coming under Chapter 39 as the latter covers only the items classified under the chapter in terms of the Notes to Chapters 39 and 40. Broad-based imposition of duties based on mere allegations by the petitioners can have a devastating effect on the user industry.

In response to the Disclosure, M/s All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers has made the following submission:-

- (i) Our arguments put forth in our submissions have either not been taken into consideration or have been brushed aside as a result of which the Anti-dumping Authority has erroneously exceeded the scope of review envisaged under Rule 23 with regard to 'Product under Consideration' whereas in the original final findings dated 2.6.1999 the Designated Authority has restricted the scope of the "Product under Consideration."

2. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the submissions made by various interested parties regarding the product under consideration being quite broad based and also that the goods manufactured by the Domestic Industry are not like article to the goods imported from the subject countries. The Authority also notes that it has been indicated that both M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd. make High Styrene Rubber(HSR) and that this product would only fall under Chapter 40 of the Customs classification and also that in the previous anti dumping investigation of SBR from the subject countries, classification regarding this product has already been given. The Authority notes that it has been argued that the product is broad enough and extends to two chapters of customs classification whereas Chapter 39 pertains to Resins and not to rubber, the products which the Domestic Industry manufactures. It has also been indicated that by virtue of such a broad based coverage certain category of products like Asaflex from Japan, Styrolus from Germany and K-resin from USA would also attract anti dumping duty even though they may not be covered in the scope of the investigation. The Authority also notes that specifically the practice of EU has been quoted in reference to the definition of the product under consideration.

The Authority after carefully examining into the above arguments holds that the product under consideration as defined in the initiation notification and subsequently in the preliminary findings in Para C(I) is different by virtue of being wider from the product under consideration as defined in the earlier investigation on SBR from Japan, Korea, USA, Turkey and Taiwan

being referred to by various interested parties in the foregoing para. The Authority noting the submissions made by various interested parties that certain category of goods would not fall under the scope of investigation viz. Asaflex from Japan, Styrolus from Germany and K-resin from USA confirms the product under consideration as indicated in the preliminary findings in Para C(1) but with exclusion of certain category of goods as indicated below. The product under consideration is defined as under:-

“High Styrene Butadiene Copolymer, also called High Styrene Resin/Rubber (HSR) of all grades and forms. HSR covers SBR 1900 series referring to High Styrene Resin Latex Master batch and HSBP referring to High Styrene re-informement Polymer. The product does not include Polystyrene, Thermoplastic elastomer, Acrylonitrile-Butadiene Styrene copolymers, Styrene-acrylonitrile copolymers. Also SBR 1500 and 1700 Series are not covered in the product.

As regards the customs classification and the product under consideration, the Authority notes the submissions specifically made by various interested parties and holds that depending on the Styrene content, the product can be imported under Chapter 40, Custom Head 4002.19 (ITC classification 4002.1902) (Styrene Butadiene Rubber with Styrene content of over 50%) and Chapter 39, Custom Head 3903.90 (ITC Classification 3903.9000) (Polymers of Styrene in primary form other than Polystyrene, Styrene-Acrylonitrile copolymers & Acrylonitrile-Butadiene-Styrene copolymers).

Recalling Hon'ble CEGAT's order No. 20& 21/2000 dated 2.2.2000, the Authority also holds that the custom classification is relevant to the extent the product can be specifically defined and that irrespective of classification under the customs head the description of the product as illustrated above is binding. The Authority also recalls the catalyst case wherein the subject goods were cleared under two chapters of customs classification.

The Authority notes that certain submissions have been made on quality and standard of the subject goods supplied by Domestic Industry. At the same time views have been expressed that Domestic Industry is unable to meet the demand of subject goods in totality. There is an inherent contradiction in these submissions to the extent that as such the users are sourcing the material from domestic producers and also disputing quality. The Authority, therefore, holds that the quality and standards claims of the users are unsubstantiated, not quantified and are therefore rejected.

The Authority also notes the submissions made by various interested parties regarding the goods manufactured by the Domestic Industry not being like article to the goods imported from subject countries and that the test of likeness has not been spelt out in the preliminary findings. The Authority noting the data provided by the exporter M/s Firma Chemiczna Dwory SA, Poland holds that the goods exported by them to India during the POI and the goods produced by the Domestic Industry have closely resembling characteristics. The goods exported from Poland were used in similar uses like the domestic product and that there is technical and commercial

substitutability of these goods with reference to usage by certain common customers in footwear/ other applications. The Authority also notes that besides the grade KER 1904 which has been exported by the exporter from Poland, the other grades viz. KER 1909 and KER 9000 manufactured by them also have characteristics closely resembling the goods exported by them, and are also used for similar end uses and are also therefore within the purview of investigation and qualify the test of like article. The Authority also notes that the goods produced by the Domestic Industry are also technically and commercially substitutable with characteristics closely resembling the goods exported by M/s Bayer International SA Switzerland in terms of end use both application and customer-wise. The Authority therefore recalls and confirms the finding on like article as indicated in Para C(2) of the preliminary findings.

D.1 STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY

a) M/s Apar Industries Limited and M/s Apcotex Lattices Limited have made the following submissions:-

(i) We reiterate our earlier submissions on the standing of the Domestic Industry, which are not being repeated for sake of brevity. The petitioners satisfy the conditions of standing and constitute the Domestic Industry within the meaning of the Rules.

b) All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers and M/s Paragon Rubber have made the following submissions:

(i) The petitioners have stated in this petition that M/s Synthetics and Chemicals Limited have recently stopped production but surprisingly have sought to include their data for purposes of injury.

(ii) This is all the more surprising since in 1999 the petitioners filed a petition against import of NBR from Taiwan and in that petition categorically stating that M/s Synthetics and Chemicals had suspended its production for the past many years.

(iii) M/s Synthetics and Chemicals Limited cannot be included as the Domestic Industry as they have ceased production since about three years and accordingly cannot be included even for injury purposes.

(iv) If M/s Synthetics and Chemicals Ltd. is to be included as part of the Domestic Industry for injury (as the Petitioners seem to have done), the petitioners – M/s Apar Industries Ltd. and Apcotex Lattices Ltd. do not have sufficient standing to file this petition, as M/s synthetics and Chemicals Ltd. accounted for over 85% of the domestic HSR production in India. If their capacity is to be counted, then clearly with 15% capacity the petitioners cannot file this petition.

- (v) Furthermore, assuming without admitting that the petitioners comprise "Domestic Industry" then based upon the same "confidential data" from the same "Public Sources" that the petitioners rely upon, it appears that M/s Apar Industries Limited have themselves imported rubber under the classification 4002.1900 from UK, which is a part of the European Union. It is submitted that based on this alone, the Hon'ble Designated Authority should consider if M/s Apar Industries must be removed from the Domestic Industry. It also shows that full facts were not brought to the notice of the Designated Authority at the time of initiation.

2. **EXAMINATION BY AUTHORITY:**

The Authority notes that it has been indicated by certain interested parties that if the data of M/s Synthetics and Chemicals Ltd., a domestic producer of SBR is included for the purpose of costing and injury analysis, the petitioners would not qualify for the purpose of standing for this petition and that M/s Apar Industries Ltd. has also imported the subject goods from territory of EU in the POI. The Authority noting the above submissions holds that M/s Apar and M/s Apcotex have not imported the subject goods in the POI and that M/s Synthetic and Chemicals Ltd have closed their production and have not produced the subject goods during the POI and that M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd. qualify as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and also have the requisite standing to file the petition as per Rule 5(a) and 5(b). In this regard, therefore, the Authority recalls and confirms Para C(3) of the preliminary findings on standing of the petitioners.

E.1 OTHER ISSUES

a) M/s Apar Industries Limited and M/s Apcotex Lattices Limited, Mumbai have made the following submissions:-

- (i) No suppression of information regarding address of factories on this account by the petitioners was made. This is mere oversight and was hitherto not pointed out by any interested party. In fact, the address of the plants of the two companies are well known to a large number of consumers of the subject goods in India. The relevant addresses are:

- Apar Industries Limited
Dharmsinh Desai Marg,
Mahul Trombay
Mumbai 400074 Maharashtra
Contact Person: Shri G. R. Karandikar
Telephone: 5951531/5544005
Facsimile: 5541708

The company has produced the subject goods at its Valia plant also, address of which is as under:

Village Dungri,
Taluka Valia
District Bharuch-Gujarat
Contact person: Shri Dinesh Bale,
Telephone: 2643-70442/3/5
Facsimile: 2643-70010

Apcotex Lattices Limited

*Plot No. 3/1,
Taloja Industrial Area of MIDC*

P O Taloja District-Reigad Maharashtra
Contact person: Shri B V Manjunath
Telephone No.: 7412239
Facsimile: 7412360

- (ii) The Domestic Industry while providing information on non-confidential basis as sought by various interested parties in the public hearing requests that the matching information in respect of two responding exporters and the basis of AIRIA's assessment of demand of HSR be provided.
- (iii) This issue has been raised by opposing interested parties that the domestic industry had not given sufficient information to the Designated Authority for the purposes of initiation.

We submit that the Designated Authority took eight months to initiate the investigation and before initiation, a lot of additional information as well as a lot of clarifications were desired by the Designated Authority, which were also provided by the domestic industry. During this eight months period, the domestic industry's allegation has been scrutinised in detail. Further, we submit that the domestic industry is required to provide sufficient evidence to establish dumping and onus is on the exporter to provide all information without any suppression/distortions to the Designated Authority to establish that there was no dumping. Before initiating the investigations, the Designated Authority examined adequacy and accuracy of the information provided in the petition, as noted in the initiation notification dated 20.12.2000. The investigations have been initiated in accordance with the Rules. The argument of the opposing interested parties perhaps is that the Designated Authority should have investigated the case before initiating the investigations. We submit that purpose of initiation is to investigate the existence of alleged dumping causing injury. The Designated Authority is not obliged to investigate the allegation before initiating the investigations.

(iv) AIRIA has written to the Designated Authority as also to us seeking certain information about the company. While we find that the matching information has not been provided by the exporter from Poland, we are providing the relevant information to the Designated Authority. We are willing to disclose this information to the exporters, importers and AIRIA. However, we request the Designated Authority to apply the same treatment to an exporter and a domestic producer with regard to the issue of confidentiality. In case the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality by the exporter is warranted, we request the same treatment. In case the Designated Authority is satisfied that this information should be disclosed to the opposing interested parties, we request the following information:-

1. Matching information in respect of the two responding exporters.
2. AIRIA's assessment of demand of HSR and the basis thereof. We also request that AIRIA be in that event directed to further provide information how this demand was met by the industry. As is known, the Designated Authority has defined demand as the sum of imports and sales by the domestic companies. The demand is thus required to be furnished accordingly by AIRIA.
3. Information on volume of imports by each responding importer.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

1. There are a number of submissions made by opposing interested parties which are either factually not correct or are made with an attempt to mislead the Designated Authority or are not relevant to the present investigations. For instance, it has been pointed out that submissions made by the petitioners are unsigned and does not identify the persons taking responsibility for the statements made. The argument is without appreciation of the fact that the written submissions filed by the Domestic Industry were accompanied with a covering letter, duly signed.
2. There are lots of submissions, which remained unsubstantiated or inconclusive or does not lead to an argument/averment at all. For instance, while the opposing interested parties are pointed out that there should be sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link, the opposing interested parties have thereafter argued that the evidence of normal value in terms of cost of production should be only in terms of cost of production in the country of origin. In fact, it is not even the argument of the exporter that the Domestic Industry has adopted Indian cost as normal value in the subject countries.
3. A hype is being created with regard to disclosure of information and confidentiality of information. Surprising, such an argument has

come from those interested parties whose data has been found much different than what has been filed. In fact, the Domestic Industry earnestly submits that responses of such exporters should be completely rejected wherein it is found upon subsequent verification that the information initially furnished was factually wrong and misleading.

4. With regard to confidentiality, any information, which is by nature confidential is allowed as confidential by the Designated Authority. It may not be out of context to mention that even the exporters have not cited any reason for claiming confidentiality and yet the exporters have resorted excessive confidentiality.
- 5.** With regard to the information sought by All India Federation of Rubber Footwear Manufacturer(FORM), it is submitted that FORM has conveniently ignored to mention that Domestic Industry has also addressed a number of letter (copies of which were also endorsed to the Designated Authority) to FORM, which not only remained unreplied to the core issues involved but also, were evasive on the other suggestions made by the Domestic Industry.
6. The opposing interested parties have projected as if the Designated Authority should have first investigated the case before initiating investigations. It is submitted that the purpose of initiation to investigate the allegation and not that the Authority should first investigate to initiate.
7. The opposing interested parties have resorted to conjectures while assessing demand. Demand of the subject product in the investigation period was in the region of 17000 MT on annualized basis.

b) M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland has made the following submissions:-

- (i) It is submitted that the submission made on behalf of the petitioners is unsigned and does not identify the persons who are taking responsibility for the statements made. This is crucial since the Hon'ble Designated Authority is a quasi-judicial authority. Furthermore some of the statements made are misleading and wrong. Accordingly the party making the statement must identify themselves.
- (ii) Rule 5 (3) (a) states that the designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-Rule (1) unless (a) It determines on the basis of an examination of the degree of support for or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. (b) It examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is **sufficient evidence** regarding:

- (i) Dumping,
- (ii) Injury, where applicable, and
- (iii) Where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury to justify the initiation of an investigation.

A plain reading of the above provisions clearly indicate that the evidence with regard to dumping, injury and causal link are required at every stage of the investigation. The only difference for the purpose of initiation is that instead of full satisfaction of the Designated Authority, sufficient evidence is required. However, it may kindly be noted that while the level of evidence may be different between the initiation and the provisional/final findings, the authorities are not at liberty to change the 'nature' of evidence at the time of initiation or at the time of provisional / final findings. To illustrate the argument, it is submitted that for initiating an investigation, it is necessary that there should, *inter alia* be sufficient evidence with regard to Normal Value. The first option is to have the prices prevailing in the home market of the exporting country. The other two options subject to certain conditions are:

- Third country export price
- Cost of production in the country of origin plus reasonable administrative, selling and general costs, and profits

Assuming that for the purpose of initiation, it was sufficient to rely upon any of the three options, it was incumbent upon the petitioner domestic industry to provide sufficient information with regard to that particular option. In the instant case, the domestic industry has chosen to rely upon the 'cost of production' method. Without prejudice to our reservations on the merits and propriety of selecting the 'cost of production' method for a market economies like EU and Poland, we submit that the domestic industry ought to have made the estimations for the Normal Value based on the cost of production plus expenses and profit only in the country of origin.

- (iii) The attitude displayed by the domestic industry with regard to the information, which has been kept as confidential, by the domestic industry is, it is respectfully submitted, strikes a major blow to the cornerstones of all anti dumping investigations, viz. transparency and adversarial investigations. The argument advanced for not giving the requisite information is that the exporter should also be asked to provide the same information. It has not been clarified as to what information is being sought from the exporter, which the latter is not, entitled to keep as confidential. It may be pointed out that it was the domestic industry, which had approached the Hon'ble Designated Authority for imposition of anti-dumping duty against specific sources. It is a well-settled point of law that it is for the party bringing the case

to lead the evidence. It would not be permissible for the domestic industry to first provide inadequate and inaccurate information and when it is pointed out that the same cannot be kept as confidential under the existing Rules and instructions on the subject, it is argued that the exporter should be asked to give the same information. The responsibility of the domestic industry with regard to submission of confidential information cannot be brushed aside so lightly. We submit that our rights under the rules are seriously jeopardized due to the stand of the domestic industry. We reiterate our request to the Hon'ble Designated Authority to kindly let us have the reasons submitted by the domestic industry, as required under the rules, to keep the following information confidential and whether the same were considered sufficient by the Designated Authority:

- (i) Basis of stating that HSR is being cleared under Chapter 39 also.
 - (ii) Source and basis of alleged imports of HSR under chapter 39.
 - (iii) Import figures based on so-called public sources.
 - (iv) Volume and Value of imports from other countries.
 - (v) Production Volume by the domestic industry.
 - (vi) Production Volume of Other related products by the domestic industry.
- (iv) The citations, statements and quotations by the petitioners are in many places wrong and have been made selectively, concealing the true context in which they were made. Accordingly, it is respectfully submitted that the Hon'ble Designated Authority verify the accuracy and the context of the same rather than accepting them at face value.
- (v) -Designated Authority may terminate the investigation on account of:
- (a) inaccurate and inadequate information was not available at the time of initiation.
 - (b) there is no dumping.
 - (c) no injury to the Petitioners.
 - (d) there is no causal link between the alleged dumping and alleged injury.
 - (e) domestic industry has not been able to substantiate their arguments and have failed in responding to the issues of facts and law raised by the exporter/ user industry.

c) M/s Bayer International SA Switzerland have made the following submissions:-

- (i) M/s Bayer International SA has indicated that the crucial issue, which the Designated Authority needs to address, is the nature of confidentiality and it is respectfully submitted that the Authority is only required to keep confidential figures and data which are susceptible to use by competitors or interested parties detrimental to the person providing the information. It is incumbent on the Authority to determine for itself as to what information marked as confidential by the parties is not really in the nature of confidential information and to disclose the same despite the fact that the party providing the information has marked the same as confidential. Failure to do so would result in the inability of the parties to effectively counter information, which may be used against them in arriving at a decision and may amount to miscarriage of justice and/or arrival at incorrect conclusions.
- (ii) Virtually all figures in the complaint have been treated as confidential including figures compiled by Polymer Plastics & Rubber Journal which is clearly not a privileged document and publication available in the public domain. It is submitted that this Designated Authority should therefore analyse the same and provide such information as it may in its discretion consider to be not confidential

d) M/s All India Federation of Rubber Footwear Manufactures and M/s Paragon Rubber have made the following submissions:

- (i) The anti dumping rules are clear that the Designated Authority must be satisfied as to the need for keeping information as confidential. in particular Rule 7(1) and Rule 6 of the Anti Dumping rules are relevant.
- (ii) The aspects which have been kept as confidential by the Domestic Industry are in total disregard to the above instructions, rules and jurisprudence on the subject.
- (iii) Designated Authority had during the public hearing specifically asked the Domestic Industry to provide the basic information to the user industry. Encouraged by this, the All India Federation of Rubber Footwear Manufactures (FORM) wrote to the Domestic Industry to provide the relevant information in due deference to the directions of the Hon'ble Designated Authority. We would like to inform you that FORM has not received any information.
- (iv) Rule 5 (3) (a) states that the designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-Rule (1) unless (a) It determines on the basis of an examination of the degree of support for or opposition to the application expressed by domestic

producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. (b) It examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding:

- (a) Dumping,
 - (b) Injury, where applicable, and
 - (c) Where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury to justify the initiation of an investigation.
- (v) The aspect concerning the accuracy and adequacy of information concerning dumping, injury and a causal link is an obligation emanating from Article 5.3 of the WTO Agreement on anti-dumping.
- (vi) This point was also raised in a dispute concerning the Panel decision in the Guatemala - Mexico Cement case. In that case the Honourable Panel opined that an aspect which was required to have been considered at the time of initiating a particular case could not subsequently be rectified retrospectively. Para 8.62 of the panel decision is relevant.¹
- (vii) The information submitted by the petitioner is wholly insufficient and inaccurate for the purposes of initiating an investigation. The information pertaining to the imports is based on mere conjecture and contains a number of misleading statements.
- (viii) Using this self-created confusion, the petitioner goes on to compile import information from secondary sources, which is kept confidential. While doing so it admits that the secondary sources do not reflect information from all Indian Ports.
- (ix) It is respectfully submitted that to prevent self serving and selective data being used to file a Petition that rule 5 (3) (b) puts a duty on the Hon'ble Designated Authority, in fact this duty was very eloquently expressed in the Guatemala Mexico Cement Case as per para 8.31 of the report .
- (x) It is respectfully submitted that the anti dumping rules are clear that the Designated Authority must be satisfied as to the need for keeping information as confidential. In particular Rule 7(1) and Rule 6 of the Anti Dumping Rules are relevant.
- (xi) We would like to reiterate that aspects which have been kept as confidential by the Domestic Industry are in total disregard to the above instructions rules and jurisprudence on the subject.

- (xii) It may be recalled that the Designated Authority has during the public hearing specifically asked the Domestic Industry to provide the basic information to the user industry. Encourage by this, the All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers (FORM) wrote to the Domestic Industry to provide the relevant information in due deference to the directions of the Designated Authority. We would like to inform you that FORM has not received the information.
- (xiii) It was indicated that the Domestic Industry has kept confidential information . "Basis of stating that HSR is being cleared under Chapter 39, source and basis of alleged imports of HSR under Chapter 39, Import figures based on so-called public sources, volume and value of imports from other countries, production volume by the Domestic Industry, production volume of other related products by the Domestic Industry and name and addresses of the manufacturing units". It is requested that the Hon'ble Designated Authority should compel the Domestic Industry to submit at least the above essential information on a non-confidential basis.
- (xiv) We had also requested the Designated Authority to kindly let us know if the Domestic Industry had in pursuance to the rule position and the instruction on the issue, provided reasons for keeping such information as mentioned above confidential. Unfortunately, we have not received any response in the matter. We would also like to mention that from the inspection of the public file, it appears that the Domestic Industry did not provide any such reason for keeping the basic information confidential. Therefore, it is respectfully submitted that the question of the Designated Authority taking any specific decision on the issue will not arise. The investigations in the case therefor need to be terminated on this ground alone.
- (xv) It may be mentioned that the petitioners claim to rely upon import data provided by M/s Polymers Plastics and Rubber Journal. The user industry has obtained a copy of the Polymers Plastic and Rubber Journal data for import during January to September 2000. The only import from Poland of HSR 1900 came in on 30th August, 2000 at a price of Rs.43.68 per kg., whereas the petitioners have showed imports from Poland at an export price of Rs.38.93 per kg.
- (xvi) In addition to this the import data impacts the apparent injury to the Domestic Industry, thus distorting the ability of the Designated Authority to ascertain whether there exists dumping or indeed injury in the present petition. By inflating volumes and reducing the export price the apparent injury is manifested more severely.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- i) That the entire proceedings were initiated on the basis of deficient application, viz. the petitioners furnishing of location of their plant with the written submission after completion of preliminary findings is itself proof of the deficient application. On this ground alone the investigation should have been dropped but the reason why the same was not dropped by the anti dumping Authority is best known to them.
- ii) We have not received any satisfactory reply either from the petitioner or from the Designated Authority with the regard to our submission about the authenticity of the claim that synthetic rubber is being cleared under Chapter 39.

e) M/s Sharma Associates, New Delhi have made the following submissions:-

- (i) In response to the information provided by the Authority, **M/s Sharma Associates** have stated that the import figures relied upon by the Domestic Industry have been provided rather than the data as sought by them and that the actual data has been concealed. Designated Authority has merely acted upon as post office and forwarded certain information purported to be enclosure to the written submission. The information is grossly inadequate, incomplete, and misleading. The investigation is continuing without any regard to the principle of natural justice. The Designated Authority should give us oral hearing to comment on the methodology and other issues relating to injury margin conclusion. No final decision may be given without hearing us in person.

f) M/s Banik Rubber Industries, Calcutta have made the following submissions:-

- (i) M/s Banik Rubber Industry have indicated that the application of the petitioner was incomplete and deficient and that the accuracy of the information given by the Domestic Industry was not verified and therefore the findings are not according to 1995 Rules and are absolutely bad, illegal and without jurisdiction.

2. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the various submissions regarding non-supply of certain non-confidential information by the petitioners to other interested parties for an effective defence. The Authority also notes the requests made by the various interested parties regarding the rules provision and the role of the Designated Authority in dealing with such a situation. The Authority keeping in view the Rule 7 of the Anti Dumping Rules, notes that the non-confidential petition/and information as provided by various interested parties has been placed in the public file and made available to

all interested parties as and when requested. This practice has been followed uniformly and consistently.

The Authority as such during the course of investigation taking note of the submissions made by various interested parties and their desire to have additional information for an effective defence, requested the interested parties for making available the additional information sought so that effective defence can be made by all concerned parties for a fair determination. In this regard, the Authority recalls that one of the interested parties, i.e. M/s Sharma Associates who had made request for information and for a personal hearing was provided opportunity not only to inspect the public file but also to make a presentation personally. However, while such an opportunity was granted, the interested party did not appear and offered a blanket criticism indicating the Designated Authority as post office.

The Authority notes that all available non-confidential information on different aspects as requested by certain parties was provided to the desiring parties and placed in public file. In response to the disclosure, M/s Sharma Associates has indicated that they were not in a position to make arguments in absence of the required data and hence did not come for a personal hearing. The Authority notes that as indicated above all essential ingredients as desired and to the extent they were non-confidential were made available to various interested parties. The confidential information on costing including the components like raw material for both Domestic Industry and the cooperating exporter from Poland could not be provided to M/s Sharma Associates as it was confidential data. Supply of information on ratio of raw material to the domestic selling price would also lead to revealing of confidential information on raw material. The personal hearing sought by this importer was on injury and NIP determination methodology on which arguments on methodology could have always been provided. The issue of availability of data on raw material prices should not have hampered the interested party to make such arguments. Further the Authority notes that NIP determination which is a vital parameter to quantify injury due to price suppression is made on the basis of confidential cost data of the Domestic Industry and which in any way is not available to interested parties in other such investigations also. The Authority therefore holds that due opportunity and all relevant information as per anti dumping rules was made available to this interested party for an effective defence.

The Authority therefore holds that this interested party has only referred generic criticism without providing and assisting the Authority with any meaningful data. The Authority also notes that due procedure has been followed as provided in the Anti Dumping Rules.

The information on imports data from CBEC which was also requested by certain interested parties was not available from CBEC. However updated DGCIS data which is compiled on the basis of customs data only has been released by DGCIS.

The Authority also notes that it has been indicated that the initiation was not done on the basis of reliable data as per Rule 5(3)(a). The Authority in this regard notes that the initiation took considerable time in fact more than seven months since Authority had to satisfy itself on the availability of prima facie evidence regarding dumping, injury and causal link and only after all parameters regarding initiation were satisfied, the Authority initiated the anti dumping investigation as per Rule 5(3)(a) as done consistently for all its cases.

As regards accuracy and authenticity of data filed by various interested parties including Domestic Industry, the Authority has adopted the data after due verification and satisfaction.

F.1 NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

a). **The following submissions have been made by M/s Apar Industries Ltd. and M/s Apcotex Lattices Ltd.:-**

- (i) The Authority had forwarded the questionnaire to the known exporters/producers from subject countries and Embassies of subject country/territory in India. However, only one exporter from Poland and one exporter from European Union has responded to the Designated Authority. The responses filed by the exporters are far from sufficient for the purpose of determination of dumping and dumping margin. The exporters have adopted a selective and pre-decisive approach and vital information has not been provided to the Designated Authority. While the exporter from Germany has even conceded not having supplied full information, the response filed by the Polish exporter deserves to be rejected, being incomplete and insufficient.
- (ii) M/s Firma Chemiczna Dwory SA, Poland has not filed complete information as prescribed under the questionnaire and that the response filed is incomplete, insufficient and unreliable. The non-confidential response filed by them does not tantamount to disclosure of information on non-confidential basis.
- (iii) From the response filed by the exporters M/s Firma Chemiczna Dwory SA it is evident that the exporter has selectively provided information and has pre-decided a number of issues without giving full information.
- (iv) The final findings in the matter of catalysts which were also upheld by Hon'ble Supreme Court are relevant.
- (v) As per the Initiation notification dated 20th Dec., 2000 stated that the product under consideration in the present investigation is *High*

Styrene Butadiene Copolymer, also called High Styrene Resin/Rubber (HSR) of all grades and forms.....” It is abundantly clear that all grades and forms of HSR are covered in the scope of the product. However, while replying to the questionnaire, the exporter has provided information only with regard to one grade of HSR, having decided that information in respect of home market is required to be provided only for the grade exported to India. In its response, the exporter has states as under:

*“Details in connection with the total quantities and net sales revenue from the **sales of KER 1904 ('the relevant product') to India**, the market (Poland) and other third countries during the previous years and the relevant period is set out in Appendix 3.”*

The exporter has withheld complete information with regard to other types/grades of HSR (**in fact the exporter has not even disclosed the fact that it has other grades of HSR**). The view taken by the exporter is unsupported by the Rules and the order of the Supreme Court and would prevent the Designated Authority from deciding the matter. For instance, the Designated Authority is now prevented from determining the propriety of information with regard to cost of production (selling, general, administrative expenses) and in assessing the level of reasonable profits.

As a result of the above, the exporter has succeeded in getting minuscule dumping margin at the stage of preliminary findings by not disclosing full information.

- (vi) Another major deficiency in the response filed by the exporter is that there are wide gaps between the information provided by the exporter and information sought by the Designated Authority in the questionnaire.
 - a) We have assessed the cost of production of the Polish exporter and find that the exporter could not have under any circumstances recovered its full cost of production.
 - b) The Polish exporter itself has admitted having made losses in sales to some of the customers as per the Preliminary Findings on Normal Value. It is our contention that all the transactions are below the full cost of HSR.

The exporter has further provided details of the customer-wise sales rather than of all the transactions. We strongly urge the Designated Authority to direct the exporter for the details of all the sales transactions. Customer wise sales can not be substitute for a transaction-wise sales. Even when sales to a customer were at a profit, it is quite possible that some of the transactions were at a profit and some at a loss for that customer, thus resulting in

average profitability for that customer. However, the Designated Authority has to ignore all loss making transactions while assessing the selling price in the home market. This is the consistent practice of the other investigating authorities also.

- c) It has been argued by the exporter that the loss making transactions can be ignored in accordance with Annexure I only when the Designated Authority has compared these sales with the cost of production at the time of sale. The order of the CEGAT in the matter of acrylic fibre against Thailand was cited in this connection. We wish to submit that:
1. The Designated Authority has, in the preliminary findings, found that **average selling price to a customer** was at a loss. The Designated Authority has not found that the transactions were at a loss. The question of comparison with the cost of production at the time of sale did not arise in the preliminary findings.
 2. While on the one hand the exporter has not provided transaction-wise sales in the home market, on the other hand, the exporter has argued about the comparison with cost of production at the time of sale.
 3. While the exporter has argued about comparison with the cost of production at the time of sale, the exporter has not considered it appropriate to provide such information (cost of production at the time of sale) to the Designated Authority. Thus, the exporter has urged upon the Designated Authority to consider cost of production at the time of sale without providing relevant information. Or alternatively, the exporter wish the Designated Authority to ignore compliance to Annexure I since the cost of production at the time of sale was not made available by the Designated Authority.
 4. The data provided by the exporter with regard to domestic and export sales is on different basis. While the exporter has provided transaction-wise details of exports made to India, the sales in the home market are customer-wise. Thus, the exporter has provided data on different basis, thwarting the efforts of the Designated Authority to ensure fair comparison.
- (d) In view of the foregoing, we submit that full and sufficient details have not been provided by the exporter. We request the Designated Authority to disregard the entire response filed by the exporter in view of deficient critical information. The exporter should not be given another opportunity to supplement the response or provide new information, as this would simply tantamount to bonus for selective co-operation. The situation cannot be resolved even by conducting spot investigations, as the purpose of spot investigations is not to compile the information. Spot verification

visits are not data compiling visits. The purpose of the spot investigations is to merely verify the information already provided by the exporter. When the exporter has not fully provided information, the question of its verification does not arise. We rely upon the Annex I to the WTO Agreement in this regard.

- (vii) As the exporter M/s Bayer International SA has not filed full information and has been admitted also by the exporter, there is no reason to grant another opportunity to the exporter to provide remaining information, nor any other investigating Authority would over provides repeated opportunity to an interested party. The preliminary determination in respect of this company is thus fully justified and is required to be confirmed.
- (viii) Also with regards to Bayer, we understood in the Hearing that they wish to submit their data to the Designated Authority at this stage. Bayer's counsel mentioned that their selling prices of HSR in EU and India did not differ much. This suggests that Bayer was also selling HSR in EU at a loss since the write-up of costs (as detailed in the above section pertaining to Dwory) is also applicable for Bayer. Hence, we request the Designated Authority to scrutinise the cost of production of HSR manufactured by Bayer also critically.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- i) While the disclosure is self-explanatory with regard to grossly incomplete, insufficient and misleading information filed by M/s Firma Chemiczna Dwory, it is found that the Designated Authority has still proposed to proceed further with the response filed by the exporter. The petitioners strongly object to admission of the response and the information of the exporter for determination of Normal Value. Such a kind consideration and treatment by the Designated Authority to the exporter would be a big bonus to the exporter. Further, this would encourage similar behaviour by the other exporters also. It would also be relevant to point out that in the matter of investigation relating to review of duty from Korea, the Domestic Industry had repeatedly pointed out towards inconsistencies in the information furnished by the exporter and yet the exporters information was admitted.
- ii) The petitioners had reportedly argued that the Polish exporter in particular and all exporters in general could not have recovered their cost of production, given the prices at which these parties had exported HSR to India and the prevailing raw material prices. It is indeed interesting to note that the exporter has vehemently objected to consideration of Normal Value based on estimates of cost of production and it shows the finding of the Designated Authority that majority of the sale of the exporter was at loss.

- iii) It is submitted that the Dumping Margin assessed in the disclosure statement for M/s Firma Chemiczna Dwory is inadequate. Further, there is sufficient ground for rejecting the entire information of the exporter. At the same time, we are not aware of what supplementary information has been filed by the exporter subsequent to our exposures with regard to the exporter in the public hearing and subsequent submissions. We request a complete set of information filed by the exporter after the visit by the officers.
- iv) It is submitted that Bayer International is a company outside European Union, is apparently a trader and an affiliate of the concerned producer. The response filed by the company is grossly inadequate. It is not clear whether the producer concerned had responded. Accordingly, it is submitted that Normal Value can only be determined in accordance with Rule 6(8).
- v) The argument made by Enichem with regard to low volume of exports made by them is untenable. If Enichem is not keen in responding, considering this as unimportant, the Authority is requested to confirm Dumping Margin in respect of this company in accordance with Rule 6(8).
- vi) As regards other non-cooperative exporters from the subject countries the methodology proposed by the Designated Authority be confirmed in the Final Findings.

b) **M/s Enichem Elastomeri S.r.l Italy have made the following submissions:-**

- (i) M/s Enichem Elastomeri S.r.l., Italy have indicated that they have exported 22 MT in the year 2000 and that negligible quantities cannot cause injury to the indigenous producer and therefore they strongly feel that imposing Anti Dumping Duty on HSR on supplies from Enichem Elastomeri. Italy has caused injustice not only to them but also to their valued customers in India

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- i) According to our database records of sales, we have been sold our HSR type, i.e HS65, only in 1999, during July, August and October months, for a total of approx 328 tons, you will find all details of these sales in the summary sheet, we have sent to your attention by separate cover.
- ii) Enichem export price for these sales in 1999 to India was 840 USD/mt, as per a.m. documentation; this price has been kept for the

whole July-October period. We are in position to show evidence of related invoices at later stage.

- iii) At the rate of exchange of the period, as per a.m. documentation, our selling price corresponded to a range of 1510-1591 Lire/Kg..
- iv) Enichem official price list on HS65 for Italian market, dated 15.6.99 (for 3rd quarter 1999) was 1420 Lire/kg. With reference to this price our Italian States Managers had a max. discount tolerance of 5%(i.e. down to 1349 Lire/kg) as per our internal procedure, to sell HS65 in Italy. We are in position to show evidence of related document (i.e. a.m. Price List) at a later stage. We have also supplied to others Asian countries at similar prices.
- v) Between June 1999 and October 1999 we sold in our domestic market, Italy, volumes of approx 50 tons/month to representative customers at prices between 1300 Lire/Kg (under Management approval) and 1480 Lire/Kg.. We are in position to show evidence of related invoices at later stage.
- vi) Based on comparison of a.m. prices (domestic vs. export prices to India) we do not see any reason to be involved in a dumping situation vs. Indian market; our selling prices in Italy were always below, or at least comparable with our export prices to India.
- vii) We did not sell any quantity during years 2000 and 2001.
- viii) In view of the above we felt that by imposing the Anti Dumping Duty on HSR supplies from Enichem Spa Italy, the Authority has caused injustice not only to us, but also to our valued customers in India.
- ix) We do agree that Italy is a member of European Union but a sweeping duty on all the countries of the Union is not fair to the country who is not indulging in dumping activity.
- x) Hence we request to exempt import of HSR from Anti Dumping Duty.
- xi) By withdrawing the Anti Dumping Duty on our exports and charging such duty on exports from countries who are indeed indulging in such malpractice, the Authority will do justice to those countries and the Indian buyers who are not indulging in such unfair practice.

c.) M/s Bayer International S.A., Switzerland have made the following submissions:-

M/s Bayer International SA., Switzerland have indicated that at the time of hearing it was pointed out that they were non-cooperative and that it was misconceived.

- (i) We had been subjected to the investigation to the same product in the earlier proceedings with respect to SBR and
- (ii) that all relevant documentation and data had already been submitted in those proceedings.
- (iii) Immediately, however, on the learned authority expressing its dissatisfaction with our response in the preliminary findings we have by our response April, 19, 2001 provided complete details as also the requisite exporters questionnaire.
- (iv) In view of the above we apologise for our misunderstanding and respectfully submit that we may not be treated as non-cooperative exporters. It was never our intention not to cooperate with this authority.
- (v) At the outset it was pointed out that the produce which market is under the name Krylene HS 260. This same product namely Krylene HS 260 was the relevant product in previous investigation. No other grade of SBR under investigation has been exported by us. In the current investigation the only grade of SBR under investigation is the same product namely Krylene HS 260.
- (vi) In the previous proceeding the Final Findings were arrived at which inter-alia found that the dumping margin for all grades of SBR exported from France was 28.2%. A further finding is recorded whereby it was found that the landed value of our product was significantly higher compared to the reasonable selling price of the domestic industry and therefore was not causing injury to the Domestic Industry.
- (vii) From the above, it is abundantly clear that this same product was in fact investigated, dumping margin was determined, but the export price did not cause injury to the domestic market.
- (viii) It was further pointed out by the Actual users and Trade Associations during the hearing that as per Rubber Board data demand amounted to the region of 30600 MT per annum. If the total exports made by us which amount to 437 MT (all invoices submitted) the proprata percentage for the 9 months period of investigation would amount to

less than 2% of the demand which is well below the requirements of Rule 14 of the Anti Dumping Rules. Further, even if the EU is to be considered as a block, we submit, that to the best of our knowledge, there is no other exporter making any significant exports to India and therefore even collectively EU imports would be below the prescribed percentage in the said Rule. We would also like to point out that the price of \$850 MT does not appear to be in line with this grade of SBR and may be related to other types of SBR.

- (ix) We may point out that at no stage have the petitioners production figures been disclosed or provided during the course of investigation and therefore it is impossible to ascertain the same in view of the petitioners facility being a multi product one. Further, no details with respect to the alleged price of \$850 PMT or the product upon which the price is based even provided to us. It is submitted that unless such figures are disclosed it is not possible for us to make any adequate or accurate submission in this regard to defend ourselves.
- (x) Further, the Dumping Margin determined by the Authority in the preliminary findings amounts to 103.3%. We are unable to counter the same view of the fact that we have no information as to what export price has been taken into consideration for this purpose. If the same is the export price mentioned by the petitioner viz. \$ 850 PMT, the same is ex-facie erroneous in view of the invoices provided by us.
- (xi) Without prejudice to our contention that the price in the domestic market is comparable to the export price as evidenced by the domestic price invoices provided to the Authority it is submitted that the same may be taken into consideration for arriving at the normal value and not the petitioners data.
- (xii) The Authority has discarded the price provided for the Domestic market. However, the basis for disregarding the same appears to be that no cost of production details have been provided and therefore, the transaction is not in the normal course of trade. It is respectfully submitted that the Authority has erroneously discarded the price provided for the Domestic Industry in the preliminary findings.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) We have been subjected to the investigation of the same product in the earlier proceedings with respect to SBR and absolutely all relevant documentation and data has been submitted by us.
- (ii) The findings at that time indicated that the export price by us did not cause any injury to the domestic market.

- (iii) We fail to understand why having exported insignificant quantities at price comparable to the domestic market and other international markets, the findings this time are different.
- (iv) We have always cooperated and supplied all data required by the Authority.

d) **M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland have made the following submissions:-**

- (i) The petitioners have argued that the submission made by the Polish exporter deserves to be rejected, being incomplete and insufficient. In this context, it is submitted that the petitioners have perhaps conveniently glossed over the specific provisions of the WTO Agreement (paras 5 & 6 of Annex II), which were read out during the course of the hearing. This is without prejudice to our contention that we had supplied all information as required in the Exporters' Questionnaire to the best of our understanding and ability. We reiterate our stand and offer all cooperation to the Designated Authority for any other further information, which may be needed under the Indian rules and the WTO provisions now or during the course of the verification visit. The specific provisions of the WTO Agreement (paras 5 & 6 of Annex II) are reproduced below:

“5. Even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability.

6. If evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefor, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period, due account being taken of the time-limits of the investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, the reasons for the rejection of such evidence or information should be given in any published determinations.”

- (ii) It is regretful that the decision of the Hon'ble Supreme Court (Haldor Topsoe case) has been cited entirely out of context. This judgement of the Hon'ble Supreme Court was in the context that the exporter in this particular case preferred not to disclose the details of the export price of the concerned catalysts to an appropriate third country even though the same was available with the respondent. Further, the reasons advanced by the respondent for not furnishing the information were not found worthy of acceptance by the Authority. The citation and the *ratio decidendi* of the Hon'ble Supreme court's decision has no relevance in this case as all information asked for by the Designated Authority has been furnished to the best of ability of the exporter and

the exporter is also willing to submit any further information which the Designated Authority may consider necessary for the findings in the case.

- (iii) On page 9 of the written submissions, we are surprised to see the conclusion reached by the petitioners with regard to the information to be supplied by the exporters. If a particular grade is not exported, where is the question of determining the dumping margin on that product. The assertion of the petitioners that the "Designated Authority is now prevented from determining the propriety of information with regard to cost of production", is without any logical basis. Such statements are made only to mislead and bias the Hon'ble Designated Authority, which we respectfully submit, should be ignored.
- (iv) The petitioners have stated that the exporter should not be given another opportunity as it would tantamount to bonus for selective cooperation. It has further been stated that the situation cannot be resolved even by conducting spot investigations, as the purpose of spot investigations is not to compile the information. Reliance is placed on Annex I to the WTO Agreement. In this connection, we wish to reproduce the relevant provision from Annex I of the Agreement:

the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided *or to obtain further details, . . .*"

The same Annex goes on to state that:

it should be standard practice prior to the visit to advise the firms concerned of the general nature of the information to be verified and of any further information which needs to be provided, though this should not preclude requests to be made on the spot for further details to be provided in the light of information obtained.

Annex II of the Agreement states as under:

- "5. Even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability.
- 6. If evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefore, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period, due account being taken of the time-limits of the investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, the reasons for the rejection of such evidence or information should be given in any published determinations."

- (v) Thus, it is clear that the WTO provisions prove beyond any doubt that the arguments of the petitioners with regard to the so-called deficiencies deserve to be ignored.
- (vi) The petitioners have rightly selected the international prices of major raw materials for the estimate but have fatally flawed the determination of the Normal Value in EU and Poland by assuming "All other costs" on the basis of expenses incurred by them in Para III of the non-confidential version of the petition. Thus, it is clear that even at the time of initiation the information available with the Designated Authority was conceptually and legally inadequate and an initiation could not have been initiated on that basis. We also respectfully submit that this defect at the time of initiation is incurable and cannot be rectified at any subsequent stage. We place reliance on the case Guatemala-Mexico cement case, which has been adequately cited in our written submissions, and not being reproduced for the sake of brevity. Other arguments taken at the time of the public hearing have not been addressed by the domestic industry.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) In response to our letter dated 26.11.2001 requesting for details of normal value, since we have not heard from the Directorate, we are offering our comments on other issues at this stage. It is reiterated that the Authority may kindly provide us with the details as required in our earlier letter.
- (ii) The detailed disclosure would also be in line with the principles of natural justice as well as the guidelines of the WTO.
- (iii) We are not in a position to effectively response to the disclosure statement and would like to state that while the disclosure narrates some of the arguments on issues of confidentiality, adequacy and accuracy of information at the time of initiation, non-availability of certain crucial information, the same has not been addressed in the disclosure statement..

e) M/s All India Federation of Rubber Footwear Manufactures and M/s Paragon have made the following submissions:-

- i) The Honourable Designated Authority in the preliminary finding has rejected certain transactions provided by the Polish Exporter on the ground that the sales to certain customers in the domestic market are

below the cost of production as claimed by the producer/exporter and are, therefore, not in the normal course of trade.

- ii) It is respectfully submitted that whether particular transactions are below cost of production are subject to a two part test as set out in Annexure I to the Anti Dumping Rules.
- iii) This aspect was also recently dealt with by the Hon'ble CEGAT in the matter of M/s Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. V/s Ministry of Finance, Designated Authority (2001(75) ECC 197 (Tri.)). The Honourable CEGAT stated:

"In view of the.....understanding of the provisions contained in Clause (2) of Annexure I, the da was clearly in error in rejecting all sales which were effected at prices below per unit cost of production for the period of investigation. Only those sales at prices below per unit cost of production at the relevant time should have been excluded as not having been effected in the ordinary course of trade. This should have been subject to the provisions contained in sub-clause (1) and (2). Even in apply this, it should have been examined whether such sales were within the reasonable period of not less than six months and whether such sales were in relation to substantial quantity of not less than 20% of the volume".

- iv) It is respectfully submitted that on the basis of the information provided by the exporter to the Honourable Designated Authority, this two parts test enumerated above must be carried out. We are hopeful that there would be no dumping margin if both the tests are applied in the case of exporter from Poland.
- v) Furthermore, the Honourable Designated Authority has disallowed certain adjustments for expenses incurred exclusively for domestic sale. It is respectfully submitted that the exporter from Poland has substantiated the adjustment with documents supplied on a confidential basis. Accordingly it is respectfully submitted that the Honourable Designated Authority give full and complete effect to the same.

In response to the disclosure, the following submissions have been made:-

- (i) M/s Banik Rubber Industries have stated that rejection of certain transactions carried by the Polish exporters on certain grounds need in-depth scrutiny with regard to cost of production as per anti

dumping rules before determining the dumping margin.' Two part test must be carried out to know the actual position of the adjustments for the domestic sales by the exporters should also be taken into account.

- (ii) M/s All India Rubber Industries Association and Small Scale Rubber Industries Association and M/s New India Works Pvt. Limited have also reiterated the above comments made by M/s Banik Rubber Industries.

EXAMINATION BY AUTHORITY:

2(a) M/S FIRMA CHEMICZNA DWORY SA, POLAND

(i) NORMAL VALUE

The Authority notes the various submissions made by the interested parties regarding the computation of the normal value for M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland. The Authority notes that in response to the disclosure statement, wherein a confidential disclosure on the evaluation of Normal Value and Dumping Margin was provided to the exporter indicating the methodology and the basis of various cost elements, the exporter had indicated that disclosure is non-speaking and desired that detailed computation and cost components be provided to them. The Authority keeping in view the request of the exporter granted a personal interaction with the Directorate. The representative of the exporter interacted with the Directorate, wherein it was reiterated that detailed methodology, and basis of computation of cost of production has already been given in the disclosure. The Authority in this regard holds that as per the anti dumping rules and standard practice of the Directorate, the detailed methodology and basis of computation of normal value has been indicated in the confidential disclosure which is in fact based on the documents provided to the verification team by the exporter themselves and which have been clearly indicated in the confidential disclosure statement issued to the exporter.

The Authority notes that the questionnaire response filed by the exporter did not reconcile with the original records of the exporter and therefore the data as provided by M/s Firma Chemiczna Dwory S.A. to the verification team at the time of on site verification has been referenced and on the basis of this data provided to the verification team, the cost of production of the subject goods in the period of investigation (KER 1904 grade) comes to ****\$/MT. This cost of production is above the weighted average domestic selling prices in the period of investigation for the grade KER 1904. The Authority has therefore disregarded the domestic selling prices of the subject goods in the period of investigation as these are not in the ordinary course of trade as per Annexure 1 to the Anti Dumping Rules. The Authority also notes that during the Period of investigation, the domestic sales transactions have not been able to recover the costs as indicated in Annexure 1 to the Anti Dumping Rules and therefore the recovery test as argued by the exporter is not relevant. The Authority has therefore

constructed the Normal Value on the basis of cost of production details as made available to the verification team for the subject goods in the period of investigation as per the Anti Dumping Rules.

The weighted average normal value for the subject goods in the period of investigation comes to ****\$/MT.

(ii) EXPORT PRICE

As regards the export price, the Authority notes that the exporter has provided the weighted average CIF price to India for the subject goods in the period of investigation. The Authority also notes that the exporter has claimed adjustments on inland freight, ocean freight, packing, commission and VAT to an extent of ***, ***, ***, *** and ****\$/MT.. The Authority has considered these adjustments on the basis of data as verified by the verification team. The total value of transportation cost which is inclusive of ocean freight, ocean insurance and other port expenses has been considered as adjustment as provided to the verification team. As regards the adjustments on VAT, it is noted that the exporter has claimed this adjustment to an extent of ****\$/MT. During the verification, the verification team was informed by the exporter that the VAT has been claimed only on an actual basis as paid by them on the various inputs which have gone into the export production. The Authority has therefore allowed the VAT refund adjustment to an extent of ****\$/MT.,

The weighted average Ex-Factory Export Price comes to ****\$/MT.

(b) OTHER NON-COOPERATIVE EXPORTERS/PRODUCERS FROM POLAND

(i) NORMAL VALUE

As regards the non-cooperative exporters/producers other than M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland, the Authority has constructed the normal value of the subject goods in the period of investigation on the basis of the cost of production data for subject goods in Poland.

The weighted average normal value for the non-cooperative exporters/producers is considered at ****\$/MT.

(ii) EXPORT PRICE

As regards the export price, the Authority has considered the least export selling price of subject goods from Poland to India in the POI with adjustments as the petitioners data and as co-related by the data given by M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland. These adjustments are ocean freight, inland freight, port expenses, commission and ocean insurance.

The weighted average Ex-factory Export Price is considered at ****\$/MT,

(c) TERRITORY OF EUROPEAN UNION (EU)

M/s Bayer International S.A., Switzerland & M/s Bayer International, France (M/s Bayer)

(i) NORMAL VALUE

The Authority notes the various submissions made by the Domestic Industry and M/s Bayer International S.A., Switzerland regarding the evaluation of the dumping margin. The Authority notes that it has been admitted by M/s Bayer that they did not provide the complete information before the preliminary findings. The Authority also notes that the subsequent to the preliminary findings M/s Bayer has provided certain additional information. However, the Authority notes that the same was found to be grossly deficient. The Authority had requested M/s Bayer to provide the cost of production and information as per the prescribed questionnaire. No such information was made available by M/s Bayer. The Authority in confidential disclosure issued to the exporter indicated the non-availability of cost of production of subject goods in the Period of Investigation and indicated inability to hold the domestic sales made by them in ordinary course of trade. Basis of constructing the normal value for subject goods in the Period of Investigation was also indicated. In response to the disclosure, the exporter has indicated that in the earlier investigation of SBR they had provided all data. However no cost of production in the current Period of Investigation was made available.

In view of the non-availability of specific cost of production data for the POI, the Authority notes that the export prices to the third countries other than India as indicated by M/s Bayer cannot be referenced for Normal Value and also the domestic prices as indicated by M/s Bayer cannot be held in the ordinary course of trade. The Authority also notes that even on the basis of the domestic selling prices and ex-factory export price information as provided by M/s Bayer, dumping of subject goods in POI is evidenced. The Authority in this regard notes that as per Anti Dumping Rules, the Authority has no option but to construct the normal value for M/s Bayer as per Rule 6(8) on the basis of the data on various cost elements viz. raw materials etc. at international prices and other duly normated cost elements as available from the petitioners data .

The weighted average constructed normal value for M/s Bayer International S.A., Switzerland, the exporter and M/s Bayer International, France, the producer comes to ****\$/MT.

(ii) EXPORT PRICE

As regards the export price, the Authority has considered the weighted average export price for subject goods (KS 260) in the period of investigation as indicated by the exporter. The Authority has allowed adjustments on inland freight, overseas freight, overseas insurance, handling, sales tax and credit on the basis of the data as provided by the exporter. The weighted average ex-factory export price for the subject goods in the period of investigation is considered at ****\$/MT.

(d) M/s Enichem Elastomeri S.r.l Italy (M/s Enichem)

The Authority notes the submissions made by M/s Enichem, Italy regarding low volume of exports made by them and the submissions made subsequent to the disclosure. Since the investigation is for European Union as a territory and that the total imports from EU are above the de-minimis, as per rules, M/s Enichem cannot be excluded from the scope of the investigation.

The Authority notes that M/s Enichem has reported that no quantity of subject goods has been sold by them during the year 2000 and 2001. The Authority therefore notes that in view of no exports being made during the Period of Investigation, the exporter would be attracted under the Rule 22 of the Anti Dumping Rules. The exporter may make a request under Rule 22, however, pending the Rule 22 investigation, the exporter shall be treated along with other exporters/producers category other than M/s Bayer International as indicated below.

(e) OTHER NON-COOPERATIVE EXPORTERS OTHER THAN M/S BAYER INTERNATIONAL S.A., SWITZERLAND**(i) NORMAL VALUE**

The Authority has adopted the same methodology for the normal value as for M/s Bayer for exporters/producers who have not responded i.e. the normal value has been constructed as per Rule 6(8) on the basis of the data on various cost elements viz. raw materials etc. at international prices and other duly normated cost elements as available from the petitioners data.

The weighted average normal value is considered at ****\$/MT.

(ii) EXPORT PRICE

As regards the export price the Authority has considered the least export price from European Union in the POI with appropriate adjustments as per data provided by M/s Bayer including commission to the agent in India.

The weighted average Ex-factory Export Price is considered at ****\$/MT..

5. DUMPING-COMPARISON OF NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

The rules relating to comparison provides as follows:

“While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability.”

The Authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price in POI for evaluation of dumping margin.

The dumping margin for the producers/exporters of the subject goods in the subject countries in the POI are as under:--

Exporters/producers	Normal value (\$/MT)	Export price (\$/MT)	Dumping margin(%)
<u>Territory of European Union</u>			
M/s Bayer International S.A. Switzerland and M/s Bayer International, France	*****	*****	87.2
All other exporters/producers of Territory of European Union	****	****	107.48
<u>Poland</u>			
M/s Firma Chemiczna Dwory S.A.	****	****	26.7
All other exporters/producers of Poland	****	****	55.68

The above dumping margins are above the de-minimus limits

G.1 INJURY AND CAUSAL LINK

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it

is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II(iv) of the rules supra.

The following submissions have been made by various interested parties

a) **M/s Apar Industries Limited and M/s Apcotex Lattices Limited have made the following submissions:-**

- (i) The demand of HSR in the country in 1999-2000 as assessed by various interested parties in the region of 30601 MT is wrong as per the information received from Rubber Board. It has been indicated that the figure of 30601 MT includes all types of the synthetic rubber viz. NBR, EVA etc. Based on our assessment the demand of HSR in the country is in the region of 17000 MT.
- (ii) Though the preliminary findings already confirms that the exporters from subject country/territory are dumping HSR in the Indian market, it is submitted that there is injury to the domestic industry, there is threat of material injury to the domestic industry due to dumping of the subject goods in the Indian market. We submit that the domestic industry has earlier suffered material injury as a result of dumping from a number of countries which are now attracting anti-dumping duties. So severe was the extent of damage to the domestic industry that one of the producers, M/s. Synthetics & Chemicals was even forced to suspend its production. The petitioners note with amusement the interest being shown by the consumers now in the goods produced by Synthetics & Chemicals, notwithstanding their stiff opposition and argument to imposition of anti-dumping duty on SBR earlier consequent to the petition filed by that company. Furthermore, in view of the imposition of anti-dumping duty on imports of SBR from some of the countries, the injury to the domestic industry is required to be seen in the context of existing duties and impact thereof.
- (iii) During the course of the oral hearing, it has been argued by the exporter/importer that in the anti dumping investigation of NBR, it has been stated by the Domestic Industry that NBR is the cause of

its poor profitability while now the Domestic Industry is claiming that HSR is the cause of its poor profitability.

- (iv) We submit that the Designated Authority has conducted a number of investigations on the basis of the verified data/information provided by the company. Different investigations pertain to different investigation period and it would not be appropriate to assume that the financial performance of the company in different period remained the same. The information furnished by the company in various investigations is true, correct and as per books of accounts. We are prepared to give any further information which the Designated Authority may require in this connection.
- (v) The material injury and threat of material injury suffered by the domestic industry as a result of dumped imports is evident from following parameters:
- The injury to the domestic industry is required to be cumulatively assessed.
 - Imports have increased significantly in absolute terms from the two countries. The actual volume of imports from Poland have increased to a level of about 1000 MT from no imports till 1999.
 - Imports from the subject countries have increased in relation to demand of the product in India.
 - Imports from the subject countries have increased in relation to production in India.
 - Market share of domestic industry in demand of the product in India declined.
 - Significant rise in dumped imports from subject countries in a very short period which indicates the likelihood of substantially increased importation in future,
 - Substantial capacity available with the exporters in the subject countries.
 - Sufficient freely disposable capacities available in the subject country/territory. It is understood that the Polish company has reduced its production and sales of HSR in the last few years. Further, the company is having significant surplus capacity.
 - The existing capacities in the subject country/territory is much more than demand of HSR in the subject country/territory.
 - The export price is significantly below the fair selling price of the domestic industry, causing severe price suppression/depression in the Indian market.
 - The landed price of Imports is significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. The price undercutting is forcing the domestic industry to reduce its price levels and the domestic industry is finding difficult to hold on to their prices.

- Losses of the domestic industry have piled up. The industry has been forced to sell at prices below the optimum cost of production and reasonable return on investments
- Operating margins of the domestic industry have been declining substantially as a result of severe price undercutting.
- Stock with the domestic industry have piled up.
- Capacity utilisation of the industry has remained sub-optimal. The industry has not been able to utilise its plant optimally in spite of imposition of antidumping duties on other countries.
- Employees with the domestic industry are demoralised. The company is finding it difficult to retain its talented employees as a result of continued dumping of the product in the market.
- The domestic industry is unable to grow as a result of continued dumping of this product in the Indian market. This is in spite of rising demand of the product.
- Due to severe dumping and injury to the domestic industry earlier from other countries and now from subject country/territory, one manufacturer have already applied to BIFR.

It may thus be seen that all the above parameters individually and collectively establish that the domestic industry has been materially injured and there is severe threat of material injury to the domestic industry as a result of dumped imports. We submit that the Anti Dumping Duty is required to be imposed now, otherwise, it would not be possible for the domestic industry to sustain its existence.

In response to the Disclosure, the following submission has been made:-

We rely upon our arguments advanced earlier, which are not being repeated hereunder for sake of brevity. The various arguments brought by us on the issues of injury and causal link clearly establish that the Domestic Industry has suffered material injury.

b). M/s Sharma Associates, New Delhi have made the following submissions:-

- (i) The notification does not give details of injury analysis in the absence of which we are unable to understand in the absence of which we are unable to understand as to how the injury is caused.
- (ii) The information on production, figures of Domestic Industry, details of imports from CBEC, ratio of raw-material, cost versus selling prices from the domestic producers and the exporters may be made available.

c) M/s Banik Rubber, Calcutta have made the following submissions:-

- (i) There is a gap between demand and supply of HSR and that the quality of HSR produced by Domestic Industry is not upto the

standard for manufacturing the rubber products at the time of globalization in the world market. Therefore, the local industries have no other alternative but to depend on the better quality of HSR from imported sources. The question of imposition of anti dumping duty therefore does not arise.

d) M/s All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers and M/s Paragon have made the following submissions:

- (i) It may also be pointed out that the preliminary findings in this particular case do not reveal the basic information relied upon, as envisaged under Rule 12 or under the WTO Agreement on Anti-dumping. This is a significant departure from the long established practice of giving the details of injury analysis even in the preliminary findings, as was done also in the earlier cases of synthetic rubber. You would kindly appreciate that this severely handicaps the domestic user industry from offering any meaningful comments.
- (ii) At the outset it must be submitted that it is incumbent upon the Honourable Designated Authority to consider all the aspects of injury as enumerated in Annexure II (iv).
- (iii) In fact the WTO Panel in case of Bed Linen, in which India was a party, considered this aspect.
- (iv) This provision is squarely incorporated in the Indian Anti-dumping Rules specifically. Annexure II (iv) clearly states that "the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concern shall include an evaluation of all relevant economic factor and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output market shares, productivity, returns on investments or utilization of capacity : factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping : actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
- (v) It is an admitted fact the Petitioners are a multi-product companies manufacturing several types of synthetic rubbers including HSR (SBR 1900). It is to be noted that it is an admitted fact that the Petitioners do not manufacture 1500 or 1700 series of SBR.
- (vi) Further, it is also note-worthy that M/s. Gujarat Apar / Apar have filed several anti-dumping cases on other forms of synthetic rubber, namely NBR. Admittedly, the plants of M/s. Apar can be used interchangeably to produce different types of synthetic rubbers.

- (vii) The first case was filed on or about October, 1994 against Japan.
- i. The second case again concerning NBR was filed against Korea on or about March, 1995.
 - ii. A third case was filed against Taiwan on or about January 1999.

- (viii) In NBR 1 (period of investigation 1.4.1993 to 31.3.1994) the Honourable Designated Authority noted that the Petitioners "had to resort to production of non-NBR products (which otherwise does not require such plants and technology as are available with the Petitioners +for producing NBR) . . ." It is noteworthy that until 1.4.94 SBR plant belonged to M/s Apar Limited (a Private Limited Company) On 1.4.94, M/s Apar Limited was transferred to M/s. Gujarat Apar.

In NBR II the investigation period was from 1st October 1994 to 31st March, 1995. By this time the SBR capacity has been amalgamated. In this case also the authority notes that the petitioners had been forced to produced non-NBR items which otherwise does not require such plant and machinery as are available with the petitioners. The authorities went on to note that even though the petitioners had reported profits in its published annual accounts, the same is because of sale of non-NBR items.

- (ix) NBR III case which covered investigation period from 1st April, 1998 to 31st December, 1998. For the third time inspite of record profits and capacity utilisation the petitioners once again claimed injury on the basis that the profits and high capacity utilization in the synthetic rubber business was on account of non-NBR products.

- (x) Not surprisingly in the present case once again M/s Apar have had record capacity utilisation and production with an installed capacity of 11600 MT; in 1999-2000 M/s Apar had produced 12203 MT of synthetic rubber.

- (xi) In NBR II, M/s Gujarat Apar/Apar also identified that their polymer capacity was 6250 MT out of a total installed capacity for synthetic rubber of 11600 MT. Thus, it is surprising to note that at the public hearing a Director from M/s Apar publicly stated synthetic rubber including HSR(SBR1900). It is to be noted that it is an admitted fact that the petitioners do not manufacture 1500 or 1700 series of SBR. It is submitted that through the abuse of the confidentiality procedure M/s. Gujarat Apar / Apar have been repeatedly seeking the imposition of anti-dumping duty on all the products they manufacture. If the Petition is for NBR, record production on profits is attributed to other forms of synthetic

rubber. In this instant case the roles have been reversed and the injury now is being caused to rubbers other than NBR, i.e. HSR.

- (xii) It is evident that the proof of injury to the domestic industry was wholly inadequate and each and every parameter showed an improvement in performance over the previous.
- (xiii) Within the factual matrix of this particular case, the Petitioners submitted inadequate data on import volume, import prices, etc. A few unsubstantiated claims on injury and on threat of injury were made. Clearly and prima-facie, these are wholly inadequate and cannot be considered as 'sufficient' for the purpose of whether initiation or for further investigations. Further, we respectfully submit that it was incumbent upon the Honourable Designated Authority to examine the accuracy and the adequacy of the data filed by the Petitioners prior to initiating the investigation, as per Rule 5 (3) of the Anti-dumping rules. Due to these incurable defects in the petition by the domestic industry and the Designated Authority not examining the adequacy and accuracy of the submissions made by the domestic industry, we most respectfully submit that the investigations need to be terminated forthwith.

In response to the Disclosure, M/s All India Rubber Footwear Manufacturers have made the following submission:-

- i) The total proceedings in the subject case are shrouded with evasiveness. The Domestic Industry has failed to give a clear cut reply to our queries made from time to time. No satisfactory reply why HSR was being cleared under Chapter 39 is given.
- ii) The contention of the petitioners that HSR can be cleared both under Chapters 39 and 40 is highly misleading and cannot be accepted.
- iii) When the import data from the Government sources, i.e. DGCI&S was available why the Domestic Industry chose to rely upon data from the secondary sources.
- iv) In the petition the petitioners have indicated that total production of HSR equals to 4996+2759 tons whereas in their rejoinder they had indicated that the established demand was of the order of 18000 to 20000 M. tons pa.. The capacity of both the domestic producers, however, taken together, is not more than 10000 to 12000 M. tons pa..
- v) We deny the contention of the petitioners that the imports have increased. On the other hand imports have actually gone down to 7383 M. tons in 1999-2000 from 11083 M. tons in 1998-99.

e) **M/s Firma Chemiczna Dwory S.A., Poland have made the following submissions:-**

- (i) The petitioners have merely reproduced the contentions made by them in the petition. In this connection, it may be pointed out that the details of the so-called injury have to be mentioned in the preliminary findings after taking into account all the individual economic and financial parameters. Further, the requirements for 'threat of injury' have not been met with in the instant case. There is nothing more than mere assertion that there is threat of injury from the alleged dumped imports just to sensationalize the issue. It is also submitted that the arguments made by the exporter/importers and users during the oral hearing as well as in the written submissions stand un rebutted by the petitioners.
- (ii) We also urge the Hon'ble Designated Authority to kindly follow the rule of the Bed Linen case and the position taken by India therein.
- (iii) We also request the Hon'ble Designated Authority to kindly take into account the specific production capacities of the petitioners in their different plants for various types of rubber. Our request for the capacities of producing different synthetic by M/s Apar has not been paid attention to by the domestic industry. We are covering this aspect separately in the section relating to confidentiality and adequacy & accuracy of information.

f) **M/s Small Scale Rubber Industries of India, New India Rubber Works (P) Ltd., M/s Banik Rubber Industries and All India Industries Association have made the following submissions:-**

- (i) There is no injury to the domestic producers. The domestic producers have not made any losses, and any pile up of stocks is on account of poor quality of their product. Domestic Industry have increased their capacity and also their selling prices

In response to the disclosure, the following submissions have been made by New India Rubber Works (P) Ltd. and M/s Banik Rubber Industries:-.

- i) There is no injury to the Domestic Industry if a proper and detailed investigation is carried out particularly after considering the fluctuation in the cost of input of the raw materials consumed by the Domestic Industry. Here it may again be referred that one of the Domestic Industry, M/s Apar Industries Ltd. has made a huge profit due to less input cost (please refer the Economic Times, Kolkata dt. 7.11.2001).
- ii) The consuming industry must not be made to suffer due to incapability of the Domestic Industry for non-economic sale of production by using outdated technology by the Domestic Industry.

Any increase in cost by the Domestic Industry due to their in-efficiency should be ignored and must not be taken into account while calculating their cost of production. The Authority must not allow itself to be used as a profit generating tool by one or two Domestic Industry employing total workmen within 1000 against thousands of small consuming units employing lakhs of workmen. This is obviously not permissible in a developing country like ours which is always fighting against unemployment, poverty and other social problems. Here we also take the opportunity to respectfully submit that any improper decision affecting the Rubber consuming industry in the country shall have also an indirect impact on the condition of natural rubber growers of the country for which the Government always prefer to look for their interest.

2. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority after considering the above submissions, the data provided by the Domestic Industry and the imports data observes the following:-

- (i) The imports of subject goods from the countries other than the subject countries as per the DGCI&S data is 3487 MT and as per secondary source Polymers Plastics Rubber (PPR) Trade Journal is 4039 MT in POI. The maximum imports from non-subject countries by considering these two sources comes to 5073 MT (Chapter 40 imports of DGCIS and Chapter 39 imports of PPR). On the basis of this data, the Authority notes that the imports from the subject countries are above the de-minimis level.
- (ii) The production of the Domestic Industry has increased from 5490 MT in 1997-98 to 6532 MT in 1998-99, to 9224 MT in 1999-2000 and further to 7627 MT in POI (annualised 10169 MT).
- (iii) The capacity utilisation has decreased from 72.73% in 1997-98 to 42.14% in 1998-99, to 59.5% in 1999-2000 and has decreased to 57.13 % in POI.
- (iv) The domestic sales of the Domestic Industry has increased from 6109 MT in 1997-98 to 7617 MT in 1998-99 to 8960 MT in 1999-2000 and 8352 MT in POI (annualised 11136 MT).
- (v) The imports in absolute terms from Poland have increased from 0 MT in 1998-99 to 1160 MT in POI (annualised 1546 MT) and that from territory of EU from 1152 MT to 1250 MT (annualised 1667 MT) during the same period. In terms of market share, the imports from Poland have increased from 0% in 1998-99 to 7.3% in POI, whereas for territory of EU it has increased from 6.16% to 7.9% for the same period.

As proportion of total imports, the imports from Poland have increased from 0% in 1998-99 to 15.5% in POI while for territory of EU the share has increased from 10.4% to 16.7% for the same period. The imports data is referenced from DGCIS and correlated appropriately with PPR data and exporters response to the extent it is feasible.

- (vi) The market share of the Domestic Industry has increased from 40.7% in 1998-99 to 55.87% in 1999-2000 and has been 52.74% in POI.
- (vii) The profitability of Domestic Industry has declined significantly in POI as compared to 1997-98 and 1998-99.
- (viii) Though the production, domestic sales, capacity utilisation and selling prices of the subject goods of Domestic Industry have increased in POI as compared to 1998-99 and 1999-2000, the net sales realisation of the Domestic Industry has been suppressed on account of the low landed values of the dumped imports from the subject countries and has been significantly lower than the non-injurious price thereby leading to financial losses.

2. The Authority also notes the submissions regarding the injury analysis for the Domestic Industry made by various interested parties on the issue of capacity and injury analysis. In this regard, the Authority holds that non-injurious price (NIP) has been evaluated for the Domestic Industry by bench-marking the best consumption norms and normating the various cost components and by considering the dedicated capacity of the subject goods available with the Domestic Industry. In this regard therefore the injury to the Domestic Industry on account of price suppression due to dumped imports has been evaluated with reference to the cost of production in POI of the subject goods only.

3. The Authority notes the various arguments pertaining to demand of HSR in the country. The Authority on the basis of the import data available from DGCIS and from Polymers Plastics Trade Journal Intelligence (PPR) for the period of investigation evaluates the demand of HSR on the basis of the domestic sales and imports made as 18000 MT approximately. The Authority notes that if the data of imports under Chapter 39 of PPR and data of imports of Chapter 40 by DGCIS pertaining to the subject goods is considered, the best demand in the country can be considered of an order of 21000 MT approximately. On the basis of this demand and on the basis of the total available capacity, the Authority notes that there is a demand-supply gap on the basis of the actual production done by the Domestic Industry. The available capacity indicates that this demand-supply gap can be reduced if the domestic industry attains a higher capacity. On the basis of the previous years imports data as available from DGCIS and domestic sales of the Domestic Industry, the Authority holds that the demand of the subject goods is rising and therefore has not been a factor responsible for injury to the Domestic Industry. Also on the basis of the submissions made

by various interested parties, the Authority notes that the demand has not been a constraining factor.

The above economic factors collectively and cumulatively indicate that the dumped imports have kept the domestic prices depressed in the Indian market thereby causing material injury to the Domestic Industry by way of depressed Net Sales Realisation below the Non-Injurious Price thus leading to financial losses.

H.1 INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

The following submissions have been made by various interested parties:-

a) **M/s India Federation of Rubber Footwear Manufactures have made the following submissions:-**

- (i) The Domestic industry is taking undue advantage of the anti dumping system and attempt is being made by the vested interests in the country so that they can increase the price of their products.
- (ii) It is respectfully submitted that Public Interest is an aspect which the Honourable Designated Authority must consider prior to the imposition of Anti-Dumping Duty.
- (iii) It is further submitted that it is wholly simplistic to assume that any public interest view would essentially condone dumping, which is only beneficial in the short term, thus Anti Dumping Duties must be imposed, irrespective of the consequences on the user Industry.
- (iv) In fact the Anti Dumping Rules themselves require that the Honourable Designated Authority take into account the interest of the consuming industry in particular the Rule 6(5).
- (v) Clearly, the consumer interest is not to be discarded.
- (vi) In the factual matrix of the particular case, the Domestic Industry can admittedly not meet the domestic demand. Further, the user industry has confirmed that the quality of the domestic product is so poor that it impacts the brand equity of their slippers.
- (vii) Further, the end product is rubber slippers consumed by the common citizen of India. By imposing unduly high Anti-Dumping Duties the Honourable Designated Authority may consider the eventual impact on the consuming public.

In response to the Disclosure, the following submissions have been made:-

- iii) That the sole purpose of the petitioners is to increase the price of HSR on one pretext or the other. The Domestic Industry has increased their prices on four occasions within the last two years from Rs.60/- per kg. to Rs.88/- per kg..
 - iv) Apar Industries Ltd. and Apcotex are not providing HSR produced by them at fair prices and very often they jack up the prices on one pretext or the other hurting the viability of the local rubber industry. Their qualities are also not upto the mark. Their supply position is equally bad.
- b) M/s Banik Rubber Industries, Calcutta have made the following submissions:-
- (i) It has also been indicated that M/s Banik Rubber industries that the anti dumping duty has been imposed without taking into account the concerns of the user industry who employ four lakh workers which is not only bad in law but also without jurisdiction.
 - (ii) It has also been indicated that imposition of anti dumping duty on HSR in India has resulted in opportunity for the products from Nepal, Bangladesh, Korea and Thailand who are grabbing Indian market.
 - (iii) M/s Banik Rubber Industry have indicated that the manufactures of rubber are taking advantage of anti dumping duties and have revised their prices on various grounds over the last three years. The goods supplied by the Domestic Industry also do not meet the quality and standard required. M/s Small Scale Rubber Industries Association and New India Works Pvt. Ltd. have also supported the above submissions.

2. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the submissions made by the user industry on the likely impact of the anti dumping duty on the footwear manufactures. The Authority also notes that it has been indicated that the anti dumping duty will have an adverse effect on the employment in the small scale units. The Authority also notes that the submissions have been made regarding problems related to quality and standards of the goods supplied by the Domestic Industry and also regarding the mis-match in the demand-supply situation in the country. The Authority notes that various interested parties have also argued that subsequent to the levy of anti dumping duty, the Domestic Industry has raised the prices of the subject goods. It has also been submitted that the levy of anti dumping duty would lead to import of the finished products which the user industry is manufacturing and that the levy

of anti dumping duty which is to protect only two units is against the spirit of globalisation and WTO.

The Authority noting the above submissions made by various user industry holds that the purpose of anti dumping duty in general only to redress the injury which has been caused to the Domestic Industry due to unfair practice of dumping and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market which is in the general interest of the country.

The Authority recognises that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products which are manufactured with the usage of the subject goods and therefore might have some influence on relative competitiveness and price levels of this products. However, the fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice of the subject goods to the user industry and the consumers. Imposition of anti dumping measures would also not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

Regarding the mis-match in demand and supply, the Authority holds that consequent to the anti dumping measures, the imports of the subject goods from the subject countries would only get regulated at a fair price and in no way these measures are were intended to restrict imports from the subject countries. As regards the quality and standard of the subject goods as indicated by the user industry, the Authority reiterates as indicated in the foregoing para that these claims are unsubstantiated and have therefore not been considered. Also the Domestic Industry has been supplying these subject goods to the user industry in past and during the POI. Since the purpose of anti dumping duty is only to redress the injury caused due to the unfair practice of dumping the Authority keeping in view the interests of the user industry has recommended the anti dumping duty on the basis of lesser duty rule.

I. **LANDED VALUE**

The landed value has been determined for the subject goods after adding on weighted average CIF export price, the applicable level of custom duties (except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A) and one percent towards landing charges.

J CONCLUSIONS:**It is seen, after considering the foregoing that:**

- (a) The subject goods in all forms originating in or exported from the subject countries have been exported to India below its normal value.
- (b) The domestic industry has suffered material injury by way of depressed Net Sales Realization (NSR) on account of price suppression caused by low landed prices of the dumped subject goods from the subject countries leading to financial losses.
- (c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries. The authority recommends anti-dumping duty on imports of all forms/grades of subject goods falling under Chapter 40 and Chapter 39 originating in or exported from the subject countries as also indicated in sub-para (d) below.
- (d) It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less so as to remove the injury caused to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that definitive anti dumping duties as set out below be imposed, by the Central Government on all forms and grades of subject goods originating in or exported from Territory of European Union and Poland under Chapter 40, Customs Sub-Heading 4002.19 (ITC Classification 4002.1902) and Chapter 39, Custom Sub-Heading 3903.90 (ITC Classification 3903.9000) of the Customs Tariff. However the goods specifically indicated in foregoing para C(2) as being excluded do not attract the anti dumping duty.

Sl. No	Name of the exporter/producer	Product	Amount of Duty (US\$/MT)
1.	Poland		
	M/s Firma Chemiczna Dwory SA	All grades including KER 1904, 1909, 9000 of High Styrene Resin/Rubber(HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch/High Styrene reinforcement Polymer, excluding Polystyrene, Thermoplastic elastomer, Acrylonitrile-Butadiene Styrene copolymers and Styrene acrylonitrile copolymers and SBR 1500 and 1700 Series.	248.14
	All other exporters/producers	All grades including KER 1904, 1909, 9000 of High Styrene Resin/Rubber(HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch/High Styrene re-inforcement Polymer Excluding Polystyrene, Thermoplastic elastomer, Acrylonitrile-Butadiene Styrene copolymers and Styrene acrylonitrile copolymers and SBR 1500 and 1700 Series.	421.05
2.	Territory of EU		
	N/s Bayer International SA, Switzerland and M/s Bayer International, France.	All grades including Krylene HS 260 of High Styrene Resin/Rubber(HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch/High Styrene re-inforcement Polymer excluding Polystyrene, Thermoplastic elastomer, Acrylonitrile-Butadiene Styrene copolymers and Styrene acrylonitrile copolymers and SBR 1500 and 1700 Series.	359.70
	All other exporters/producers	All grades including Krylene HS 260 of High Styrene Resin/Rubber(HSR) covering SBR 1900 series referencing to High Styrene Resin Latex Master Batch/High Styrene re-inforcement Polymer excluding Polystyrene, Thermoplastic elastomer, Acrylonitrile-Butadiene Styrene copolymers and Styrene acrylonitrile copolymers and SBR 1500 and 1700 Series.	430.08

- (e) Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 13.3.2001
- (g) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority & Addl. Secy.